सुविचार
जीवन उनका नहीं युधिष्ठिर, जो उससे डरते हैं। वह उनका, जो चरण रोप निर्भय होकर लड़ते हैं।
–रामधारी सिंह 'दिनकर'

Daily
THE PHOTON NEWS
सच के हक में...
द फोटोन न्यूज Published from Ranchi

Kiara Advani In NYC Ahead... 12

Ranchi ● Wednesday, 07 May 2025 ● Year : 03 ● Issue : 111 ● Ranchi Edition ● Page : 12 ● Price : ₹3 ● www.thephotonnews.com
E-Paper : epaper.thephotonnews.com

भारत का एक्शन : पाक के नौ आतंकी ठिकानों पर ताबड़तोड़ दागीं मिसाइलें

AGENCY NEW DELHI : भारत ने बुधवार की रात 'ऑपरेशन सिंदूर' के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर बड़ी कार्रवाई की। इस हमले में कुल 9 आतंकी अड्डों को निशाना बनाया गया। पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, हमले में 3 लोगों की मौत हुई है और 12 लोग घायल हुए हैं। भारतीय सेना के अनुसार, ये वे ठिकाने थे, जहां से भारत पर हमलों की साजिशें रची जा रही थीं। हालांकि, हमले में पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाया गया है। ऑपरेशन के दौरान हुए नुकसान की जानकारी फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाई है। यह कार्रवाई 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में की गई है, जिसमें 26 पर्यटक मारे गए थे।

पाकिस्तानी मीडिया का दावा हमले में 3 लोगों की हुई मौत

ऑपरेशन सिंदूर : पहलगाम हमले के 15 दिन बाद बड़ी कार्रवाई

- भारतीय सेना के अनुसार, ये वे ठिकाने थे, जहां से भारत पर हमलों की रची जा रही थीं साजिशें
- एयर स्ट्राइक में पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को नहीं बनाया गया निशाना
- 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर में हुए आतंकी हमले के जवाब में की गई है यह कार्रवाई, इसमें 26 पर्यटक मारे गए थे

लाहौर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लागू

पाकिस्तान के लाहौर एयरपोर्ट पर आपात स्थिति घोषित कर दी गई है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और यात्रियों को तुरंत टर्मिनल खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। कई उड़ानें रद्द की जा चुकी हैं और कुछ विमानों को डायवर्ट किया गया है। एयरपोर्ट पर अफरा-तफरी की स्थिति बनी हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने कहा कि, यह शर्मनाक है।

आज झारखंड की राजधानी सहित 300 जिलों में होगा मॉक ड्रिल

बुधवार को परमाणु संयंत्रों, सैन्य ठिकानों, रिफाइनरी और जलविद्युत बांधों जैसे संवेदनशील प्रतिष्ठानों वाले करीब 300 नागरिक सुरक्षा जिलों में हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन, 'शत्रुतापूर्ण हमले' के लिए नागरिक प्रशिक्षण और बंकरों और खंदकों की सफाई के साथ मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन की अध्यक्षता में मंगलवार को एक उच्चस्तरीय बैठक में लोगों की सक्रिय सहभागिता के साथ मॉक अभ्यास करने पर विस्तार से चर्चा की गई थी। झारखंड में जिन जगहों पर मॉक ड्रिल की जाएगी, उसमें राजधानी रांची के साथ-साथ जमशेदपुर, बोकारो, गोड्डा, साहिबगंज और गोमिया शामिल हैं।

SHARE

सेंसेक्स	:	80,641.07
निफ्टी	:	24,379.60

SARAFA

सोना	:	8,575
चांदी	:	111.00

(नोट : सोना 22 कैरेट प्रति ग्राम)

BRIEF NEWS

उत्तर-पूर्वी जिलों में 10 को लू चलने की आशंका

RANCHI : झारखंड के उत्तर-पूर्वी जिलों में 10 मई को लू चलने की आशंका है। मौसम विभाग ने इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने जिन जिलों में लू चलने की आशंका व्यक्त की है उनमें दुमका, पाकुड और गोडडा शामिल है। वहीं विभाग के अनुसार राज्य भर में तापमान बढने की आशंका है। तापमान बढते ही राज्य में फिर से प्रचंड गर्मी पडेगी। इससे राजधानी रांची समेत सभी जिलों के तापमान में पांच से सात डिग्री की वृद्धि हो सकती है। उल्लेखनीय है कि अप्रैल माह में गर्जन और बारिश के कारण पूरे राज्यर भर में तापमान कम रहा। इससे लोगों को गर्मी का प्रकोप नहीं झेलना पडा। लेकिन मौसम विभाग ने आठ मई के बाद तापमान में वद्धि होने की आशंका जतायी है। मंगलवार को रांची में अधिकतम तापमान 32.5 डिग्री, जमशेदपुर में 33.5, डालटेनगंज में 37, बोकारो में 34.1, चाईबासा में 34.7, देवघर में 34.3, धनबाद में 29.2, गुमला में 32.6, हजारीबाग में 33.3 और गढवा में अधिकतम तापमान 37.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।

पुंछ में खाई में गिरी बस चार की मौत, 44 घायल

POONCH : मंगलवार को जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में एक बस अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। इस हादसे में एक सैनिक सहित चार लोगों की मौत हो गई है, जबकि 44 लोग घायल हैं। अधिकारियों ने बताया कि बस घनी गांव से मेंढर जा रही थी। इसी दौरान सुबह करीब 9.20 बजे बस अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। स्थानीय लोगों ने पुलिस, सेना और सीआरपीएफ के जवानों के साथ मिलकर तुरंत बचाव अभियान शुरू किया। अधिकारियों ने मृतकों की पहचान घनी गांव के 45 वर्षीय मोहम्मद मजीद, 55 वर्षीय शकीला बेगम और कस्बलारी के 60 वर्षीय नूर हुसैन के रूप में की है। घायलों में से आठ की हालत गंभीर है। मेंढर के ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर अशफाक चौधरी ने बताया कि गंभीर रूप से घायल आठ लोगों में से पांच को विशेष

रांची में संविधान बचाओ रैली : मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर बोला हमला, कहा-

इंटेलिजेंस इनपुट के बाद भी सरकार ने पहलगाम में नहीं किए सुरक्षा के इंतजाम

PHOTON NEWS RANCHI : मंगलवार को रांची के धुर्वा स्थित पुराने विधानसभा मैदान में कांग्रेस द्वारा आयोजित संविधान बचाओ रैली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला। ढोल-नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया गया। उनके साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल भी पहुंचे। रैली में राज्य के कई मंत्री और नेता भी मौजूद रहे। सभा को संबोधित करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें 22 अप्रैल के आतंकी हमले से तीन दिन पहले इंटेलिजेंस इनपुट था, जिसके चलते उन्होंने अपना कश्मीर दौरा रद्द कर दिया, लेकिन आम नागरिकों की सुरक्षा को नजरअंदाज किया गया। उन्होंने सवाल उठाया कि जब खतरे की जानकारी थी तो पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम क्यों नहीं किए गए। 26 बेगुनाहों की जान चली गई।

प्रधानमंत्री मोदी ने रद्द कर दिया था अपना कश्मीर दौरा, नहीं बचाए जा सके निर्दोष नागरिक

आदिवासी और गरीब नेताओं को जेल भेज कर डराना चाहती है सरकार

खड़गे ने कहा कि केंद्र सरकार आदिवासी और गरीब नेताओं को जेल भेज कर डराना चाहती है, लेकिन कांग्रेस इससे डरने वाली नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि झारखंड के मुख्यमंत्री को जेल भेजकर भाजपा सरकार ने लोकतंत्र का मजाक उड़ाया है। सरकार की नीतियों पर हमला करते हुए कहा कि पब्लिक सेक्टर को बंद करने की साजिश की जा रही है और पिछड़े वर्ग के युवाओं की नौकरियां छीनी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार जानबूझकर रिक्त पद नहीं भर रही, जिससे गरीबों को परेशान किया जा सके। उन्होंने लोगों से अन्याय के खिलाफ एकजुट होकर संविधान की रक्षा करने की अपील की। संविधान बचाओ रैली के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक भी की।

एकता का परिचय देते कांग्रेस नेता

जनता के लिए अच्छा काम कर रहे मंत्री-विधायक

खड़गे ने कहा कि झारखंड में गठबंधन सरकार बनने के बाद पहली बार यहां आया हूं। मैं सभी झारखंडवासियों का तहेदिल से शुक्रिया अदा करता हूं। हम सबने आपकी वजह से बहुमत हासिल किया और आज झारखंड में एक मजबूत सरकार चल रही है। खड़गे ने कहा कि हम सभी जनता से किये वादे निभा रहे हैं। हमारे सरकार के मंत्री, विधायक सभी मिलकर जनता के लिए अच्छे से काम कर रहे हैं। इसके लिए मैं इन सब को भी धन्यवाद देता हूं। खड़गे ने कहा कि आज जो अच्छा लिखता और बोलता है उसको भी जेल में डाल देते हैं। फ्रीडम आफ स्पीच को मोदी और शाह ने दबाकर रखा है। ईडी और सीबीआई केस कर रहे हैं। ईडी ने 200 केस किये, जिसमें सिर्फ दो को ही सजा मिली।

- पब्लिक सेक्टर को बंद करने की चल रही साजिश, खत्म किए जा रहे रोजगार के अवसर
- सरकार जानबूझकर रिक्त पद नहीं भर रही, ताकि गरीबों को परेशान किया जा सके

मंईयां योजना से खुश हैं सभी महिलाएं

खड़गे ने मंईयां योजना की तारीफ करते हुए कहा कि इस योजना से सभी महिलाएं खुश हैं। कांग्रेस और जेएमएम की सरकार मिलकर काम कर रही है। 56 सीट लाकर मजबूत सरकार झारखंड में है। जो भी वादे किए हैं, उसे निभा रहे हैं।

संविधान को बचाने का करना है काम

खड़गे ने कहा कि संविधान को बचाने का काम करना है। अगर इस काम में इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो फिर से गुलाम बन जाएंगे।

भाजपा गरीबों को कुचलने का काम कर रही है। आने वाली जनगणना में सरना कोड के लिए लड़ेंगे। धर्म की रक्षा भाजपा और पीएम मोदी नहीं कर सकते हैं। सरना कोड के लिए सीएम हेमंत सोरेन से भी कहूंगा। भीमराव अंबेडकर, महात्मा बुद्ध और महावीर भी सरना समाज को पसंद करते थे। उन्होंने कहा कि संविधान बचाओ रैली 40 दिन तक चलेगा। जिला, प्रखंड और बूथ लेवल पर काम करना होगा।

वन भूमि घोटाले को लेकर बोकारो में प्रवर्तन निदेशालय ने की कार्रवाई

दो ठिकानों पर मारी रेड, डिजिटल उपकरण जब्त

PHOTON NEWS BOKARO : मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने बोकारो में दो जगहों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई जमीन कारोबार से जुड़े लोगों के ठिकानों पर की गई है। ईडी की टीम बोकारो के चास स्थित राणा प्रताप नगर में महेश नागिया के घर पर पहुंची और छापेमारी की। वहां से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए गए हैं। महेश के तेतुलिया मौजा के जमीन फजीर्वाड़ा में शामिल अजहर और अख्तर हुसैन से संबंधों के कारण ईडी ने महेश के यहां दबिश दी है। ईडी की टीम ने बोकारो स्टील के एडीएम बिल्डिंग में भी छापेमारी की है। यह छापा तेतुलिया मौजा की उसी वन भूमि से जुड़े संदिग्ध अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी किए जाने के मामले में मारा गया है।

छापेमारी के दौरान जांच एजेंसी को कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी मिले

- बोकारो स्टील के एडीएम बिल्डिंग में भी दबिश
- अजहर और अख्तर हुसैन से संबंधों के कारण महेश के यहां छापा

बाबा बर्फानी की पहली तस्वीर आई सामने

AGENCY SRINAGAR : मंगलवार को कश्मीर के अनंतनाग जिले में अमरनाथ की पवित्र गुफा से बाबा बर्फानी की पहली तस्वीर सामने आ गई है। इस बार बर्फ का शिवलिंग करीब 7 फीट ऊंचा है। इस शिवलिंग के दर्शन के लिए देशभर से लाखों लोग अमरनाथ आते हैं। यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी जो करीब 38 दिन चलेगी। 9 अगस्त को छड़ी मुबारक के साथ रक्षाबंधन के दिन पूरी होगी। यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। जरूरी मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने की प्रक्रिया चल रही है।

- सात फीट ऊंचे हिम शिवलिंग के दर्शन को आएंगे लाखों श्रद्धालु जुलाई में शुरू होगी यात्रा
- शिवलिंग के दर्शन के लिए देशभर से लाखों लोग आते हैं अमरनाथ

न्यू स्टडी डॉक्टरों ने 13 वर्षों तक 4 लाख से अधिक लोगों पर किया शोध

तेज गति से टहलने पर नियंत्रित होंगी दिल की अनियमित धड़कनें

PHOTON NEWS @ RESEARCH DESK : आज के तनाव भरे दौर में कम उम्र में भी शुगर और हृदय संबंधी बीमारियां लोगों को हो रही हैं। ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखने के लिए सुबह में तेज गति से टहलने की सलाह डॉक्टर देते हैं। दूसरी सामान्य रूप से चिकित्सकीय भाषा में दौड़ने अथवा तेज चलने से दिल की धड़कनें असामान्य रूप से बढ़ जाया करती हैं। फिर धीरे-धीरे सामान्य होती हैं। कभी-कभार ऐसी स्थिति में दिल की धड़कनें बहुत कम भी हो जाया करते हैं। डॉक्टर इसे एट्रियल फिब्रिलेशन या हृदय अतालता कहते हैं। ताजा शोध से यह जानकारी सामने आई है कि तेज गति से पैदल चलना न केवल इस समस्या को नियंत्रित कर सकता है, बल्कि इसके जोखिम को 46 प्रतिशत तक घटाने में भी मददगार साबित हो सकता है। एक अन्य रिसर्च में पाया गया है कि एक हजार कदम चलने से मृत्यु का जोखिम 15 प्रतिशत तक घटता है। 60 साल से अधिक आयु के लोगों में 6 से 10 हजार कदम प्रतिदिन चलने पर मृत्यु जोखिम में 42 प्रतिशत की गिरावट देखी गई है।

तेजी से चलने वालों में 46 प्रतिशत कम पाया गया हृदय गति असामान्यता का खतरा

औसत गति से चलने वालों में 35% तक घटा हुआ पाया गया असामान्यता जोखिम

- ग्लासगो यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने पूरी स्थिति का व्यापक स्तर पर किया है विश्लेषण
- अंतरराष्ट्रीय रिसर्च जर्नल 'हार्ट' में विस्तार से प्रकाशित की गई है रिपोर्ट
- शोध में शामिल प्रतिभागियों ने खुद अपने चलने की गति धीमी, औसत या तेज बताई

धीमी गति से चलने वालों में यह जोखिम अपेक्षाकृत गंभीर स्थिति में देखा गया

बेहतर होती है मेटाबॉलिक रेट

तेज चलने से शरीर में मेटाबॉलिज्म (चयापचय) दर बेहतर होती है और सूजन संबंधी कारक घटते हैं। इससे हृदय की विद्युत गतिविधियों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त यह मोटापे को कम करता है, जो हृदय रोगों का एक प्रमुख कारण है।

निष्क्रिय लोगों में मौत का खतरा ज्यादा

शरीर में इंफ्लेमेशन (सूजन) को घटाकर हृदय की कोशिकाओं को स्वस्थ बनाए रखता है। इससे रक्त प्रवाह और ऑक्सीजन वितरण बेहतर होता है। इससे हृदय पर तनाव कम पड़ता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, जो लोग निष्क्रिय रहते हैं उनमें सक्रिय लोगों की तुलना में मौत का जोखिम 20-30 प्रतिशत अधिक होता है। इसलिए पैदल चलना एक सुलभ, सस्ता और प्रभावी व्यायाम माना जाता है। प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ प्रोफेसर मैकीज बानाच बताते हैं कि भले ही 10 हजार कदम चलना आदर्श माना जाता हो, लेकिन रोजाना सिर्फ 4 हजार कदम भी स्वास्थ्य लाभ के लिए पर्याप्त हो सकते हैं। ग्लासगो यूनिवर्सिटी के शोधकताओं ने पूरी स्थिति का व्यापक विश्लेषण किया है। इस विशेष अध्ययन से जुड़ी रिपोर्ट अंतरराष्ट्रीय जर्नल 'हार्ट' में विस्तार से प्रकाशित की गई है।

BRIEF NEWS

रनिया में गजराजों ने मचाया उत्पात, दंपती घायल

KHUNTI : रनिया प्रखंड में जंगली हाथियों का उत्पात थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा घटना सोमवार देर रात करीब डेढ़ बजे की है, जब एक भूखा जंगली हाथी बनई पंचायत के मनातू गांव में घुस आया और घुरन महतो के घर को ध्वस्त कर दिया। हाथी ने घर में रखे लगभग पांच क्विंटल चावल में से कुछ खा लिया और बाकी को बर्बाद कर दिया। घर गिरने से अंदर सो रहे घुरन महतो और उनकी पत्नी पुष्पा देवी मलबे के नीचे दब गईं। पुष्पा देवी को मामूली चोटें आई हैं, लेकिन घुरन महतो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हाथी की दहाड़ और घर गिरने की आवाज सुनकर गांववाले अपने घरों से निकल आए। उन्होंने मशालें जलाईं, ढोल-नगाड़े पीटे और शोर मचाकर हाथी को गांव से भगाया। इसके बाद ग्रामीणों ने मलबे में दबे दंपती को बाहर निकाला। घायलों को आनन-फानन में इलाज के लिए ले जाया गया, जहां घुरन महतो को रांची के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। गांव में हाथी के हमले से दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने वन विभाग से हाथियों के आतंक से निजात दिलाने की मांग की है।

हाथी से परेशान लोगों ने किया सड़क जाम

LOHARDAGA : भंडरा प्रखंड के कुम्हारिया गांव के ग्रामीण आठ दिनों से हाथी के उत्पात से परेशान हैं। ग्रामीणों को जानमाल का डर सता रहा है। भंडरा थाना क्षेत्र के कुम्हारिया गांव में सोमवार की रात हाथी ने दो परिवार का खपरैल घर पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। इसके अलावे कुम्हारिया क्षेत्र मे एक सप्ताह से जंगली हाथी लगभग छह ग्रामीणों के घरों को ध्वस्त कर चुके है। साथ ही सैकड़ो किसानो के फसल को बर्बाद किया है । घटना के विरोध, हाथी को भगाने की मांग और पीड़ित परिवारो को राहत एवं मुआवजा के लिए ग्रामीणों ने भंडरा अकाशी मार्ग को पांच घंटे तक जाम कर दिया गया। बीती रात कुम्हारिया मे गांव के सुरेन्द्र महली एवं महावीर लोहरा के घर को ध्वस्त कर दिया। ग्रामीणों ने बताया कि झुंड से बिछड़ा हुआ एक हाथी पिछले एक सप्ताह से बगुला पतरा मे डेरा जमाये हुऐ है। दिन भर बगुला पतरा मे रहने के बाद रात मे गांव की ओर रुख करता है और कभी कुम्हारिया तो कभी अम्बेरा कसपुर गांव पहुंचकर ग्रामीणों के फसल एवं घरों को क्षतिग्रस्त कर रहा है । कभी कभी हाथी दिन में भी रिहायशी क्षेत्र में आ जाता है। इधर घटना की सूचना देने के बाद भी वन विभाग नहीं पहुंच रही है। इससे ग्रामीणों मे आक्रोश बढ़ गया और इस घटना के विरोध में स्थानीय ग्रामीणों ने कुम्हारिया के पास करीब पांच घंटे अकाशी भंडरा मार्ग जाम कर दिया। सूचना के बाद बीडीओ प्रतिमा कुमारी, सीओ दुर्गा कुमार,थाना प्रभारी अरविंद सिंह, वहां पहुंचे और जाम करनेवालों को तीन दिनों में हाथी को भगाने का आश्वासन देकर जाम समाप्त कराया।

भाकपा-माओवादी के पांच नक्सली किए गए गिरफ्तार

सड़क निर्माण कंपनी के मुंशी की हत्या के मामले में थे शामिल

पत्रकारों को पूरे मामले की जानकारी देते एसपी कुमार गौरव ● फोटोन न्यूज

AGENCY LATEHAR : लातेहार एसपी कुमार गौरव को मिली गुप्त सूचना पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भाकपा माओवादियों के पांच नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार सभी नक्सली गत 30 अप्रैल की रात को जिले के महुआडांड़ थाना क्षेत्र के ओरसापाट गांव के पास बन रहे सड़क निर्माण कार्य के मुंशी की हत्या तथा गाड़ियों को जलाने की घटना में शामिल थे। गिरफ्तार माओवादी नक्सलियों में सत्येंद्र यादव, सूरजभान यादव, कृष्ण यादव, राजेंद्र यादव और प्रसाद यादव शामिल हैं। सभी महुआडांड़ थाना क्षेत्र के निवासी हैं। मंगलवार को महुआडांड़ थाना में प्रेस वार्ता करते हुए इंस्पेक्टर पीर मोहम्मद ने बताया कि लातेहार एसपी कुमार गौरव को मिली गुप्त सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सघन छापेमारी अभियान चलाकर पांचों नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। छानबीन के दौरान उनके पास से लेवी के रूप में वसूले गए लगभग 52 हजार रुपये तथा कई नक्सली पर्चा भी बरामद किया गया। गिरफ्तार नक्सलियों ने पूछताछ के दौरान अपने अपराध भी स्वीकार किया और कहा कि माओवादी कमांडर कुंदन खरवार के नेतृत्व में घटना को अंजाम दिया गया था। पुलिस इंस्पेक्टर ने बताया कि एसपी के निर्देश पर पुलिस की टीम घटना में शामिल अन्य नक्सलियों की गिरफ्तारी के लिए भी लगातार छापेमारी अभियान चला रही है।

शादी के 16 दिन पहले युवक की सड़क हादसे में हुई मौत

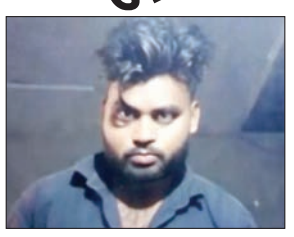

मृतक की फाइल फोटो

PALAMU : शादी के 16 दिन पहले एक युवक की मौत हो गई। अपनी शादी का कार्ड बांटकर लौटने के दौरान सोमवार रात युवक सड़क हादसे का शिकार हो गया। घटना पलामू जिले के पिपरा थाना क्षेत्र के विजय तारा पेट्रोल पंप के पास हुई। अज्ञात वाहन से मोटरसाइकिल में टक्कर हो गई। बाइक पर साथ बैठा युवक जख्मी हुआ है। मृत युवक की पहचान छतरपुर के कंचनपुर गांव निवासी बसंत राम का पुत्र अविनाश कुमार (26) के रूप में हुई है। उसके साथ बाइक पर पीछे बैठा युवक चंदन कुमार बताया गया है। मंगलवार को शव का पोस्टमार्टम एमआरएमसीएच में किया गया। घटना के बाद शादी की तैयारी बंद हो गई है और घर में खुशी का माहौल मातम में बदल गया है। परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल बना हुआ है। जानकारी के अनुसार अविनाश और चंदन सोमवार की रात डालटनगंज-औरंगाबाद एनएच 98 पर बाइक से लौट रहे थे। जैसे ही पिपरा थाना क्षेत्र में विजय तारा पेट्रोल पंप के पास पहुंचे कि अज्ञात वाहन से उनकी मोटरसाइकिल में टक्कर हो गई। मौके पर ही अविनाश कुमार की मौत हो गई, जबकि चंदन को गंभीर स्थिति में इलाज के लिए एमआरएमसीएच भेजा गया। मृतक के पिता बसंत राम के अनुसार अविनाश का तिलक 18 मई को था और 21 को बारात गढ़वा जिला में जानी थी। सोमवार सुबह 11 बजे के करीब अविनाश शादी का कार्ड बांटने निकला था। अपने दोस्त को भी साथ ले गया था। रात में वापस घर लौट रहा था, तभी हादसा हुआ। जानकारी होने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों युवकों को छतरपुर अनुमंडलीय अस्पताल में इलाज के लिए भेजा।

म्यूटेशन के लिए रिश्वत ले रहा राजस्व कर्मी रंगेहाथ गिरफ्तार

आरोपी को ले जाती पुलिस ● फोटोन न्यूज

LATEHAR : लातेहार अंचल कार्यालय में पदस्थापित राजस्व कर्मचारी सुशील कुमार को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। राजस्व कर्मचारी जमीन म्यूटेशन के लिए एक ग्रामीण से 10 हजार रुपये रिश्वत ले रहा था। एसीबी एसपी अंजनी अंजन ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार लातेहार के एक जमीन मालिक से जमीन के म्यूटेशन के बदले राजस्व कर्मचारी के द्वारा 20 हजार रुपए की मांग की जा रही थी। परेशान होकर सूचक ने पलामू एसीबी की टीम से मामले की शिकायत की।

शिकायत प्राप्त होने के बाद एसपी के निर्देश पर निगरानी की टीम ने पूरे मामले की छानबीन की। रिश्वत मांगने की जब पुष्टि हो गई तो निगरानी की टीम ने राजस्व कर्मचारी को रंगेहाथ गिरफ्तार करने की योजना बनाई।

संजय नदी के किनारे कचरा डंप करने का लोगों ने किया विरोध, आश्वासन पर माने

एसडीओ के समझाने के बाद मामला हुआ शांत, डेढ़ माह में हो जाएगी री-साइक्लिंग

डंपिंग एरिया के पास विरोध करते स्थानीय निवासी ● फोटोन न्यूज

PHOTON NEWS CKP : चक्रधरपुर शहर के वार्ड संख्या-2, कुदलीबाड़ी स्थित शमशान घाट पर नगर परिषद ने डंपिंग यार्ड बनाया है। जिसमें शहर से उठाए गए कचरों को फेंका जाता है। लेकिन, कुछ दिनों से डंपिंग यार्ड के बजाए बाहर में कचरा फेंका जा रहा है। डंपिंग यार्ड के बाहर कचरों का पहाड़ बना दिया गया है। ऐसा करने से क्षेत्र में बदबू फैलनी शुरू हो गई है। इसके बाद स्थानीय लोगों ने कचरा फेंकने पर रोक लगा दिया और विरोध जताया।

कचरा फेंकने नहीं देने से शहर का कचरा उठाव होना बंद हो गया। एक सप्ताह में ही शहर की स्थिति बदतर हो गई। शहर के विभिन्न गली-मोहल्लों और सड़कों पर कचरों का ढेर लग गया। लोगों को सड़कों पर चलना मुश्किल हुआ। इसके बाद प्रशासन पर दबाव बना। विरोध जता रहे लोगों को नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी राहुल यादव द्वारा काफी समझाने-बुझाने की कोशिश की गई, लेकिन स्थानीय लोग नहीं माने और कचरा फेंकने पर रोक लगा रखा। इससे दिक्कतें बढ़ीं। समस्या को देखते हुए मंगलवार की शाम पांच बजे एसडीओ श्रुति राजलक्ष्मी, एएसपी शुभम प्रकाश, सीओ सुरेश कुमार सिन्हा डंपिंग यार्ड पहुंचे, जहां वस्तुस्थिति को देखा।

विरोध जता रहे लोगों के साथ एसडीओ, एएसपी, सीओ व कार्यपालक पदाधिकारी राहुल यादव ने वार्ता की, जिसमें प्रशासन ने आश्वासन दिया कि डंपिंग यार्ड के बाहर जितना कचरा है, उसे डेढ़ महीने के अंदर री-साइकिल कर दिया जाएगा तथा डंपिंग यार्ड के बाहर कचरा नहीं फेंका जाएगा। प्रशासन के इस आश्वासन के बाद विरोध टला। अब बुधवार से शहर में जमा करना नियमित रुप से उठेगा।

देवघर के श्रावणी मेले में इस बार सोमवार को नहीं मिलेगी वीआईपी दर्शन की सुविधा

नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार ने बैठक में सुनाया निर्णय

परिसदन में बैठक करते मंत्री सुदिव्य कुमार ● फोटोन न्यूज

AGENCY DEOGHAR : राजकीय श्रावणी मेला 2025 की तैयारियों को लेकर नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक मंगलवार को देवघर के परिसदन सभागार में की गई। बैठक मेला की तैयारियों को लेकर मंत्री ने विभागवार समीक्षा की और अधिकारियों को कई निर्देश दिया। बैठक में श्रद्धालुओं को समान अवसर देने के लिए इस वर्ष सोमवार को आउट ऑफ टर्न दर्शन (वीआईपी और वीवीआईपी दर्शन) पर पूर्ण रूप से रोक लगाने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा श्रावणी मेला में तकनीक का व्यापक उपयोग करने का निर्णय लिया गया। इसमें एआई आधारित इंटीग्रेटेड मेला कंट्रोल रूम बनाने, एआई चैटबोट-सूचना, फीडबैक और हेल्पलाइन, एआई आधारित ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, क्यूनआर कोड आधारित फीडबैक सिस्टम, लोकेशन बेस्ड अटेंडेंस सिस्टम और डिजिटल पवेलियन की सुविधा शामिल है।

सुरक्षा और तकनीकी नवाचार पर जोर

बैठक में मंत्री ने कहा कि श्रावणी मेला झारखंड की पहचान है और लाखों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा है। इसलिए सभी विभागों को आपसी समन्वय से काम करने की जरूरत है। ताकि सुलभ व सुरक्षित जलार्पण के साथ श्रद्धालुओं को बेहतर अनुभूति प्राप्त हो।

श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्था

मेला क्षेत्र में स्वास्थ्य केंद्र, सूचना सह सहायता केंद्र, टेंट सिटी, पेयजल, स्नानगृह, शौचालय, कूड़ेदान, सफाई व्यवस्था, इंद्र वर्षा (मिस्ट कूलिंग) और सजावट और तोरण द्वार की बेहतर योजना पर निर्देश दिया गया। साथ ही पुख्ताश सुरक्षा व्यदवस्था को लेकर ओपी, ट्रैफिक नियंत्रण केंद्र, अपराध नियंत्रण, वाहन पड़ाव स्थल और रूटलाइनिंग की विस्तृत योजना पर चर्चा हुई, ताकि श्रद्धालुओं को सहज अनुभव मिल सके। इसके अलावा विद्युत आपूर्ति, नगर विकास, पेयजल और स्वच्छता, पर्यटन, जनसंपर्क, स्वास्थ्य, भवन प्रमंडल सहित सभी विभागों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण काम को पूरा करने को कहा गया। बैठक में पर्यटन सचिव, देवघर उपायुक्त, दुमका उपायुक्त, पर्यटन निदेशक समेत विभिन्न विभागों के वरीय पदाधिकारी मौजूद रहे।

लातेहार में निःशुल्क अंग प्रत्यारोपण शिविर शुरू

LATEHAR : जिले में जरूरतमंद दिव्यांगों के लिए रेडक्रॉस परिसर में मंगलवार को निःशुल्क अंग प्रत्यारोपण शिविर शुरू हुआ, जो 8 मई तक चलेगा। भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति, जयपुर के तत्वावधान में सदर अस्पताल लातेहार के समीप स्थित रेडक्रॉस सोसाइटी परिसर में आयोजित शिविर में उन लोगों को कृत्रिम अंग उपलब्ध कराए जाएंगे, जिनके हाथ या पैर किसी कारणवश कट गए हैं या वे जन्म से ही शारीरिक रूप से असमर्थ हैं। इसके अतिरिक्त अन्य शारीरिक अंग जो कार्य करने में अक्षम हो चुके हैं, उनकी सहायता के लिए भी विशेषज्ञ टीम द्वारा तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। शिविर पूरी तरह निःशुल्क है। इसमें भाग लेने वाले लोगों के रहने, खाने और इलाज की संपूर्ण व्यवस्था आयोजकों द्वारा की गई है।

सीसीएल कर्मी महिला से हुई साढ़े दस लाख रुपये की ठगी

पीड़ित महिला

BERMO : बोकारो जिला के बेरमो अनुमंडल स्थित बोकारो थर्मल थाना अंतर्गत सीसीएल जारंगडीह कोलियरी में कार्यरत महिला कर्मी सुदामा माहली से धोखाधड़ी कर बैंक से लोन दिलाकर उसके ही अकाउंट से दो बार में चेक से साढ़े दस लाख रुपये की निकासी कर ली गई। घटना की लिखित सूचना महिला कर्मी ने मंगलवार को स्थानीय थाना को दी। थाना प्रभारी पिंकू कुमार यादव के निर्देश पर अवर निरीक्षक अजीत कुमार ने मामले की जांच आरंभ कर दी है। घटना के संबंध में महिला कर्मी ने थाना को दिए गए आवेदन में बताया है कि बोकारो थर्मल हॉस्पिटल मोड़ कॉलोनी निवासी ललन रविदास और राजेश कुमार ने उसे बैंक से लोन दिलाने की बात कही। गिरिडीह स्थित एसबीआई से उसे साढ़े दस लाख रुपये का लोन दिलाने की प्रक्रिया पूरी होने की बात कहते हुए दोनों ने उससे हस्ताक्षर किया हुआ दो चेक बैंक में जमा करने की भी बात कहते हुए ले लिया। चूंकि वह अनपढ़ आदिवासी महिला है, इसलिए दोनों ने लोन स्वीकृत कराकर बोकारो थर्मल एसबीआई स्थित उसके अकाउंट नंबर-11086212607 से दो बार में साढ़े आठ लाख और दो लाख रुपये, कुल साढ़े दस लाख रुपये की निकासी कर ली। बाद में, जब वह पासबुक अपडेट कराने बैंक गई तब उसे पता चला कि उसके अकाउंट से साढ़े दस लाख रुपये की निकासी कर ली गई है।

तालाब में डूबकर युवक की हुई मौत

SERAIKELA : सरायकेला-खरसावां जिले के चांडिल थाना क्षेत्र के कपाली पंचायत स्थित उड़ियासिली गांव में मंगलवार को युवक रविंद्रनाथ प्रमाणिक (26) की तालाब में डूबने से मौत हो गई। बताया जाता है कि रविंद्रनाथ रोज की तरह सुबह तालाब में नहाने गया था। नहाने के दौरान अचानक उसका पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में चला गया, जब आसपास के लोगों ने उसे डूबते देखा तो तुरंत तालाब से बाहर निकाला और परिजनों की मदद से उसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। रविंद्रनाथ प्रमाणिक गांव के ही सैलून में काम करता था और तीन भाइयों में सबसे छोटा था। उसकी शादी वर्ष 2021 में हुई थी, लेकिन आपसी विवाद के कारण उसकी पत्नी उसे छोड़कर मायके चली गई थी।

पूर्व मुख्यमंत्री ने कांग्रेस को बताया संविधान व दलित का सबसे बड़ा विरोधी

झारखंड में बढ़ता जा रहा 'दो टोपियों' का बोलबाला : रघुवर दास

पत्रकारों को संबोधित करते रघुवर दास ● फोटोन न्यूज

PHOTON NEWS JSR : पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मंगलवार को कांग्रेस और झामुमो सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज झारखंड में 'दो टोपियों' का दबदबा बढ़ता जा रहा है, जो न सिर्फ फल-फूल रहा है, बल्कि सत्ता पर भी इनका असर है।

हालांकि, पत्रकारों द्वारा पूछे जाने पर कि यह 'दो टोपियों' वाला कौन हैं, उन्होंने खुलकर नाम नहीं लिया और कहा कि आप लोग जानते हैं कि कौन टोपी पहनता है।

एग्रिको स्थित अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए रघुवर दास ने मंगलवार को रांची में हुई कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली को दिखावा करार दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ही असल में डॉ. भीमराव अंबेडकर और दलितों के अधिकारों की विरोधी रही है। जब तक कांग्रेस सत्ता में रही, तब तक अंबेडकर को भारत रत्न नहीं दिया गया। इसके उलट, कांग्रेस ने अंबेडकर को लोकसभा चुनाव में हराने के लिए उम्मीदवार तक खड़ा कर दिया था।

इमरजेंसी व संविधान पर हमला

पूर्व मुख्यमंत्री ने 1975 के आपातकाल को याद करते हुए कहा कि उस समय कांग्रेस ने संविधान की धज्जियां उड़ाई थीं। अनुच्छेद 14, 21 और 32 में बदलाव कर जनता के मौलिक अधिकार छीन लिए गए थे। पत्रकारों और आम नागरिकों की गिरफ्तारियां की गईं और उन्हें बिना सुनवाई के जेल भेजा गया। रघुवर दास ने कहा कि मुझे भी उस समय गिरफ्तार किया गया था।

राज्य में हो गए 10 क्रिश्चियन एमएलए

रघुवर दास ने कहा कि राज्य में अब 10 क्रिश्चियन विधायक और दो सांसद हो चुके हैं, जो अवैध धर्मांतरण और घुसपैठ का परिणाम है। उन्होंने सरकार से पूछा कि वह पेसा कानून को लागू क्यों नहीं कर रही है, जबकि यह संविधान की पांचवीं अनुसूची में शामिल है।

धर्मांतरण, लव जिहाद और घुसपैठ का आरोप

रघुवर दास ने राज्य में बढ़ते धर्मांतरण को गंभीर खतरा बताया। उन्होंने कहा कि झारखंड में आदिवासी संस्कृति को खत्म करने की साजिश हो रही है और सरकार इसमें मूकदर्शक बनी हुई है। उन्होंने झामुमो सरकार पर धर्मांतरण को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य में अवैध घुसपैठ, लव जिहाद और लैंड जिहाद जैसी गतिविधियां तेज हो गई हैं। उन्होंने झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों की मौजूदगी का मुद्दा भी उठाया और कहा कि संथाल परगना, एकीकृत सिंहभूम और रांची जैसे इलाकों में इनकी संख्या तेजी से बढ़ रही है। आरोप लगाया कि झामुमो और कांग्रेस के नेता खुद इनका आधार और वोटर कार्ड बनवा रहे हैं, ताकि ये सरकारी योजनाओं का फायदा उठा सकें।

...तो सरकार से समर्थन वापस ले कांग्रेस

उन्होंने कांग्रेस को चुनौती देते हुए कहा कि अगर वह वास्तव में संविधान की रक्षक है, तो उसे झामुमो सरकार से समर्थन वापस लेना चाहिए। क्योंकि, झामुमो के मंत्री हफीजुल हसन ने शरीयत को पहले और संविधान को उसके बाद माना है। इसके साथ ही उन्होंने हफीजुल हसन जैसे मंत्रियों को बर्खास्त करने की मांग की जो शरीयत को संविधान से ऊपर बताते हैं।

पंचायतों को सशक्त बनाना जिला प्रशासन की प्राथमिकता : उपायुक्त

छात्रों को प्रमाणपत्र देते डीसी डॉ. वाघमारे प्रसाद ● फोटोन न्यूज

AGENCY LOHARDAGA : पंचायत ज्ञान केंद्र के अधिष्ठापन और एक ग्रामीण पुस्तकालय के रूप में उसके उपयोग और आदर्श ग्राम पंचायत की स्थापना विषय पर जिला पंचायत राज कार्यालय की ओर से कार्यशाला का आयोजन नया नगर भवन में मंगलवार को किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलित कर उपायुक्त डॉ वाघमारे प्रसाद ने किया। उपायुक्त ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पंचायतों को सशक्त बनाना जिला प्रशासन की प्राथमिकता में रही है। पंचायत स्तरीय व्यवस्था को सुदृढ़ करना सुनिश्चित किया गया है। इसी कड़ी में हम सबने ठाना है कि पंचायत में मिलनेवाली सभी सेवाओं को सशक्त किया जाए, पंचायत स्तर पर डिजिटल क्रांति लायी जाए। पंचायत सचिवालय में जो सेवा मिलती है उसे डिजिटाइज किया सके, इस दिशा में पहल की गई है। हम सभी का प्रयास है कि पंचायत स्तर पर ही काम हो जाए ताकि किसी व्यक्ति को प्रखण्ड स्तर या जिला स्तर के कार्यालय में अपना काम कराने नहीं जाना पड़े। ऐसी सिंगल विण्डो की व्यवस्था हो। उपायुक्त ने कहा कि पंचायत सचिवालय में पंचायत ज्ञान केंद्र खुलेगा जिसमें कोई भी अध्ययन कर सकेंगे। इसमें वैसे छात्र-छात्राओं को सुविधा मिलेगी जो गांव में रहते हुए अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं। जिला और प्रखण्ड स्तर पर पुस्तकालय की सुविधा है लेकिन अब तक पंचायत स्तर पर पुस्तकालय की व्यवस्था नहीं थी। पंचायत ज्ञान केंद्र के खुलने से यह कमी दूर हो जाएगी। ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों का पूरा फायदा मिलेगा। पंचायत सेवक, मुखिया और सेवानिवृत्त शिक्षकों की भूमिका पंचायत ज्ञान केंद्र में काफी महत्वपूर्ण हो जाएगी। बच्चों के माता-पिता अपने बच्चों को प्रेरित करेंगे ताकि उनके बच्चे पंचायत ज्ञान केंद्र में पढ़ाई करने के लिए जाएं।

BRIEF NEWS

एबीवीपी ने आज होने वाली 'सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल' का किया स्वागत

RANCHI : अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने केंद्र सरकार द्वारा 7 मई को होने वाली 'सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल' का स्वागत करते हुए युवाओं और विद्यार्थियों से इसमें सक्रिय भागीदारी की अपील की है। बता दें कि कुछ दिन पहले कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले और बढ़ते साइबर खतरों के मद्देनजर यह मॉक ड्रिल देशभर में नागरिक और संस्थागत तंत्र की आपात स्थितियों से निपटने की तैयारियों को सशक्त करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

रैली में शामिल हुए सिठियो से सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता

RANCHI : नामकुम प्रखंड के सिठियो से रांची जिला ग्रामीण महासचिव मोहम्मद ओवैस आजाद के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता संविधान बचाओ रैली में शामिल हुए। इस मौके पर कांग्रेस नेताओं और कार्यकताओं में उत्साह देखते ही बन रहा था। कार्यकताओं ने कहा कि इस रैली का उद्देश्य संविधान के प्रति लोगों को जागरूक करना है।

पासवा ने प्राइवेट स्कूलों की समस्या पर की चर्चा

RANCHI : प्राइवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन ने राज्य में संचलित निजी विद्यालयों कि समस्याओं के संबंध में एसोसिएशन के कार्यकारी अध्यक्ष मो.उस्मान की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय ऑनलाइन बैठक का आयोजन गूगल मीट के माध्यम से किया। संचालन प्रदेश सचिव तौफीक हुसैन ने किया। इस वर्चुअल बैठक में झारखंड के विभिन्न जिलों से जुड़े संगठन के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने हिस्सा लिया और पासवा ने उन सभी का स्वागत किया। बैठक में हाई कोर्ट द्वारा जारी आदेश पर चर्चा हुई। बैठक को सफल बनाने में मसूद कच्ची, अरविंद कुमार, आलोक विपिन टोप्पो ने अहम भूमिका निभाई।

नवनियुक्त तीन काजी हुए सम्मानित

RANCHI : पठान तंजीम ने झारखंड सरकार द्वारा नियुक्त तीन शहर काजियों को सम्मानित किया। हिंदपीढ़ी सेकेंड स्ट्रीट स्थित तंजीम के केंद्रीय कार्यालय में कारी अंसार कासमी, मौलाना नासिरउद्दीन फैजी और हाफिज अबुल कलाम को स्मृति चिह्न, प्रणाम पत्र और साफा प्रदान कर सम्मानित किया गया। मौके पर तंजीम के अध्यक्ष अयूब राजा खान, उपाध्यक्ष वसीम खान बबलू, सचिव शहजाद बबलू, सह सचिव रिजवान खान और कोषाध्यक्ष तौसीफ खान, हाजी फिरोज जिलानी, अतिकुर रहमान, मेराज गद्दी, शकील अहमद, इमरान बाबू, हीरा भाई, मोहम्मद शोएब, अलीम खान, मंजर जावेद, अधिवक्ता अजहर खान, नौशाद, शमशु खान, अशफाक बबलू व सज्जाद इदरीसी सहित कई लोग मौजूद थे।

मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिया संगठन को मजबूत बनाने का टास्क

- प्रदेश कांग्रेस की विस्तारित कार्यसमिति की हुई बैठक, केसी वेणुगोपाल व झारखंड प्रभारी के. राजू हुए शामिल
- प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने की विगत छह महीनों की गतिविधियों की समीक्षा
- आगामी कार्यक्रमों की प्रस्तुत की रूपरेखा

विस्तारित कार्यसमिति की बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे व अन्य ● फोटोन न्यूज

PHOTON NEWS RANCHI : मंगलवार को झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की विस्तारित कार्यसमिति की बैठक बीएनआर चाणक्य के सभागार में प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश की अध्यक्षता में हुई। बैठक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और झारखंड प्रभारी के राजू विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद थे। बैठक में पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने, जनमुद्दों को घर-घर पहुंचाने और आगामी राजनीतिक रणनीतियों पर विस्तृत चर्चा हुई। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि सरकार बनने के बाद संगठन का काम समाप्त नहीं होता, बल्कि तब उसका असली दायित्व शुरू होता है। उन्होंने पदाधिकारियों से अपील की कि वे मैं नहीं हम की भावना से संगठन को मजबूत करें। उन्होंने कहा कि संगठन की बदौलत ही सांसद, विधायक और मंत्री बनते हैं, इस नाते सभी को संगठन की मजबूती पर ध्यान देना चाहिए। बैठक में कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता, विधायक, पूर्व मंत्री और संगठन के प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित रहे। अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने विगत छह महीनों की गतिविधियों की समीक्षा की और आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा प्रस्तुत की।

विचारधारा को जन-जन तक पहुंचाए : खड़गे ने कांग्रेस के उसूलों और विचारधारा को जन-जन तक पहुंचाने पर जोर देते हुए कहा कि अगर हम उसूलों पर चलें तो कोई उंगली नहीं उठाएगा। उन्होंने संविधान बचाओ रैली की सफलता के लिए झारखंड कांग्रेस के नेताओं, कार्यकताओं और जनता को बधाई दी।

खड़गे से मिले सीएम हेमंत सोरेन, कई मुद्दों पर हुई चर्चा

RANCHI : मंगलवार को झारखंड दौरे पर पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन होटल बीएनआर पहुंचे। सीएम के साथ उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी मौजूद थीं। करीब 40 मिनट तक दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई। इस दौरान कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल भी मौजूद थे। मुलाकात के दौरान वर्तमान राजनीतिक स्थिति और सरकार के कामकाज पर चर्चा हुई है। बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मीडियाकर्मियों से बात करते हुए कहा कि ये हमारे अलायंस के लोग हैं, बड़े नेता हैं?। इनका (मल्लिकार्जुन खड़गे) कार्यक्रम झारखंड में था। ऐसे में शिष्टाचार मुलाकात तो बनती है। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि उसी बाबत कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात हुई है। मीडियाकर्मियों द्वारा जातीय जनगणना को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हमलोगों की मांग रही है। जानकारी के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच बिहार चुनाव में जेएमएम के सीटों की दावेदारी और तैयारी पर चर्चा हुई है। गौरतलब है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में 14 सीटों पर तैयारी कर रखी है, जिसमें हर हाल में पार्टी 12 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। जिन सीटों पर जेएमएम लड़ना चाह रहा है, उनमें झाझा, चकाई, कटोरिया, धमदाहा, मनिहारी, पीरपैंती, नाथनगर, बांका, ठाकुरगंज, रुपौली, रामपुर और बनमनखी शामिल हैं।

बेसिक सुविधाएं देने के सभी दावे फेल, पब्लिक हो रही परेशान

टैक्स वसूलने में अव्वल बना नगर निगम, सुविधाएं देने में फिसड्डी

VIVEK SHARMA RANCHI : रांची नगर निगम के जिम्मे शहर की सफाई व्यवस्था है। शहर के लोगों को बेसिक सुविधाएं पानी, सड़क, नाली भी मुहैया कराना भी है। इसके बदले में रांची नगर निगम शहर में लोगों से टैक्स वसूलता है। वहीं टैक्स वसूलने में रांची नगर निगम राज्य के सभी निकायों में अव्वल रहा है। लेकिन लोगों को सुविधाएं देने में फिसड्डी साबित हो रहा है। राजधानी के नागरिकों ने बीते एक वर्ष में नगर निगम को लगभग 90 करोड़ रुपये का टैक्स दिया, लेकिन इसके बावजूद शहर की सड़कों, जलापूर्ति और सफाई जैसी मूलभूत सुविधाओं की हालत ज्यों की त्यों बनी हुई है। निगम भले ही टैक्स वसूली में अव्वल रहा हो, लेकिन सुविधा देने के मामले में पूरी तरह फिसड्डी साबित हुआ है।

टूटी-फूटी सड़कों से गुजर रहे लोग : शहर के कई वार्डों में आज भी लोग टूटी-फूटी और कच्ची सड़कों से गुजरने को मजबूर हैं। खासकर शहर के बाहरी इलाकों और नए बसे इलाकों में सड़कों की हालत बदतर है। बरसात के दिनों में इन सड़कों पर कीचड़ और जलभराव आम बात है, जिससे लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ती है। कुछ इलाकों में तो सड़कें आज भी कच्ची हैं, जहां न वाहन ठीक से चल पाते हैं, न ही पैदल चलना सुरक्षित रहता है।

- शहर के कई इलाकों में सड़कों की हालत खराब
- कुछ इलाकों में तो कच्ची सड़क से गुजर रहे लोग
- वार्डों में एचवाईडीटी का मोटर खोलकर ले गया ठेकेदार
- 90 करोड़ रुपये टैक्स राजधानी के लोगों से एक साल में वसूला निगम ने
- बेसिक सुविधाएं देने के सभी दावे फेल, पब्लिक हो रही परेशान
- बंपर हुई वसूली, फिर भी बुनियादी सुविधाओं को तरसते रहे लोग

पानी की समस्या से होना पड़ रहा दो-चार

गर्मी में लोगों को पानी की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। इतनी गर्मी के बीच में ही ठेकेदार की वार्डों से दर्जनों मोटर खोलकर रिपेयर कराने ले गया है। लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी मोटर का पता नहीं है। वहीं इसकी कोई जानकारी भी लोगों को नहीं मिल पा रही है। ठेकेदार द्वारा मरम्मत के नाम पर कई जगहों से मोटर तो निकाल लिए गए और कई दिनों से उन्हें दोबारा नहीं लगाया गया है। इससे लोगों को पीने के पानी के लिए इधर-उधर भटकना पड़ रहा है। पूर्व पार्षदों के पास लोग इसके लिए गुहार लगा रहे है। आखिर उन्हें जरूरत का पानी जो नहीं मिल पा रहा है।

घरों से हर दिन नहीं उठ रहा कचरा

शहर में डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन का जिम्मा रांची नगर निगम ने स्वच्छता कापोर्रेशन को दे दिया है। कुछ दिन तो एजेंसी ने बेहतर काम किया। लेकिन 5 महीने बीतने के बाद ही एजेंसी ने रंग दिखाना शुरू कर दिया है। अब तो हर दिन डोर टू डोर कलेक्शन ही नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थिति में कचरा लोगों के घरों में पड़ा है। मजबूरी में लोग घरों का कचरा रोड किनारे फेंक रहे है। जिससे शहर की छवि भी खराब हो रही है। जबकि वेस्ट कलेक्शन के लिए भी शहर के लोगों से रांची नगर निगम वेस्ट यूजर चार्ज वसूलता है।

निगम क्षेत्र में 2.40 लाख हाउस होल्डर

रांची नगर निगम क्षेत्र में 2.40 लाख के करीब हाउस होल्डर रजिस्टर्ड है। इसके अलावा भी शहर में बड़ी आबादी नगर निगम क्षेत्र में निवास करती है। इसके बावजूद नगर निगम लोगों को बुनियादी सुविधाएं मुहैया नहीं करा पा रहा है। शहर के लोगों की मांग है कि निगम टैक्स वसूली जितनी गंभीरता से करता है, उतनी ही प्राथमिकता सुविधाएं देने में भी दिखाए। साथ ही काम में पारदर्शिता के साथ जवाबदेही तय की जाए। तभी लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेगी।

स्वच्छता व्यवस्था सुदृढ़ करने को नगर निगम ने दिए सख्त निर्देश

PHOTON NEWS RANCHI : रांची नगर निगम क्षेत्र में स्वच्छता व्यवस्था को सुदृढ़ करने और कूड़े के स्रोत पृथक्करण को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से मंगलवार को उप प्रशासक रविंद्र कुमार की अध्यक्षता में स्वच्छता शाखा की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जिसमें सहायक प्रशासक निहारिका तिर्की, नगर प्रबंधक, जोनल सुपरवाइजर, एमटीएस इंचार्ज, स्वच्छता कॉरपोरेशन एवं पीएमसी प्रतिनिधि उपस्थित रहे। उप प्रशासक ने कहा कि फिलहाल निगम क्षेत्र से प्रतिदिन लगभग 50 टन गीला कूड़ा संग्रहित किया जा रहा है, लेकिन इस मात्रा में और वृद्धि की आवश्यकता है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि शहर के लोगों का सहयोग अत्यंत आवश्यक है, ताकि कूड़े के स्रोत पर ही गीला और सूखा कूड़ा अलग-अलग किया जा सके।

डोर टू डोर जाकर करेंगे निरीक्षण

बैठक में निर्णय लिया गया कि सैनिटरी इंस्पेक्टर, इनफोर्समेंट शाखा, स्वच्छता कॉरपोरेशन कर्मी एवं वार्ड सुपरवाइजर की संयुक्त टीम द्वारा विभिन्न वार्डों में घर-घर जाकर बल्क वेस्ट जनरेटर, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों एवं आवासीय भवनों में कूड़ा पृथक्करण की व्यवस्था का निरीक्षण किया जाएगा। उप प्रशासक ने सख्त निर्देश दिए कि किसी भी परिस्थिति में मिक्स कूड़े का संग्रहण नहीं किया जाएगा। झिरी स्थित 150 टन प्रतिदिन क्षमता वाले गेल सीबीजी प्लांट के माध्यम से गीले कूड़े से ऊर्जा और जैविक खाद तैयार की जा रही है। इस संदर्भ में वृहद स्तर पर जनजागरूकता अभियान चलाया जाएगा।

निगम की सुविधाएं की जाएगी बंद : उन्होंने यह भी कहा कि जो बल्क वेस्ट जेनरेटर और अपार्टमेंट्स शत-प्रतिशत कूड़ा पृथक्करण सुनिश्चित करेंगे, उन्हें निगम द्वारा प्रोत्साहन पत्र दिया जाएगा। वहीं, बार-बार निर्देश के बावजूद जो नियमों का पालन नहीं करेंगे, उन्हें नोटिस जारी कर निगम की यूटिलिटी सेवाएं जैसे जल आपूर्ति और कूड़ा उठाव बंद कर दिया जाएगा।

20 से अधिक मामलों में वांछित भू-माफिया कुर्बान खान गिरफ्तार, भेजा गया जेल

PHOTON NEWS RANCHI : मंगलवार को पिठोरिया पुलिस ने भू-माफिया मोहम्मद कुर्बान उर्फ कुर्बान खान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। उलातू निवासी कुर्बान खान के खिलाफ जमीन से जुड़ी धोखाधड़ी के 20 से अधिक मामलों में गिरफ्तारी वारंट लंबित था। कुर्बान खान पर लोगों से जमीन दिलाने के नाम पर करोड़ों रुपये की ठगी का आरोप है। लंबे समय से वह पुलिस से बचते हुए रातू थाना क्षेत्र में छिपकर रह रहा था। पिठोरिया पुलिस ने न्यायालय द्वारा निर्गत गिरफ्तारी वारंट के आधार पर उसे गिरफ्तार किया।

सभी भू-माफिया को कड़ी चेतावनी : पुलिस ने गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए सभीभू-माफिया को कड़ी चेतावनी दी।

कहा कि जो भी व्यक्ति जमीन की अवैध खरीद-बिक्री, ठगी या जालसाजी में लिप्त पाए जाएंगे, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की इस कार्रवाई से क्षेत्र में अवैध जमीन कारोबार में संलिप्त लोगों में हड़कंप मच गया है।

पुराने और जीर्ण-शीर्ण अस्पताल भवनों का होगा कायाकल्प : अपर मुख्य सचिव

RANCHI : रांची के प्रसिद्ध चिकित्सा महाविद्यालय रिम्स के साथ राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों के पुराने और जीर्ण भवनों का कायाकल्प होगा। कंडेम घोषित भवन ध्वस्त होंगे और जिन भवनों में मरम्मती की जरूरत होगी उनकी मरम्मती की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव ने मंगलवार को अजय कुमार सिंह ने इस संबंध में रिम्स के साथ साथ सभी मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों को तीन दिन में कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। पत्र के माध्यम से अपर मुख्य सचिव ने रिम्स के साथ साथ सभी मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों को निर्देश देते हुए कहा है कि जमशेदपुर जैसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो।

शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी समस्याओं को लेकर छात्रों ने किया प्रदर्शन

PHOTON NEWS RANCHI : झारखंड में शिक्षा व्यवस्था की बदहाली और लंबे समय से लंबित मांगों को लेकर मंगलवार को ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन झारखंड राज्य कमेटी के नेतृत्व में राज्यभर के सैकड़ों छात्र-छात्राओं ने राजधानी रांची में प्रदर्शन किया। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से शुरू होकर यह जुलूस राजभवन तक पहुंचा, जहां छात्रों ने मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी मांगों को रखा। छात्र प्रतिनिधियों ने सरकार को चेतावनी दी कि अगर मांगे जल्द पूरी नहीं हुईं, तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। बिरसा मुंडा के सपनों का झारखंड कब बनेगा, जेटेट परीक्षा कब होगी, शिक्षा का निजीकरण

बंद करो जैसे नारे लगाए गए। मुख्य वक्ता एआईडीएसओ, केंद्रीय परिषद कोषाध्यक्ष शमशुल आलम ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को छात्रों और शिक्षकों के लिए घातक बताया। प्रदेश अध्यक्ष समर महतो और सचिव सोहन महतो ने झारखंड की स्थापना के 24 वर्ष बाद भी शिक्षा क्षेत्र में भारी कमियों की ओर इशारा करते हुए कहा कि राज्य के पास देश के 40% खनिज संसाधन होने के बावजूद शिक्षा की हालत बेहद चिंताजनक है। प्रदर्शन में कोल्हान, रांची, पश्चिमी सिंहभूम समेत कई जिलों के छात्र शामिल हुए।

जानकी नवमी पर 51 कुंवारी कन्याओं का हुआ पूजन

RANCHI : मंगलवार को अंतरराष्ट्रीय मैथिली परिषद के तत्वावधान में मां जानकी के प्राकट्य दिवस पर कोकर वार्ड संख्या 6 के पार्षद कार्यालय न्यू नगर, बांधगाड़ी में भव्य जानकी पूजनोत्सव का आयोजन किया गया। पूजा की शुरूआत वैदिक विधि से मूर्ति प्राण-प्रतिष्ठा एवं पूजन के साथ हुई, जिसे आचार्य पंडित उमा शंकर झा और यजमान किरण पाठक ने संपन्न कराया। मां भारतेश्वरी को खीर, पचमेर, फल आदि का भोग अर्पित किया गया। इसके उपरांत 51 से अधिक कुंवारी कन्याओं का विधिवत पूजन कर उन्हें भोजन कराया गया, जो मां जानकी के प्रतीक स्वरूप मानी जाती हैं। वहीं देर शाम सांस्कृतिक संध्या 4 बजे से शुरू हुई। जिसमें रूपा चौधरी और निभा झा ने मैथिली सोहर व पारंपरिक गीतों से वातावरण को भक्तिमय बना दिया।

रांची नगर निगम की बस सेवा को अपग्रेड करने के प्लान पर तेजी से हो रहा काम

राजधानी के लोगों को मिलेगी डबल डेकर बस की सेवा

PHOTON NEWS RANCHI : नगर निगम की ओर से जल्द ही शहर में पुरानी बसों को हटाकर नई एसी डबल डेकर बस और 19 एसी इलेक्ट्रिक बसों के साथ-साथ 220 नॉन एसी डीजल बसों की सुविधा शहर वासियों के लिए दी जाएगी। इसे लेकर नगर निगम में टेंडर की प्रक्रिया जारी है।

टेंडर प्रक्रिया में नोएडा, दिल्ली और पुणे की ट्रैवल एजेंसियों ने हिस्सा लिया है। टेक्निकल पहलुओं को लेकर जानकारी ली गई है। अब इन एजेंसियों को वित्तीय संबंधित दस्तावेजों की जांच करानी होगी। यह जानकारी रांची नगर निगम के नगर आयुक्त संदीप सिंह ने दी। नगर आयुक्त ने बताया कि इन बसों की खरीदारी, मालिकाना हक, संचालन और मेंटेनेंस की जिम्मेदारी कंपनियों के ऊपर ही होगी।

स्मार्ट बस डिपो का होगा निर्माण

राजभवन के समीप नागा बाबा खटाल क्षेत्र में 2,93,38,032 रुपये की लागत से इनर सिटी बस डिपो का निर्माण कराने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए टेंडर की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। इस बस डिपो को भी अत्याधुनिक सुविधाओं और वाई-फाई से लैस किया जाएगा। यात्री सुविधा का ध्यान रखते हुए तमाम पहल की जाएगी।

प्रतीकात्मक फोटो

बस ऑपरेटर का चयन और किराया निर्धारण : नगर आयुक्त ने बताया कि बस ऑपरेटर का चयन और किराया का निर्धारण रांची निगम द्वारा ही किया जाएगा। बसों के परिचालन के लिए रूट का चयन किया जा रहा है। शहर के विभिन्न चौक-चौराहों पर यात्री शेड का भी निर्माण एक बार फिर किया जाएगा।

इन रूटों से होकर गुजरेंगी बसें

रांची नगर निगम प्रबंधन से मिली जानकारी के अनुसार किशोरी यादव चौक से रामपुर, किशोरी यादव चौक से ओरमांझी, किशोरी यादव चौक से नगड़ी, किशोरी यादव चौक से मांडर, पिठौरिया, तुपुदाना, हटिया, कांटाटोली, बूटी मोड़, पटेल चौक, बूटी मोड़ से एयरपोर्ट, कांटाटोली चौक से एयरपोर्ट, रामपुर से मेसरा आउटर रिंग रोड होते हुए संचालित होंगी। बसों के परिचालन के लिए कुल 13 रूट चिन्हित किए गए हैं।

मुरतो पंचायत भवन में हुई समीक्षा बैठक

RANCHI : मंगलवार को बेड़ो प्रखंड के मुरतो पंचायत भवन में साप्ताहिक समीक्षा बैठक हुई, जिसमें मनरेगा, आवास योजना सहित अन्य विकास योजनाओं की बारीकी से समीक्षा की गई। अध्यक्षता कर रहे प्रखंड विकास पदाधिकारी राहुल उरांव ने अधिकारियों ने कहा कि मजदूरों को काम देकर ही क्षेत्र में सतत विकास सुनिश्चित किया जा सकता है। बैठक के बाद बीडीओ राहुल उरांव व प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी संजय तिर्की के नेतृत्व में डारकंदरिया ग्राम के गिरधारी उरांव के आम बागवानी योजना के अंतर्गत गड्ढा खुदाई कार्य का विधिवत शुभारंभ किया गया, जिसमें बीडीओ ने स्वयं गड्ढा खोदकर पहल की। बैठक के दौरान बीडीओ ने स्पष्ट निर्देश दिया कि अबुआ आवास एवं प्रधानमंत्री आवास योजना में शत-प्रतिशत लक्ष्य पूर्ति सुनिश्चित की जाए और सभी आवास निर्माण कार्य समयबद्ध रूप से पूर्ण हों।

जीजा के घर शादी में आई युवती की गोली लगने से मौत, जांच में जुटी पुलिस

PHOTON NEWS RANCHI : अपने जीजा के घर रांची के मांडर आई एक 21 वर्षीय युवती अनिता खलखो की फायरिंग में मौत हो गई है। गोली चलाने वाला युवक मृत युवती का पूर्व परिचित है। पुलिस हत्या और हर्ष फायरिंग दोनों ही बिंदुओं पर मामले की जांच कर रही है। गोली लगने के बाद युवती की रिम्स में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान मंगलवार को उसकी मौत हो गई है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार अनिता चान्हो से अपनी बहन और जीजा के घर एक शादी समारोह में भाग लेने की लिए आई हुई थी। इसी दौरान दीपक नाम के एक युवक द्वारा की गई फायरिंग में उसकी मौत हो गई। घटना सोमवार की आधी रात की है। बताया जा रहा है कि शादी समारोह में भाग लेकर अनिता अपने बहन के घर लौट आई थी। इसी दौरान दीपक उसके पास पहुंचा थोड़ी ही देर बाद गोली चलने की आवाज आई। जब परिजन मौके पर पहुंचे तो देखा कि अनिता के सिर के पास गोली लगी हुई है और वह जमीन पर पड़ी हुई है। वहीं दीपक उस दौरान फरार हो गया। घायल अनिता को रांची के रिम्स में भर्ती कराया गया, लेकिन मंगलवार की सुबह इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मांडर थाना प्रभारी राहुल कुमार ने बताया कि जिस युवक पर अनिता की हत्या का आरोप लगा है वह मांडर का ही रहने वाला है और अनिता के बहनोई का बेहद करीबी दोस्त है। थाना प्रभारी के अनुसार अनिता और गोली मारने वाले के बीच किसी तरह का कोई संबंध भी नहीं था, लेकिन किन परिस्थितियों में गोली चली और हथियार कहां से आया इसकी जांच की जा रही है।

चाकुलिया से जारी 4281 बर्थ सर्टिफिकेट होंगे रद्द, एसआईटी कर रही गहन जांच

पंचायत सचिव समेत पांच लोगों को भेजा गया जेल, गलत मंशा से जन्म प्रमाणपत्र बनवाने वाले लोगों पर भी होगी कार्रवाई

PHOTON NEWS JSR : पूर्वी सिंहभूम जिले के चाकुलिया प्रखंड में बड़े पैमाने पर फर्जी जन्मप्रमाण पत्र घोटाले का खुलासा हुआ है। इस मामले में जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए चाकुलिया प्रखंड से जारी किए गए 4281 फर्जी जन्म प्रमाणपत्रों को रद्द करने का आदेश दिया है। उपायुक्त अनन्य मित्तल ने इन प्रमाण पत्रों को तुरंत रद्द करने का निर्देश रजिस्ट्रार को दिया है। इसके साथ ही उन्होंने इन प्रमाण पत्रों की सार्वजनिक सूची जारी करने को कहा है, ताकि अन्य विभाग भी इनकी जांच कर सकें और यह सुनिश्चित किया जा सके कि इनका दुरुपयोग किसी सरकारी योजना का लाभ लेने में तो नहीं हुआ। फजीर्वाड़े की जांच के लिए विशेष जांच टीम (एसआईटी) का गठन किया गया है, जिसमें ग्रामीण एसपी ऋषभ गर्ग के नेतृत्व में दो डीएसपी, दो इंस्पेक्टर और एक सब-इंस्पेक्टर शामिल हैं। एसएसपी किशोर कौशल ने बताया कि फर्जी प्रमाणपत्र बनाने में शामिल लोगों की लंबी सूची तैयार की जा रही है। सोनारी के एक व्यक्ति की संलिप्तता भी सामने आई है। इस घोटाले में पंचायत सचिव सुनील महतो सहित पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। गिरफ्तार अन्य लोगों में मटियाबांधी और मालकुंडी पंचायत के प्रज्ञा केंद्र संचालक शिवम डे और सपन महतो, बिचौलिया बुंडू (रांची) के हरीश प्रमाणिक और रांची के आरिफ आलम शामिल हैं। जन्म प्रमाणपत्र बनाने में इस्तेमाल हुए कंप्यूटर और अन्य उपकरण भी जब्त कर लिए गए हैं।

पुलिस गिरफ्त में आरोपी व पत्रकारों को पूरे मामले की जानकारी देते डीसी अनन्य मित्तल व एसएसपी किशोर कौशल ● फोटोन न्यूज

स्कूल एडमिशन से हुआ मामले का खुलासा

जांच की शुरूआत तब हुई जब निजी स्कूलों में दाखिले के लिए जमा किए गए जन्म प्रमाणपत्रों की सत्यता को लेकर डीसी कार्यालय ने जांच कराई। चाकुलिया बीडीओ को भेजे गए 149 प्रमाण पत्रों में से 106 फर्जी पाए गए। इनमें कई मुस्लिम नामों से बनाए गए प्रमाणपत्र भी शामिल थे, जबकि मटियाबांधी पंचायत में मुस्लिम आबादी नहीं है। इसके बाद एसडीओ घाटशिला के नेतृत्व में टीम बनाई गई और बड़ी संख्या में फर्जी प्रमाणपत्र सामने आए।

3874 प्रमाणपत्र बहुसंख्यकों के नाम पर

एसएसपी किशोर कौशल के अनुसार, बनाए गए फर्जी प्रमाण पत्रों में से 3874 बहुसंख्यक समुदाय के हैं, जबकि 682 प्रमाण पत्र अल्पसंख्यकों के नाम पर बने हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल अल्पसंख्यकों के फर्जी प्रमाणपत्र बनवाने की बात ठीक नहीं है।

अभिभावकों पर भी होगी कार्रवाई

जिन अभिभावकों ने गलत मंशा से ये फर्जी प्रमाणपत्र बनवाए हैं, उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कुछ मामलों में आवेदनकताओं को यह जानकारी नहीं थी कि उनका प्रमाणपत्र किस तरह से जारी किया गया, लेकिन जिन्होंने जानबूझ कर उम्र घटाकर स्कूल में दाखिला दिलाने के उद्देश्य से प्रमाण पत्र बनवाए हैं और उनका अन्य योजनाओं में लाभ उठाया गया है, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा।

पोटका में हथियारबंद लुटेरों ने पेट्रोल पंप से लूटे ₹ 30 हजार

सीसीटीवी फुटेज में कैद अपराधी ● फोटोन न्यूज

JAMSHEDPUR : पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका थाना क्षेत्र अंतर्गत हल्दीपोखर के पास स्थित एचपी पेट्रोल पंप पर सोमवार सुबह करीब 9 बजे हथियारबंद अपराधियों ने धावा बोल दिया। तीन की संख्या में पहुंचे इन अपराधियों के हाथों में पिस्तौल थी। मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए लुटेरों ने पेट्रोल पंप के कर्मचारी को पिस्तौल दिखाकर डराया और करीब 30 हजार रुपये नकद लूट लिए। घटना को अंजाम देने के बाद तीनों अपराधी आसानी से मौके से फरार हो गए। बताया जाता है कि यह पेट्रोल पंप पूर्व मुख्यमंत्री के रिश्तेदार का है, इसलिए पुलिस पर अनायास दबाव बढ़ गया है। घटना की सूचना मिलते ही पोटका थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि पूरी वारदात पेट्रोल पंप में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है, जिसकी मदद से पुलिस आरोपियों की पहचान में जुटी है। हालांकि अभी तक किसी भी अपराधी की शिनाख्त नहीं हो सकी है। पुलिस ने आसपास के थानों से भी संपर्क किया है और ओडिशा की ओर भागने की आशंका के आधार पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय सूचना के आधार पर जल्द ही अपराधियों को पकड़ लिया जाएगा। क्षेत्र में इस तरह की वारदात ने लोगों में दहशत का माहौल बना दिया है।

समाचार सार

जाति जनगणना पर 9 को झामुमो का प्रदर्शन

CHAIBASA : झारखंड में सरना-आदिवासी धर्म कोड के बिना जाति जनगणना नहीं होने दिया जाएगा। झामुमो, केंद्रीय समिति के निदेर्शानुसार

9 मई को सभी जिला मुख्यालय में केंद्र सरकार के खिलाफ धरना-प्रदर्शन किया जाएगा। ये बातें झामुमो के जिला प्रवक्ता बुधराम लागुरी ने कहीं। लागुरी ने कहा कि 5 वर्ष पूर्व सरना-आदिवासी धर्म कोड विधेयक को झारखंड विधानसभा से पारित कराकर राज्यपाल के माध्यम से केंद्र सरकार के पास अनुमोदन के लिए भेजा गया था, परंतु केंद्र सरकार ने इस पर कोई निर्णय नहीं लिया है।

पं. रघुनाथ मुर्मू की धूमधाम से मनी जयंती

CHAKRADHARPUR : पोटका स्थित आदिवासी मित्र मंडल में

मंगलवार को ओलचिकी लिपि के जनक गुरु गोमके पं. रघुनाथ मुर्मू की जयंती मनाई गई। इस मौके पर संथाली ड्रामा भी हुआ। खेरवार गांवता पोटका के तत्वावधान में हुए कार्यक्रम में सांसद जोबा मांझी भी उपस्थित थीं। सांसद ने पं. रघुनाथ मुर्मू की तस्वीर पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस मौके पर सांसद ने कहा कि जब तक अपनी भाषा, लिपि, परंपरा, संस्कृति रहेगी, तब तक हमारी पहचान और अस्तित्व बना रहेगा। इस अवसर पर झामुमो के प्रखंड अध्यक्ष सन्नी उरांव, सचिव ताराकांत सिजुई, गोपीनाथपुर पंचायत के मुखिया सेलाय मुंडा, मोतीलाल मुर्मू, सीआर महाली, सुशील किस्कू, बबलू किस्कू, राम माझी, सुखलाल मुर्मू, सावन माझी समेत काफी संख्या में स्थानीय महिला-पुरुष उपस्थित थे।

एसडीओ से मिले माझी बाबा व पारगाना

GHATSILA : पारंपरिक माझी बाबा, तोरोफ पारगाना व घाट पारगाना

मंगलवार को एसडीओ, घाटशिला से मिले। उन्होंने ज्ञापन सौंपकर बताया कि धाड़ दिशोम देश पारगाना बैजू मुर्मू द्वारा सुधीर सोरेन व बहादुर सोरेन के बारे में जो शिकायत की थी, वह निराधार है। सुधीर सोरेन व बहादुर सोरेन समाजसेवी हैं। इस मौके पर पूर्व देश पारगाना स्व. हरेंद्रनाथ मुर्मू की पुत्रवधू डुमनी मुर्मू, दुर्गा मुर्मू, मेर मुर्मू राजेंद्र प्रसाद टुडू, सिमल सोरेन, रामधन सोरेन, विक्रम हांसदा, रामचंद्र माझी आदि उपस्थित थे।

क्रिकेट में संत जेवियर्स इंग्लिश स्कूल जीता

CHAIBASA : गौरव कुमार पान (71 रन) और अमनदीप चातर (53

रन) की शानदार बल्लेबाजी की बदौलत संत जेवियर्स इंग्लिश स्कूल चाईबासा ने मधुसूदन पब्लिक स्कूल आसनतलिया को 63 रनों से पराजित कर लगातार दूसरी जीत दर्ज की। पहले बल्लेबाजी करते हुए संत जेवियर्स इंग्लिश स्कूल ने 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 170 रन बनाए। जबाबी पारी खेलने उतरी मधुसूदन पब्लिक स्कूल की टीम 19.5 ओवर में 107 रन बनाकर ऑलआउट हो गई। आदित्य राज ने शानदार गेंदबाजी करते हुए मात्र 22 रन देकर 7 बल्लेबाजों को आउट किया। आदित्य राज को शानदार गेंदबाजी के लिए मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला।

ट्रैक्टर की चपेट में आकर एक व्यक्ति की मौत

CHAIBASA : पश्चिमी सिंहभूम जिले के तांतनगर ओपी क्षेत्र में ट्रैक्टर की चपेट में आकर एक व्यक्ति की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार, सोमवार को देर शाम तांतनगर ओपी क्षेत्र के टांगर पोखरिया पाटासई गांव निवासी 33 वर्षीय पुरनो पुरती एक ट्रैक्टर में बैठकर पांगा गांव से अपने गांव जा रहा था। रास्ते में बुरुसाइ के पास चलती ट्रैक्टर से अचानक गिर गया। जैसे ही वह ट्रैक्टर से गिरा, वह ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आ गया, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। मंगलवार को पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया।

हत्यारोपी को न्यायालय ने सुनाई 7 साल की सजा

CHAIBASA : पश्चिमी सिंहभूम जिले के आनंदपुर में पत्थर और लाठी-

डंडे से मार कर हत्या करने के आरोपी को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम के न्यायालय ने 7 साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा अदालत ने उस पर 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जानकारी के अनुसार, आनंदपुर थाना अंतर्गत लोरकोन्डा गांव के टोला झारियाडी निवासी रंथु ग्वाला के पुत्र अभियुक्त संजू ग्वाला ने 3 दिसंबर 2012 को किसी बात को लेकर गांव के ही सुरेश सिंह रोतिया को लाठी-डंडे और पत्थर से कुचल कर हत्या कर दी थी। बाद में उसके खिलाफ थाने में मामला दर्ज हुआ था।

पटेल बंधुओं के आवास पर जीएसटी ने की छापेमारी

घर के बाहर लगी अधिकारियों की कारें ● फोटोन न्यूज

CHAIBASA : पश्चिमी सिंहभूम जिला के मुख्यालय चाईबासा स्थित व्यापारी मनोज पटेल और मुन्ना पटेल के न्यू कॉलोनी नीमडीह स्थित आवास पर जीएसटी की टीम छापेमारी कर रही है। जानकारी के अनुसार, जीएसटी विभाग के 6 सदस्यों की टीम मनोज पटेल और उनके भाई मुन्ना पटेल के आवास पहुंची। इसके बाद घर से कोई न बाहर गया, ना अंदर। टीम के सदस्यों ने घर में कागजों की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बता दें कि मनोज पटेल का चाईबासा के हॉटगम्हरिया व राजनगर में क्रशर मशीन और राजनगर में राइस मिल भी है। इसी को लेकर जीएसटी में हेराफेरी करने का मामला सामने आने के बाद छापामारी की जा रही है। टीम कागजातों को खंगाल रही है। राइस मिल, गिट्टी, स्टोन क्रशर सहित विभिन्न व्यवसाय एवं निवेश व कारोबार से संबंधित कागजात और कंप्यूटर आदि डिजिटल साक्ष्य की जांच-पड़ताल की जा रही है। यहां बता दें कि चाईबासा में तीन दिन पूर्व झारखंड खैनी के पार्टनर नितिन प्रकाश, पंकज चिरानिया व पिंटू अग्रवाल के आवास और ठिकानों पर छापेमारी हुई थी।

सबर महिलाओं से ठग ली अबुआ आवास की राशि

GHATSILA : पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला प्रखंड में काड़ाडुबा पंचायत अंतर्गत कानीमोहली गांव की 9 सबर महिलाओं के अबुआ आवास के लिए मिली पहली किस्त की राशि 2.70 लाख की ठगी हुई है। सभी महिलाओं ने मंगलवार को प्रखंड कार्यालय में बीडीओ से लिखित शिकायत करने की बात कही। महिलाओं ने बताया कि नवीन कर्मकार नामक व्यक्ति ने गांव आकर बताया कि वह प्रखंड कार्यालय का कर्मचारी है। आवास बनाने की जिम्मेदारी उसे मिली है, इसलिए जो पहले किस्त की राशि मिली है, वह उसे दे दे। महिलाओं ने पहली किस्त की राशि 30 हजार रुपये बैंक से निकाल कर दे दिया। 5 माह बाद भी आवास का कार्य शुरू नहीं होने पर जब नवीन कर्मकार से पूछा गया, तो वह टालमटोल करता रहा। अबुआ आवास की लाभुक महिलाओं में मालावती सबर, लिलमनी सबर, पुष्पा सबर, किशोरी सबर, श्रीमती सबर, हुनू सबर, शुरूबाली सबर, सकुंतला सबर, मुगली सबर शामिल हैं।

तस्करी कर ले जाए जा रहे 20 गोवंश बरामद, तस्कर फरार

PHOTON NEWS CKP : चक्रधरपुर थाना की पुलिस के सहयोग से बजरंग दल के सदस्यों ने एक बार फिर पशु तस्करी रोकने में सफलता हासिल की है। इस बार 20 गोवंश को पकड़ कर चक्रधरपुर थाना में लाया गया है। हालांकि, पशु तस्कर भागने में सफल रहे। जानकारी के अनुसार, मंगलवार को चक्रधरपुर प्रखंड के पदमपुर से बांझीकुसुम होते हुए कुदलीबाड़ी के रास्ते पशु तस्कर पशु लेकर जा रहे हैं। इसे कुछ स्थानीय युवकों ने देखा। बाद में इसकी सूचना बजरंग दल के सदस्यों को दी। सूचना मिलते ही बजरंग दल के सदस्यों ने इसकी सूचना चक्रधरपुर थाना को दी। इसके बाद पुलिस के साथ बजरंग दल के सदस्यों ने छापामारी अभियान चलाया। मंगलवार सुबह चक्रधरपुर थाना क्षेत्र के रूंगसाई के पास पशु लेकर तस्करों को आते हुए देखा। तभी पुलिस ने धावा बोल दिया। हालांकि पशु तस्कर पुलिस को देखते ही फरार हो गए। गोवंश पकड़ाने की खबर आग की तरह फैल गई। इसके बाद मंगलवार को सुबह में ही विभिन्न गांवों से ग्रामीण आधार कार्ड लेकर चक्रधरपुर थाना पशु लेने पहुंच गए। बता दें कि पूर्व में चक्रधरपुर पुलिस कई बार पशुओं को पकड़ा था। बाद में पुलिस ने सभी पशु को चक्रधरपुर के किसानों को आधार कार्ड लेकर पकड़े गए पशु को निःशुल्क दे दिया था। बाद में इसे लेकर विवाद हो गया कि आधार कार्ड वाले ही पशु तस्कर हैं। इसलिए पुलिस अब गाय-बैल को चाकुलिया गौशाला भेजने की व्यवस्था कर रही है।

थाने में रखे गए गाय-बैल ● फोटोन न्यूज

मनोहरपुर में कार से जब्त की गई 25 पेटी अवैध शराब, एक हिरासत में

PHOTON NEWS MANOHARPUR : पश्चिमी सिंहभूम जिला के मनोहरपुर थाना की पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक कार से 25 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब जब्त की है। पुलिस ने कार चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर जेल भेज दिया। जानकारी के अनुसार, पुलिस को सोमवार को ही गुप्त सूचना मिली थी कि एक कार से अवैध विदेशी शराब की तस्करी होने वाली है। सूचना महत्वपूर्ण थी, इसलिए पुलिस ने एक टीम बनाकर वाहन चेकिंग अभियान चलाया।

इस संबंध में मनोहरपुर के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी जयदीप लकड़ा ने बताया कि वरीय अधिकारियो को गुप्त सूचना मिली थी कि जमशेदपुर से मनोहरपुर की ओर रात्रि में अवैध अंग्रेजी शराब की तस्करी की जा रही है। जब पुलिस ने रात 12 बजे रेलवे फाटक के समीप वाहन चेकिंग अभियान चलाया, तभी रात 1 बजे एक इनोवा कार रेलवे क्रॉसिंग होकर गुजरने लगी। चेकिंग कर रही पुलिस ने गाड़ी रोकने को कहा, तो गाड़ी चला रहा एम. वेंकटेश गाड़ी रोक कर भागने लगा। इसके बाद पुलिस ने उसे दौड़ाकर पकड़ा और गाड़ी चेक किया तो गाड़ी में 25 कार्टन में रखे गए करीब 300 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब जब्त किया। पुलिस ने गाड़ी जब्त कर आरोपी को पकड़ कर थाना लाया। यहां गहन पूछताछ करने पर उसने बताया कि टाटा के परसुडीह थाना के किताडीह निवासी राजेश प्रसाद नामक अवैध शराब के कारोबारी ने इस शराब को मनोहरपुर के होटल संचालक किशोर साहू के घर में उतारने को कहा था। इस मामले में पुलिस किशोर साहू के खिलाफ भी कार्रवाई कर रही है।

बरामद शराब के साथ पुलिस पदाधिकारी ● फोटोन न्यूज

बच्चियों में बांटे गए रियूजेबल सैनिटरी पैड

JAMSHEDPUR : जमशेदपुर स्थित केरूवाडुंगरी पंचायत स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय, भीतरदाढ़ी में मंगलवार को पंचायत स्तरीय जागरूकता अभियान की शुरूआत पंचायत के मुखिया कान्हु मुर्मू ने की। इस दौरान सामाजिक संस्था निश्चय फाउंडेशन के संस्थापक तरुण कुमार ने स्कूल की बच्चियों में रियूजेबल सैनिटरी पैड का वितरण किया। तरुण कुमार ने बच्चों व अभिभावकों को माहवारी स्वच्छता व बच्चों की शिक्षा से जुड़े कई अहम मुद्दों पर

संकोसाई में पानी की किल्लत से त्राहिमाम, हुआ प्रदर्शन

JAMSHEDPUR : जमशेदपुर के मानगो में संकोसाई लक्ष्मीनगर इलाके में पिछले एक महीने से पानी की सप्लाई पूरी तरह ठप है। हालात ऐसे हो चुके हैं कि लोग एक-एक बूंद पानी के लिए परेशान हैं। रोजाना जनप्रतिनिधियों के बयान पढ़कर लोगों को थोड़ी उम्मीद जरूर बनती है, लेकिन जमीनी हकीकत में अब तक कोई सुधार नहीं हुआ है। पानी की इस गंभीर समस्या से त्रस्त स्थानीय लोगों ने पूर्व भाजपा नेता विकास सिंह को मौके पर बुलाकर स्थिति से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि पिछले एक महीने से घरों की टोटियों से एक बूंद पानी नहीं आया है। लोगों ने जब पेयजल एवं स्वच्छता विभाग से संपर्क किया तो उन्हें मानगो नगर निगम जाने को कहा गया और जब वे नगर निगम पहुंचे तो वहां से फिर पेयजल विभाग लौटने की सलाह दी गई। इस तरह विभागों के चक्कर काटते-काटते लोग थक हार गए हैं। गली संकरी होने के कारण नगर निगम का पानी टैंकर भी नहीं पहुंच पाता है। पैसे वाले लोग तो किसी तरह टेंपो से पानी खरीद लेते हैं लेकिन मध्यमवर्ग और गरीब तबका इस व्यवस्था से पूरी तरह जूझ रहा है। थक-हार कर अब लोगों ने भगवान की शरण ली है।

नारेबाजी करते लोग ● फोटोन न्यूज

टाटा लीज की जमीन पर बने स्कूलों को सरकार से नहीं मिलेगी बच्चों की फीस

आरक्षित सीटों पर दाखिले के लिए हुई लॉटरी, पहली सूची में 1303 बच्चे

PHOTON NEWS JSR : शहर के निजी स्कूलों में राइट टू एजुकेशन के तहत आरक्षित 25 प्रतिशत सीट पर नामांकन के लिए मंगलवार को लॉटरी की प्रक्रिया उपायुक्त कार्यालय के समाहरणालय कक्ष में सभागार में हुई। इस दौरान सभी निजी विद्यालयों के प्राचार्य एवं अभिभावक संघ के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

सभी की उपस्थिति में एक-एक कर 43 वैसे विद्यालय, जिसमें निश्चित सीट से अधिक संख्या में फार्म प्राप्त हुए थे। उनमें लॉटरी कर सूची को अंतिम रूप दिया गया। वहीं अन्य 22 विद्यालय, जिसमें कम संख्या में फॉर्म प्राप्त हुए थे। उनका भी प्रक्रिया पूर्ण किया गया सभी विद्यालयों को एक लॉगिन आईडी पासवर्ड उपलब्ध कराया गया, जिसके आधार पर अगले 7 दिनों में नामांकन की प्रक्रिया ऑनलाइन पूर्ण करेंगे। शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, 1524 सीटों के विरुद्ध 1303 सीटों पर प्रथम चरण में नामांकन के लिए सूची बनाई गई। नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद दूसरी मेधा सूची जारी होगी। जिन बच्चों का दाखिला होगा, वे 8वीं कक्षा तक निःशुल्क पढ़ाई कर सकेंगे। वहीं इस नामांकन के बदले निजी स्कूलों को प्रति छात्र 425 रुपये की दर से फीस का भुगतान हर महीने सरकार की ओर से की जाएगी। हालांकि, जो स्कूल टाटा लीज की जमीन पर स्थित हैं उन्हें फीस नहीं मिलेगा।

डीसी ऑफिस पर नारेबाजी करते अभिभावक ● फोटोन न्यूज

बीपीएल बच्चों से हर साल आय प्रमाणपत्र मांगने पर स्कूल की शिकायत

अभिभावक संघ उपायुक्त से मिलकर एडीएलएस सनसाइन स्कूल कदमा के प्रबंधन के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की मांग की है। मंगलवार को डीसी को ज्ञापन सौंपते हुए संघ की ओर से बताया है कि एडीएलएस सनसाइन स्कूल प्रबंधन द्वारा प्रत्येक वर्ष नामांकन प्राप्त सभी बीपीएल वर्ग के बच्चों से हर वर्षा बीपीएल आय प्रमाण पत्र की मांग की जाती है और नहीं देने पर प्रबंधन द्वारा बच्चों को सामान्य वर्ग की तरह फीस देने का दबाव बनाया जाता है। इसके साथ ही उन्हें स्कूल से निष्कासित करने की धमकी भी दी जाती है। इस संदर्भ में जमशेदपुर अभिभावक संघ के अध्यक्ष का कहना है कि आरटीआई अधिनियम 2009 की धारा-13 के प्रावधान में कोई विद्यालय या व्यक्ति किसी बालक को प्रवेश देते समय कोई प्रति व्यक्ति फीस संग्रहित नहीं करेगा और बालक या उसके माता-पिता अथवा संरक्षक को किसी अनुवीक्षण प्रक्रिया के अधीन नहीं रखेगा। धारा 16 किसी विद्यालय में प्रवेश प्राप्त बालक को किसी कक्षा में रोका नहीं जाएगा।

मिट्टी की दीवार गिरने से एक की मौत

GHATSILA : पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत गालूडीह थाना क्षेत्र के बाघुड़िया गांव में मंगलवार की शाम मिट्टी की दीवार गिरने से 42 वर्षीय विश्वनाथ टुडू की मौत हो गई। परिवार के लोगों ने तत्काल उठाकर अनुमंडल अस्पताल, घाटशिला लेकर पहुंचे। अनुमंडल अस्पताल की चिकित्सक डॉ. हेना रानी ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। घटना के संबंध में मृतक की पत्नी रुक्मिणी टुडू ने बताया कि मिट्टी की दीवार के पीछे ईंट की दीवार बन रही थी। मंगलवार शाम को आई तेज आंधी-पानी में दीवार भरभरा कर पति के ऊपर गिर गई, जिससे उनकी मौत हो गई।

BRIEF NEWS

डंपर की टक्कर से युवक की मौत लोगों में आक्रोश

NALANDA : नालंदा जिले छविलापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत छविलापुर बाजार में मंगलवार को एक तेज रफ्तार डंपर ने युवक को कुचल दिया जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान सिलाव थाना क्षेत्र के बरनौसा गांव निवासी 18 वर्षीय आदित्य कुमार पिता मिथिलेश रविदास के रूप में हुई है।घटना के संबंध में प्रत्यक्षदर्शियों नें बताया कि आदित्य बाजार में किसी कार्य से आया था और सड़क पार कर रहा था तभी छविलापुर बाजार की ओर से तेज गति में आ रहे हाइवा ने उसे टक्कर मार दी। हादसे के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया। घटना के बाद गुस्साए स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया।

होटल के कमरे से संदिग्ध स्थिति में युवक का शव बरामद

BHAGALPUR : जिले के जोगसर थाना क्षेत्र स्थित भावना होटल के कमरे नंबर 101 से मंगलवार को पिरपैंती निवासी तुषार ठाकुर का फंदे से लटका हुआ शव बरामद किया गया है। युवक रविवार शाम को अपने घर से निकला था लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटने पर परिजन ने उसकी खोजबीन शुरू की और पिरपैंती थाना को इसकी सूचना दी। थाना की ओर से कुछ देर इंतजार करने की बात कही गई। लेकिन जब परिजन ने युवक के मोबाइल का लोकेशन ट्रैक किया तो लोकेशन भावना होटल का मिला। परिजन जब होटल पहुंचे तो रजिस्टर में युवक की एंट्री कल दोपहर दो बजे की पाई गई। जब परिजन होटल स्टाफ के साथ कमरे तक पहुंचे तो कमरा अंदर से बंद मिला। गेट तोड़ने के बाद देखा गया कि युवक का शव बेडशीट के सहारे फंदे से लटका हुआ था।

मृतक व्यवसायी के परिजन से मिला राजद प्रतिनिधिमंडल

BHAGALPUR : राष्ट्रीय जनता दल का एक प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को मृतक विनय गुप्ता के पिता विश्वनाथ गुप्ता से जाकर उनके आवास पर मुलाकात की। उल्लेखनीय है कि बीते रविवार देर रात नवगछिया बाजार में किराना व्यवसाई विनय गुप्ता की हत्या अपराधियों ने गोली मारकर कर दी थी। इस मौके पर बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉ चक्रपाणि हिमांशु ने नवगछिया बाजार के हरिया पट्टी में किराना दुकानदार विनय गुप्ता की हत्या की निंदा करते हुए शोक व्यक्त किया एवं परिजन के प्रति संवेदना व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि विनय गुप्ता के हत्यारे को अविलंब गिरफ्तार कर उसे कड़ी से कड़ी सजा बिहार सरकार दे। मृतक के परिजनों को कम से कम 10 लाख रुपया का मुआवजा एवं आश्रित को नौकरी मिलनी चाहिए। साथ ही मृतक के परिवार को पुलिस सुरक्षा मुहैया कराया जाए।

खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 18 वर्ष से कम उम्र के 8500 खिलाड़ियों ने लिया भाग

AGENCY NALANDA : बिहार के नालंदा जिले के पर्यटक स्थल राजगीर खेल परिसर में आयोजित मैच प्रतिस्पर्धा में खेलों की रौनक देखते ही बन रही है। जहां18 वर्ष से कम उम्र के 8500 खिलाड़ियों ने भाग लिया है।

खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आगाज राजगीर में 4 मई को रंगारंग और भव्य उद्घाटन समारोह के साथ हुआ था। प्रधानमंत्री द्वारा भी वर्चुअल माध्यम से इसका उद्घाटन किया गया था। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार केंद्रीय खेल मंत्री और केंद्रीय राज्य मंत्री भी मौजूद रहे थे। इस खेल महोत्सव में 18 साल से कम उम्र के 8500 से अधिक बालक-बालिकाएं 28 खेलों में

करीब 2400 से ज्यादा पदकों के लिए मैदान में उतर गयी है।यहां अंतरराष्ट्रीय स्तर के शानदार स्विमिंग पूल और विभिन्न खेलों के लिए आधुनिक स्टेडियम बनाए गए हैं। पिछले दिनों राजगीर में महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन किया गया था।

इसी सफलता को देखते हुए हॉकी इंडिया ने पुरुषों के हॉकी एशियन चैपियनशिप के आयोजन का उत्तरदायित्व और मेजबानी भी बिहार को मिल गई है। यह आयोजन 29 अगस्त से 7 सितंबर 2025 तक चलेगा। वहीं खेलो इंडिया की बात करें तो मेजबान राज्य बिहार से करीब 700 खिलाड़ियों की एक मजबूत टीम इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही है। खेलों की शुरूआत जोशभरे मुकाबलों से हुई है। जहां वॉलीबॉल में पश्चिम बंगाल ने राजस्थान को कड़े मुकाबले में हराया। वहीं जम्मू-कश्मीर ने उत्तराखंड को हराकर अपनी ताकत दिखाई। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के माध्यम से बिहार में खेल संस्कृति को बढ़ावा मिला है।

जिलाधिकारी ने बैडमिंटन कोर्ट हॉल का लिया जायजा

BHAGALPUR : खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अंतर्गत भागलपुर के सैंडिश मैदान में तीरंदाजी प्रतियोगिता चल रही है। 10 मई से बैडमिंटन प्रतियोगिता सैंडिस कंपाउंड के बैडमिंटन कोर्ट हाल में आयोजित किया जाना है। बैडमिंटन प्रतियोगिता की व्यवस्था में कोई कमी ना रहे इसको लेकर जिलाधिकारी डॉ० नवल किशोर चौधरी द्वारा मंगलवार को संबंधित पदाधिकारी के साथ बैडमिंटन कोर्ट हॉल का निरीक्षण किया गया। उन्होंने कोर्ट हाल के बाहरी दीवार पर खेलो इंडिया का पोस्टर बैनर लगाने, कोर्ट हाल के पश्चिम के खाली भाग को सजाने, संवारने, रंग रोगन करवाने का निर्देश नगर निगम भागलपुर तथा डीआरडीए भागलपुर को संयुक्त रूप से दिया। उन्होंने हाल के अंदर प्रकाश की व्यवस्था, कूलिंग की व्यवस्था को देखा साथ ही आवाज की प्रतिध्वनि को कम करने करने के लिए कार्यपालक अभियंता भवन प्रमंडल भागलपुर को निर्देशित किया। बैडमिंटन कोर्ट हाल में बने वॉश रूम और चेंजिंग रूम का अवलोकन किया। उन्होंने बैडमिंटन कोर्ट हाल के अंदर खेलो इंडिया यूथ गेम्स का ब्रांडिंग करने के लिए अधिकृत एजेंसी को निर्देशित किया। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित पदाधिकारी को आज से ही युद्ध स्तर पर कार्य करने का निर्देश दिया। इस अवसर पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्षु पदाधिकारी जतिन कुमार, के. परीक्षित, संयुक्त निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, जिला निलाम पत्र पदाधिकारी सुधीर कुमार, जिला खेल पदाधिकारी जय नारायण सिंह, कार्यपालक अभियंता भवन, डीआरडीए डायरेक्टर दुर्गा शंकर प्रसाद आदि मौजूद थे।

चांदपुर चौक के पास मक्का का ढेर देखकर तेज रफ्तार गाड़ी ने खोया संतुलन

बारातियों से भरे वाहन की ट्रैक्टर से टक्कर, 9 लोगों की गई जान

AGENCY KATIHAR : बिहार के कटिहार जिले में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। जिले के पोठिया थाना क्षेत्र के एस एच 77 सड़क पर चांदपुर हनुमान मंदिर के पास सोमवार की रात ट्रैक्टर और बारातियों से भरी स्कॉर्पियो के बीच भीषण टक्कर हो गई। इसमें स्कॉर्पियो सवार आठ लोगों की मौत मौके पर ही हो गई, जबकि इस हादसे में घायल दो लोगों में से एक की मौत इलाज के दौरान हो गयी। घायलों को इलाज के लिए समेली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया था। वहां से दो घायलों को रेफर कर दिया गया था। कटिहार एसपी वैभव शर्मा ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि पोठिया थाना अंतर्गत समेली में आठ लोगों की मौत हुई है, जबकि दो लोग घायल हैं। हादसा स्कॉर्पियो और ट्रैक्टर के बीच टक्कर की वजह से हुआ।

प्रारंभ में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हुआ इलाज

घटना के संबंध में बताया जाता है कि ढिबरा बाजार बड़हरा कोठी जिला पूर्णिया से स्कॉर्पियो पर 10 व्यक्ति सवार होकर कुसेला के नजदीक कोशकीपुर बारात जा रहे थे। चांदपुर पश्चिमी पंचायत के चांदपुर चौक के पास मक्का का ढेर देखकर तेज रफ्तार स्कॉर्पियो असंतुलित होकर आगे मक्के से लदे ट्रैक्टर से जा टकराया। इस हादसे में आठ लोगों की मौत घटनास्थल पर हो गई, जबकि एक घायल की मौत इलाज के दौरान हुई। घायलों का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र समेली में किया गया, लेकिन हालत गंभीर होने के कारण दोनों को रेफर कर दिया गया था।

सड़क हादसे में मृतकों की सूची

- प्रिंस कुमार, 20 वर्ष, पिता- पृथ्वी मंडल, ग्राम-दिबरा गोड़ियारी
- ज्योति कुमार, 16 वर्ष, पिता- शंकर मंडल
- शिको कुमार, 25 वर्ष, पिता- मंटू मंडल
- अजय कुमार, 25 वर्ष पिता- स्व करमचंद मंडल
- टुनटुन मंडल, 28 वर्ष, पिता- बांसो मंडल
- रुपेश मंडल, 12 वर्ष पिता- सतीश मंडल
- धीरज पोद्दार, 32 वर्ष पिता- पवन पोद्दार
- राधा मंडल, 36 वर्ष पिता- राजू मंडल, ग्राम-लतराहा। इन सभी की दर्दनाक मृत्यु घटनास्थल पर ही हो गई थी।
- उदय कुमार 25 वर्ष, पिता- रवींद्र मंडल की इलाज के दौरान हुई मौत।

दोपहर बाद हुई मृतकों की पहचान

स्थानीय लोगों की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों एवं मृतकों को लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र समेली पहुंची। घटना को लेकर रविवार की सुबह डीआईजी प्रमोद कुमार मंडल ने पांच लोगों की मौत होने की पुष्टि की थी। उन्होंने कहा कि विशेष विवरण जुटाया जा रहा है। वहीं समेली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात डॉ मुकेश ने बताया था कि हादसे में आठ लोगों की मौत हुई है, जबकि दो लोगों उदय कुमार (25 वर्ष) पिता रविन्द्र मंडल, तथा अभिषेक कुमार (26 वर्ष), पिता सिकलाल मंडल की हालत गंभीर होने के कारण दोनों को रेफर कर दिया गया है। दोपहर बाद सभी मृतकों की पहचान हो पायी।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जताया शोक

PATNA : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कटिहार जिले के कुसेला थाना क्षेत्र में हुए सड़क हादसे के मृतकों के प्रति गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने ने इस घटना को काफी दुखद बताया और शोक संतप्त परिवारों को दुख की इस घड़ी में धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। मुख्यमंत्री ने हादसे में घायल के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की है। हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक घायल है। घायल का इलाज पूर्णिया सदर अस्पताल में चल रहा है। यह दुर्घटना कुसेला थाना क्षेत्र के चांदपुर हनुमान मंदिर के पास उस वक्त हुई जब पूर्णिया जिले के रुपौली थाना क्षेत्र के ढिबरा गांव से एक बारात पूर्णिया के कोशकी पुर जा रही थी।

कृषि शिक्षा की थीम पर मंत्री श्रवण कुमार ने की पहल

AGENCY NALANDA : बिहार सरकार में जदयू कोटे से ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कृषि शिक्षा का बढावा देने के उद्देश्य से कृषि शिक्षा की थीम पर पहल कर दी है। वे मंगलवार को सिलाव प्रखंड स्थित रासबिहारी प्लस टू उच्च विद्यालय में करीब 24 लाख 98 हजार रुपए की लागत से बने साइकिल शेड, पीसीसी ढलाई और चारदीवारी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कृषि के क्षेत्र में छात्रों के लिए असीम संभावनाएं हैं जिसका उदाहरण विद्यालय की कक्षा 12वीं की कृषि छात्रा अराधना कुमारी ने दिया है। अराधना ने पूर्वी भारत विज्ञान मेले में जीरो वेस्ट एग्रीकल्चर मार्केटिंग पर प्रोजेक्ट के माध्यम से 12 राज्यों के प्रतिभागियों को पीछे छोड़ते हुए विद्यालय और जिले का नाम रोशन किया। मंत्री ने छात्रों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि राज्य सरकार छात्र-छात्राओं को साइकिल, पोशाक, छात्रवृत्ति सहित उच्च शिक्षा के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत चार लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध करा रही है ताकि उन्हें आगे की पढ़ाई में आर्थिक अड़चनों का सामना न करना पड़े। उन्होंने यह भी आश्वस्त किया कि छह महीने के भीतर विद्यालय में विज्ञान प्रयोगशाला का निर्माण कराया जाएगा और एक सप्ताह के भीतर विद्यालय में पानी की समस्या का स्थायी समाधान किया जाएगा।

कार्यक्रम में उपस्थित लोकसभा सांसद कौशलेंद्र कुमार ने कहा कि बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लगातार प्रगति की ओर बढ़ रहा है और राज्य सरकार के मॉडल को अन्य प्रदेश भी अपना रहे हैं। उन्होंने विद्यालय की समस्याओं की जानकारी प्रभारी प्रधानाध्यापक शैलेन्द्र प्रसाद से प्राप्त की और जल्द समाधान का आश्वासन दिया। प्रधानाध्यापक शैलेन्द्र प्रसाद ने जानकारी दी कि नवीन निर्माण कार्यों में चारदीवारी, साइकिल शेड, पीसीसी ढलाई शामिल है, जिससे विद्यार्थियों को सुविधा मिलने के साथ-साथ विद्यालय परिसर भी सुरक्षित हुआ है।

युद्धाभ्यास व ब्लैक आउट को लेकर जिला प्रशासन ने दी लोगों को जानकारी

AGENCY ARARIA : सिविल डिफेंस नागरिक सुरक्षा मंत्रालय, होमगार्ड आपदा प्रबंधन विभाग, दमकल विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस और जिला प्रशासन की ओर से बुधवार को युद्धाभ्यास किया जाएगा। युद्ध की तैयारी को लेकर आयोजित मॉकड्रिल हेतु बुधवार शाम 7 बजे से लेकर 10 मिनट के लिए अर्थात 7 बजकर 10 मिनट तक ब्लैकआउट रहेगा।सभी लाइट को बंद करके वॉर लाइट सिचुएशन से बचने की तैयारी की जाएगी।

ब्लैक आउट को लेकर अररिया डीएम अनिल कुमार ने मंगलवार को जिले के लोगों से अपील की है कि 7 बजे के बाद जब

बिजली काट दी जाएगी तो जेनरेटर या इनवर्टर का इस्तेमाल नहीं करे। कंपलीट ब्लैक आउट में सहयोग करे और इससे किसी तरह की डरने की आवश्यकता नहीं होने की बात उन्होंने कही। यह मॉकड्रिल युद्ध का प्रिपरेशन है न कि पैनिक। इसलिए सकारात्मक रूप से सभी को युद्धाभ्यास अर्थात मॉकड्रिल दौरान ब्लैक आउट में रोशनी का उपयोग न करके सहयोग की जिले के लोगों से अपील की। मॉकड्रिल के दौरान फायर ब्रिगेड और थानों की गाड़ियों की सायरन बजाया जाएगा।

वज्रपात से बिहार में पांच लोगों की मौत

NALANDA : बेमौसम की बारिश के दौरान वज्रपात से बिहार में हर दिन मौत हो रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान ही वज्रपात से पटना जिले में तीन, गया में एक और अरवल में एक व्यक्ति की मौत हुई है। पांच लोगों के मौत पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा की इस घड़ी में वे प्रभावित परिवारों के साथ हैं। मुख्यमंत्री ने आज ही मृतक के परिजनों को चार-चार लाख रुपए अनुग्रह अनुदान देने के निर्देश दिये हैं। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की है कि सभी लोग खराब मौसम में पूरी सतर्कता बरतें। खराब मौसम होने पर वज्रपात से बचाव के लिये आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये सुझावों का अनुपालन करें।

बिना सुरक्षा उपकरणों के जान जोखिम में डाल नाले को साफ कर रहे सफाईकर्मी

AGENCY BHAGALPUR : भागलपुर में नगर निगम के द्वारा लापरवाही बरतें जाने का मामला प्रकाश में आया है। नगर निगम द्वारा इन दिनों शहर में बड़े नालों की उड़ाही करवाई जा रही है लेकिन इस कार्य में लगे सफाईकर्मियों की सुरक्षा को पूरी तरह से नजर अंदाज किया जा रहा है। सफाई कार्य एजेंसी और नगर निगम के अधिकारी सफाईकर्मियों को न तो हेलमेट दे रहे हैं न दस्ताने और न ही सुरक्षा बूट। इन हालात में सफाईकर्मी जान जोखिम में डालकर बड़े-बड़े नालों में उतर रहे हैं। सफाई कर्मी के अध्यक्ष ने इस पर चिंता जताई है कि यदि किसी सफाईकर्मी के ऊपर

नाले का ढक्कन या कोई भारी वस्तु गिर गई तो बड़ा हादसा हो सकता है। बिना हेलमेट के नालों में घुसना जानलेवा साबित हो सकता है। अब सवाल उठता है कि क्या नगर निगम किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहा है? सफाईकर्मियों की सुरक्षा को लेकर जवाबदेही तय होनी चाहिए। साफ-सफाई जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी उन्हें बचाना है, जो शहर को साफ रखने में दिन-रात लगे हुए हैं।

वर्ल्ड लॉ कांग्रेस में 70 देशों के 1500 से अधिक विधिक क्षेत्र के दिग्गजों व 300 वक्ताओं ने लिया हिस्सा

वर्ल्ड ज्यूरिस्ट एसोसिएशन ने भुवन ऋभु को किया सम्मानित

AGENCY PATNA : प्रख्यात बाल अधिकार कार्यकर्ता और अधिवक्ता भुवन ऋभु को वर्ल्ड ज्यूरिस्ट एसोसिएशन ने प्रतिष्ठित मेडल ऑफ ऑनर पुरस्कार से सम्मानित किया। वर्ल्ड लॉ कांग्रेस में डोमिनिकन रिपब्लिक के श्रम मंत्री एडी ओलिवारेज ऑतेर्गा और वर्ल्ड ज्यूरिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष जेवियर क्रेमाडेस ने उन्हें 'मेडल ऑफ ऑनर' प्रदान किया। इस अवसर पर डोमिनिकन रिपब्लिक महिला विभाग की मंत्री मायरा जिमेनेज भी उपस्थित थीं। यह कांग्रेस 4 से 6 मई के बीच संपन्न हुई।

भुवन ऋभु यह अंतरराष्ट्रीय सम्मान पाने वाले पहले भारतीय

'मेडल ऑफ ऑनर' ग्रहण करते अधिवक्ता भुवन ऋभु

अधिवक्ता हैं। इस वर्ल्ड लॉ कांग्रेस में 70 देशों के 1500 से अधिक विधिक क्षेत्र के दिग्गजों व 300 वक्ताओं ने हिस्सा लिया, जहां कानूनी हस्तक्षेपों और जमीनी लामबंदियों के जरिए बच्चों और उनके अधिकारों की सुरक्षा की दिशा में दो दशक से जारी संघर्षों और उपलब्धियों के लिए भुवन ऋभु को सम्मानित किया।

पुरस्कार स्वीकार करते हुए भुवन ऋभु ने कहा, न्याय की लड़ाई में बच्चों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। कानून उनकी ढाल और न्याय उनका अधिकार होना चाहिए। डब्ल्यूजेए के अध्यक्ष जेवियर क्रेमाडेस ने कहा, भुवन ऋभु का दृढ़ता से मानना है कि न्याय लोकतंत्र का सबसे मजबूत खंभा है और उन्होंने पूरा जीवन देश में व पूरे विश्व में बच्चों और यौन हिंसा से पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए समर्पित कर दिया है।

वर्ष 1963 में स्थापित वर्ल्ड ज्यूरिस्ट एसोसिएशन दुनिया के विधिवेत्ताओं की सबसे पुरानी संस्था है, जिसने न्याय के शासन की स्थापना में अपने योगदान के लिए विंस्टन चर्चिल, नेल्सन मंडेला, रूथ बेडर गिन्सबर्ग, स्पेन के राजा फेलिप षष्टम, रेने कैसिन और कैरी कैनेडी जैसी ऐतिहासिक हस्तियों को सम्मानित किया है।

जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन (जेआरसी) के संस्थापक भुवन ऋभु के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में दायर 60 से ज्यादा जनहित याचिकाओं में कई ऐतिहासिक फैसले आए हैं, जिसने देश में बाल अधिकार व बच्चों की सुरक्षा का पूरा परिदृश्य बदल दिया है। बिहार में जेआरसी के 32 सहयोगी संगठन बाल अधिकारों की सुरक्षा व संरक्षण के लिए 38 जिलों में काम कर रहे हैं। संस्थाओं का उद्देश्य 2030 तक बाल विवाह को समाप्त करना है।

राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर जिला जज ने प्रचार वाहन को किया रवाना

AGENCY MOTIHARI : राष्ट्रीय एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निदेर्शानुसार 10 मई को होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता को लेकर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष देवराज त्रिपाठी एवं कुटुंब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश संदीप कुमार ने मंगलवार को न्यायालय परिसर से एक दर्जन प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किए। प्रचार वाहन शहर एवं सुदूर गांवों में राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रति लोगों को जागरूक करेंगा।

प्राधिकार के सचिव सह सब जज 6 श्वेता सिंह ने कही कि राष्ट्रीय लोक अदालत के सफलता को लेकर प्रचार के सभी माध्यमों के अलावे प्रखंड स्तर पर विधिक

जागरूकता शिविर लगा कर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। सुलह योग्य दीवानी व फौजदारी चेक बाउंस, राजस्व, मोटर वाहन दुर्घटना दावा, बैंक ऋण, वन, माप तौल, श्रमिक वाद, पारिवारिक विवाद सहित अन्य सुलहनीय मामलों का निस्तारण किया जाएगा। मौके पर न्यायाधीश मुकुंद कुमार, अवधेश कुमार सहित अन्य न्यायाधीश, अधिवक्ता एवं न्यायालय कर्मी उपस्थित थे।

टैंकर पर लदे गांजा समेत तस्कर गिरफ्तार सवा लाख नकद बरामद

EAST CHAMPARAN : जिले के चकिया थाना पुलिस ने गुप्त सुचना के आधार पर परसौनी खेम टोलप्लाजा के समीप वाहन जांच के दौरान एक तेल टैंकर से प्रतिबंधित मादक पदार्थ गांजा व लगभग सवा लाख रुपए के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया हैं। गिरफ्तार तस्कर मुजफ्फरपुर जिला के सरैया थाना के मुगौली गांव का शत्रुघ्न राय का पुत्र सोनू कुमार बताया जाता हैं। इसके पास से पुलिस ने पंद्रह किलो चार सौ ग्राम पैकेट में रखे गांजा, एक लाख इक्कीस हजार सात सौ तीस रुपया नगद, वीवो कंपनी का एक मोबाइल फोन तस्कर का आधार कार्ड व पैनकार्ड बरामद किया हैं।

दिखेगा बिहार का दमखम

विकास के साथ जिस सर्वसमावेशिता की बात आज विश्व बैंक से संयुक्त राष्ट्र तक हर मंच पर होती है, उसके लिए हो रहे प्रयास देश के संघात्मक ढांचे की नई चमक को जाहिर कर रहे हैं। इस लिहाज से सबसे दिलचस्प है खेलों की दिशा में राज्यों का शानदार प्रदर्शन। जिस आयोजन की आज पूरे देश में चर्चा है, वह है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025। इस बार यह अहम आयोजन न सिर्फ बिहार में हो रहा है बल्कि प्रदेश के पांच शहरों में इससे जुड़ी खेल प्रतियोगिताएं हो रही हैं। ये शहर हैं- पटना, राजगीर, भागलपुर, गया और बेगूसराय। बिहार जैसे सूबे में इतने महत्वपूर्ण राष्ट्रीय खेल आयोजन के मायने गहरे और बहुस्तरीय हैं। कुछ दशक पहले तक बिहार वैसे राज्यों में शुमार होता था, जिसके विकास की संभावनाओं पर लगातार नकारात्मक तरीके से विचार किया गया। दरअसल, इस पूरे संदर्भ का आगाज 1980 के दशक में तब हुआ, जब जनसांख्यिकी और आर्थिक नीतियों के विश्लेषक आशीष बोस ने तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी को एक रिपोर्ट सौंपी। बोस ने इस रिपोर्ट में देश के चार बड़े राज्यों बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य बताया, पर बीते दशकों में यह स्थिति लगातार बदली है। इस दौरान विकास को लेकर इन राज्यों के विकास का नया चरित्र उभरा है। बात अकेले उस सूबे की करें, जहां इस बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का मेगा आयोजन हो रहा तो यह इस सूबे की खेल संस्कृति और उस दिशा में हो रही प्रगति की ओर स्वभाविक तौर पर ध्यान ले जाता है। आज की तारीख में ऐतिहासिक विरासत, संस्कृति और बौद्धिक परंपराओं के लिए मशहूर बिहार खेल के क्षेत्र में नई पहचान बना रहा है। पिछले कुछ वर्षों में कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं की मेजबानी में बिहार का दमखम खासतौर पर दिखा है। बिहार की दृष्टि से यह बड़ा बदलाव है। खेलों की मेजबानी में बिहार को प्राथमिकता मिलने के पीछे कई अहम कारण हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य की सरकार ने बीते दो दशकों में स्टेडियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ट्रेनिंग सेंटर और आधुनिक खेल सुविधाओं के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया है। यही कारण है कि राजगीर को एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप की मेजबानी मिली। पटना का पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अब राष्ट्रीय स्तर के आयोजनों के लिए तैयार है। मुजफ्फरपुर, गया और भागलपुर में भी नए स्टेडियम बनाए जा रहे हैं। खेलों के आयोजन से बिहार जैसे राज्य की अर्थव्यवस्था को बहुआयामी लाभ मिल रहा है। दरअसल, जब कहीं भी राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता आयोजित होती है, वहां हजारों खिलाड़ियों, कोच, आयोजकों और दर्शकों का आगमन होता है। इससे होटल, रेस्तरां, परिवहन, लोकल मार्केट और पर्यटन स्थलों को बढ़ावा मिलता है। हाल ही में पटना में आयोजित राष्ट्रीय खेल आयोजन के दौरान होटल और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में 40 फीसद तक की वृद्धि दर्ज की गई, जिससे स्थानीय व्यापारियों को सीधा लाभ हुआ। खेल आयोजनों से निजी निवेश को भी बढ़ावा मिलता है। खेलों को बढ़ावा देने वाले राज्य में कॉरपोरेट कंपनियां, स्पॉन्सर और खेल ब्रांड निवेश करने के लिए आकर्षित होते हैं। बिहार में अब कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेल ब्रांड अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, जिससे खेल उपकरण उद्योग, प्रशिक्षण संस्थान और अन्य संबंधित क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। इससे न केवल राज्य की जीडीपी को मजबूती मिलेगी बल्कि युवाओं के लिए करियर के नए विकल्प खुलेंगे। राज्य में अब नियमित रूप से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं, जिससे बिहार के खिलाड़ियों को अपने ही राज्य में उच्चस्तरीय प्रतिस्पर्धा का अनुभव मिल रहा है। पहले उन्हें बेहतर प्रशिक्षण और मौके के लिए दूसरे राज्यों में जाना पड़ता था, लेकिन अब पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और दरभंगा जैसे शहरों में खेल सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इससे बिहार के उभरते हुए एथलीटों को अपने घर के नजदीक विश्वस्तरीय कोचिंग और टूर्नामेंट में हिस्सा लेने का अवसर मिल रहा है। बिहार में खेल आयोजनों की सफलता से राज्य की वैश्विक पहचान भी बन रही है। स्वाभाविक तौर पर जब कोई बड़ा टूर्नामेंट आयोजित होता है तो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मीडिया में उसकी चर्चा होती है। इससे बिहार की छवि आधुनिक, प्रगतिशील और खेल-समर्थक राज्य के रूप में बनती है। पहले बिहार को केवल प्राचीन संस्कृति और ऐतिहासिक स्थलों के लिए जाना जाता था, लेकिन अब इसे खेलों की नई राजधानी के रूप में भी देखा जा रहा है। खेल आयोजनों का एक बड़ा लाभ यह भी है कि इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। बिहार पहले ही बौद्ध धर्म और ऐतिहासिक विरासत के कारण लाखों पर्यटकों को आकर्षित करता है। अगर राज्य में अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताएं नियमित रूप से आयोजित होती हैं, तो इससे यहां आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या भी बढ़ेगी। खेल आयोजनों के दौरान पर्यटक न केवल मैच देखने आते हैं बल्कि वे स्थानीय बाजारों, हस्तशिल्प उद्योग और ऐतिहासिक स्थलों का भी भ्रमण करते हैं। इससे बिहार की पर्यटन अर्थव्यवस्था को मजबूत आधार मिलता है। खेल आयोजनों से राज्य में स्पोर्ट्स इंडस्ट्री का विकास भी तेज हो रहा है। खेल सुविधाओं के निर्माण, स्पोर्ट्स गियर मैन्युफैक्चरिंग, फिटनेस और कोचिंग सेंटरों की संख्या बढ़ रही है। बिहार सरकार ने खेल नीति 2023 के तहत खेल-केंद्रित स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने का भी फैसला किया है, जिससे युवा उद्यमियों को खेल से जुड़े व्यापार में कदम रखने का अवसर मिलेगा। अगर बिहार में खेलों के महत्वपूर्ण आयोजन इसी तरह होते रहे तो आने वाले वर्षों में यह राज्य देश के प्रमुख खेल केंद्रों में से एक बन सकता है।

सरकार का है मालिकाना हक

ANALYSIS

✍ डॉ. मयंक चतुर्वेदी

वर्तमान में जो दो समानताएं वक्फ बाय यूजर और शत्रु संपत्ति में दिखाई देती हैं, एक– यह की अधिकांश सभी संपत्तियां विशुद्ध रूप से सरकारी हैं और जिन संपत्तियों को निजी बताया जा रहा है, उनमें अधिकांश के पास उसके कोई भी वैध दस्तावेज नहीं है। ऐसे में यदि किसी का हक इन पर हो सकता है तो वह सरकार है। हालांकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ जो इस मामले की सुनवाई कर रही है कि इस मामले को लेकर कुछ चिंताएं हैं, जिनसे उन्होंने केंद्र सरकार को अवगत कराया है। सरकार ने बताया है कि प्रबंधन और धार्मिक मामले अलग–अलग हैं। संपत्ति के प्रबंधन और धार्मिक मामलों से जुड़े मामलों के बीच फर्क करना होगा। संपत्ति का प्रबंधन ऐसा काम है, जिसका धर्म या संप्रदाय से कोई ताल्लुक नहीं है। बोर्ड और वक्फ परिषद यह काम कर रहे हैं। अब कोई कह सकता है कि वक्फ बोर्ड भी तो मुसलमानों का मजहबी मामले में स्थापित एक निकाय है। हिंदुओं या अन्य किसी गैर मुसलमान के धार्मिक ट्रस्ट की तरह, पर देखा जाए तो ऐसा बिल्कुल नहीं है।

वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इस्लामवादियों ने देश के उच्चतम न्यायालय को 70 याचिकाओं के माध्यम से बताना चाहा है कि केंद्र की मोदी सरकार जो वक्फ कानून में संशोधन लेकर आई है, वह गैर संवैधानिक है। इसमें वक्फ बाय यूजर पर होने वाली जिरह बहुत महत्व रखती है। न्यायालय का केंद्र सरकार से तर्क है कि वक्फ बाय यूजर के जरिए तो हजारों साल से चली आ रही इस्लामिक संपत्तियों का दर्जा खत्म हो सकता है, जिसके बाद सरकार ने विस्तार से इसका जवाब देने के लिए कोर्ट से एक सप्ताह का समय मांगा। देखा जाए तो न्यायालय में चल रही वक्फ बाय यूजर की बहस ने आज भारत में शत्रु संपत्तियों की भी याद दिला दी है। वर्तमान में जो दो समानताएं वक्फ बाय यूजर और शत्रु संपत्ति में दिखाई देती हैं, एक- यह की अधिकांश सभी संपत्तियां विशुद्ध रूप से सरकारी हैं और जिन संपत्तियों को निजी बताया जा रहा है, उनमें अधिकांश के पास उसके कोई भी वैध दस्तावेज नहीं है। ऐसे में यदि किसी का हक इन पर हो सकता है तो वह सरकार है। हालांकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ जो इस मामले की सुनवाई कर रही है कि इस मामले को लेकर कुछ चिंताएं हैं, जिनसे उन्होंने केंद्र सरकार को अवगत कराया है। सरकार ने बताया है कि प्रबंधन और धार्मिक मामले अलग-अलग हैं। संपत्ति के प्रबंधन और धार्मिक मामलों से जुड़े मामलों के बीच फर्क करना होगा। संपत्ति का प्रबंधन ऐसा काम है, जिसका धर्म या संप्रदाय से कोई ताल्लुक नहीं है। बोर्ड और वक्फ परिषद यह काम कर रहे हैं। अब कोई कह सकता है कि वक्फ बोर्ड भी तो मुसलमानों का मजहबी

मामले में स्थापित एक निकाय है। हिंदुओं या अन्य किसी गैर मुसलमान के धार्मिक ट्रस्ट की तरह, पर देखा जाए तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वक्फ की अवधारणा के अनुसार, वक्फ की गई संपत्ति का उपयोग सिर्फ परोपकार के काम में हो सकता है, लेकिन आज व्यवहार में ज्यादातर वक्फ संपत्तियों का उपयोग व्यावसायिक होना पाया गया है। इसके चलते यह बात स्पष्ट होती है कि वक्फ बोर्ड आज इस्लाम के नाम पर संपत्ति अर्जित करने का माध्यम है, जो जब चाहे तब किसी भी संपत्ति पर अपना दावा ठोक देता है। इसलिए यह वक्फ बोर्ड विवादों में आया, जिसके चलते केंद्र सरकार को इसमें संशोधन करने की आवश्यकता पड़ी। कुल मिलाकर यह सिर्फ महजबी मामला नहीं, क्योंकि वक्फ बोर्ड नियम के अनुसार ऐसा नहीं है कि आने वाले समय में वक्फ बोर्ड किसी संपत्ति पर अपना दावा करना छोड़ देगा। हां, अब इसमें इतना जरूर होगा कि यदि वह पूर्व की भांति किसी भी संपत्ति पर अपना दावा करता है तो उस संपत्ति को उसे नए नियमों के अनुसार कागजों पर स्थापित करना होगा। पाकिस्तान जाने वाले भारत छोड़ते वक्त जो संपत्तियां वक्फ कर गए, उन सभी संपत्तियों पर वर्तमान में वक्फ बोर्ड का अधिकार है। इसी तरह से ज्यादातर इस्लामिक बादशाहों की बनवाई इमारतों पर वक्फ अपना अधिकार जताता है, लेकिन ये दोनों ही प्रकार की संपत्तियां पूरी तरह से सरकारी हैं, क्योंकि बादशाहों के समय जो इमारतें देश में बनी, उनके शासन के हटते ही समय-समय पर अन्य तत्कालीन शासकों के अधीन वे रहती आई हैं। पुर्तगाली, डच, फ्रांसिसी, अंग्रेज आए, स्वतंत्र राजा-महाराजाओं की सत्ता भी रहीं, फिर उसके बाद शासन भारत सरकार का आया, नए सिरे से संविधानिक प्रावधान 1950 से लागू हुए। ऐसे में समय के साथ स्वभाविक तौर पर जमीन का मालिकाना हक बदलता रहा। आज यह सभी भूमि-भवन सरकार की मिल्कीयत हैं, पर वर्तमान में अनेकों पर वक्फ बोर्ड का कब्जा है और वह उनसे धन कमा रहा है। इनमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की 256 संरक्षित इमारतें भी शामिल हैं। इतना ही नहीं ईसाई एवं अन्य धर्म, संप्रदाय की भूमि एवं भवन पर भी इसने कई राज्यों में दावा कर रखा है। आज विवाद का कारण यही है, जैसा कि संसद में पेश हुई संयुक्त संसदीय कमेटी (जेपीसी) की रिपोर्ट में बताया गया, वक्फ बोर्ड ने पूरे देश में 58,000 से ज्यादा संपत्तियों पर कब्जा कर रखा है। इतिहास से कैसे ये वक्फ बोर्ड खिलवाड़ कर रहा है, इसको आप दिल्ली की कुतुब मीनार क्षेत्र, सुंदरवाला महल, बाराखंभा, पुराना किला, लाल बंगला, कर्नाटक का बीदर किला, कलबुर्गी स्थित गुलबर्ग किले को अपना बताए जाने की मानसिकता से समझ सकते हैं। वहीं, इसने कई प्राचीन जामा मस्जिदें, सूफी-संतों की दरगाहें और गुंबदों पर भी दावा कर रखा है। रेलवे की 2704 वर्ग मीटर जमीन पर वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर लिया है। जयपुर रेलवे स्टेशन की 45.9 वर्ग मीटर और जोधपुर रेलवे स्टेशन की 131.67 वर्ग मीटर जमीन को भी वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया गया है। वर्तमान में वक्फ बोर्ड की जमीन 9.4 लाख एकड़ जमीन में फैली है। बड़ी बात यह है कि धर्म के आधार पर इस्लामवादियों ने अपने लिए अलग देश लेकर भी भारत में अपने पास दुनिया की सबसे बड़ी वक्फ होल्डिंग रखी हुई है। वस्तुतः ऐसे में यहां साफ समझ आता है कि गैर मुसलमान को वक्फ बोर्ड में सदस्य के रूप में रखने के पीछे सरकार की मंशा क्या रही होगी। संभवतः यही कि जिस तरह से अभी तक वक्फ बोर्ड मनमानी करते हुए किसी भी संपत्ति पर अपना दावा ठोकता रहा है और वक्फ कानून का हवाला देकर जिला कलेक्टर के माध्यम से इन संपत्तियों को कब्जाता रहा है, वह अब ऐसा नहीं कर पाए। क्योंकि यदि निगरानी के स्तर पर बोर्ड में गैर मुसलमान रहेंगे तो बातें बाहर निकल कर आसानी से आएंगी और मजहब के नाम पर मनमानी बंद होगी। वास्तव में उसे रोकने के लिए ही सरकार ने ये नई व्यवस्था का निर्माण किया होगा। इस केस में एक चिंता न्यायालय की वक्फ बाय यूजर की भी देखने में आई है। देखा जाए तो इसका मतलब उस संपत्ति से होता है, जिसके कोई औपचारिक दस्तावेज नहीं है, लेकिन इन संपत्तियों का इस्तेमाल लंबे समय से मजहबी कार्यों के लिए किया जा रहा है। सरल शब्दों में कहें तो वक्फ बाय यूजर का अर्थ है मौखिक घोषणाएं। भूमि के टुकड़े या संपत्तियां जिन्हें धार्मिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा रहा है, उन्हें वक्फ संपत्ति के रूप में घोषित किया जा सकता है। इसके लिए किसी दस्तावेज, किसी विलेख या किसी कागजी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं। धारणा वाला हिस्सा व्यक्तिपरक होने के साथ-साथ अपनी व्याख्या में भी अस्पष्ट था, जिससे भूमि विवादों को देशभर में बढ़ाने का काम किया है, क्योंकि इसमें कहीं भी भूमि कब्जाओ और उसे वक्फ बोर्ड की घोषित कर दो अथवा जहां मर्जी आए उस पर वक्फ बोर्ड से दावा ठोक दो! वक्फ एसेट्स मैनेजमेंट सिस्टम आफ इंडिया के आंकड़ों को देखें तो देश में 4.02 लाख संपत्तियां वक्फ बाय यूजर के रूप में चिह्नित की गई हैं। क्षेत्रफल के लिहाज से वक्फ बाय यूजर संपत्तियों में कुल 37 लाख एकड़ में से 22 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन शामिल है।

वैश्विक शांति के लिए विकसित भारत की अवधारणा

भौतिकवादी दुनिया ने विकास, खुशी, प्राकृतिक अवलोकन, रिश्तों, देखभाल, अपनापन और सामाजिक संबंधों के आयामों को बदल दिया है। हालांकि दुनिया प्रौद्योगिकी और विज्ञान के उपयोग के माध्यम से जीवन के हर भौतिक क्षेत्र में तेजी से विस्तार कर रही है, जो सराहनीय है लेकिन क्या हम वास्तव में खुश, आनंदित, प्रकृति के प्रति जागरूक और वास्तव में सही जीवन जी रहे हैं या हमने अपने जीवन को मशीनीकृत कर दिया है, प्रेम, बंधन और सामाजिक आदर्शों को भूल गए हैं। हम 2047 में स्वतंत्रता के 100 साल मनाएंगे। हमें आने वाले दशकों में भारत को फिर से महान बनाने के लिए कैसे प्रयास और ध्यान केंद्रित करना चाहिए, शांति, आनंद और बढ़ी हुई सामाजिक आर्थिक ताकत के साथ। आइए देखें कि हम इस शानदार राष्ट्र के भाग्य को बदलने के लिए कैसे मिलकर काम कर सकते हैं। जब हमने अमृत काल में प्रवेश किया और 2047 तक भारत के विश्वगुरु बनने की कामना की, इसका क्या मतलब है। क्या यह संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस या चीन जैसी महाशक्ति को संदर्भित करता है। बिल्कुल नहीं। हम महाशक्ति नहीं बनना चाहते, जिसका अर्थ है अहंकार, लालच, अनैतिकता, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, विकासशील और अविकसित राष्ट्रों को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष और युद्ध की संस्कृति, आर्थिक अनियमितताएं इत्यादि। तो 2047 में भारत कैसा दिखना चाहिए, जब हमारे पास 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था, सबसे बड़ी रक्षा सेना और विशाल कार्यबल होगा। हमें एक ऐसा राष्ट्र बनाना चाहिए, जिसमें प्रत्येक नागरिक व्यक्तिगत और राष्ट्रीय चरित्र का विकास करे। राष्ट्रीय लोकाचार और राष्ट्र प्रथम मानसिकता स्वार्थी व्यवहार पर वरीयता लेगी। जब ऐसी मानसिकता विकसित होती है तो मजबूत सामाजिक बंधन वाला राष्ट्र बड़े पैमाने पर सामाजिक-आर्थिक प्रगति का अनुभव करता है, साथ ही पर्यावरण की रक्षा और प्रबंधन भी करता है। जब ऐसा विश्व दृष्टिकोण उभरता है तो न केवल व्यक्ति, समाज और राष्ट्र समृद्ध हो सकते हैं, बल्कि संपूर्ण विश्व सामाजिक, आर्थिक और आध्यात्मिक रूप से लाभान्वित होता है। किसी भी राष्ट्र का स्वार्थी कारणों से शोषण या वर्चस्व नहीं किया जाएगा; इसके बजाय, विकासशील और अविकसित राष्ट्रों को राष्ट्र निर्माण के सभी पहलुओं में प्रोत्साहित किया जाएगा। यही विश्वगुरु का सही अर्थ है। हम जीवंत राष्ट्र इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो यह सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा है जहाँ हिंसा, अपराध, अन्याय, घृणा और असमानता सभी समाज का हिस्सा हैं। दीनदयाल उपाध्याय जी ने इसे इस तरह से कहा: हम एक राष्ट्र हैं, देश नहीं और हम अतीत के जीवंत उदाहरण रहे हैं। अगर हम अपने ऐतिहासिक तथ्यों का अध्ययन करें तो हम एक जीवंत राष्ट्र के रूप में अपनी महान विरासत को जान पाएंगे। जब नागरिकों में यह मानसिकता जागृत होती है तो लोग और समाज सद्भाव से रहते हैं, जीवन जीने का बंधन बनाते हैं और एक साथ बाधाओं को पार करते हैं, खुशी बढ़ती है। हम सिर्फ आर्थिक स्तर बढ़ाने में विश्वास नहीं करते हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि जीडीपी या किसी अन्य आर्थिक मीट्रिक के संदर्भ में आर्थिक विकास व्यक्तिगत शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य को खतरे में डालकर समाज को कमजोर करने की कीमत पर नहीं होना चाहिए, जो अंततः समाज और राष्ट्र को कमजोर करेगा। जब हम दुनिया की वर्तमान आर्थिक स्थिति को देखते हैं, तो हम देख सकते हैं कि शराब, कई रूपों में नशीले पदार्थ, दवाइयां और चिकित्सा आवश्यकताएं, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन और पर्यावरण और प्राकृतिक आवासों का विनाश, सभी जीडीपी में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। यदि राष्ट्र को इन अप्राकृतिक, अनैतिक कार्यों के परिणामस्वरूप अधिक धन प्राप्त होता है, तो ऐसा जीडीपी सराहनीय नहीं है। भारत राष्ट्र के रूप में हमें यह सोचना चाहिए कि हम सनातन धर्म के सिद्धांतों को आधार बनाकर शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आर्थिक स्वास्थ्य के मामले में एक स्वस्थ व्यक्ति और समाज बनाने के लिए काम करेंगे। हमें ऐसे किसी भी आर्थिक विस्तार को त्याग देना चाहिए जो व्यक्तियों, समाज और राष्ट्र के स्वास्थ्य को खतरे में डालता हो। याद रखें कि एक कमजोर समाज एक कमजोर राष्ट्र को जन्म देता है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम दुनिया को आर्थिक ताकत दिखाने के लिए व्यक्तिगत या सामाजिक स्वास्थ्य का त्याग न करें। सनातन धर्म जीवन के सभी पहलुओं में जीवन को अधिक सार्थक बनाता है। वास्तविक जीवन में सनातन सिद्धांतों का ज्ञान और कार्यान्वयन जीवन कौशल और ज्ञान को बढ़ाता है, जिससे समाज और राष्ट्र की मजबूती में योगदान मिलता है। आत्मनिर्भरता राष्ट्र को मजबूत बनाने की कुंजी है। आत्मनिर्भरता पर ध्यान केंद्रित करने से रोजगार के अवसर पैदा करने, उद्यमियों को आगे बढ़ाने, वैश्विक बाजारों का विस्तार करने, प्रौद्योगिकी को उन्नत करने और कौशल और ज्ञान का निर्माण करके राष्ट्र को लाभ होता है। मोदी सरकार ने आत्मनिर्भर भारत की शुरूआत की और हम राष्ट्रीय शक्ति के संदर्भ में इसके परिणाम देख रहे हैं। सरकारों, उद्योगपतियों और समाज को सेमीकंडक्टर, रक्षा, विनिर्माण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, कृषि उपज, खाद्य प्रौद्योगिकी, फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल दुनिया और पर्यावरण प्रबंधन सहित हर क्षेत्र को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। यह आत्मनिर्भरता पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना या प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किए बिना हासिल की जानी चाहिए।

Social Media Corner

सच के हक में...

जनकनंदिनी मां जानकी के प्राकट्योत्सव जानकी नवमी का पर्व मिथिला सहित देशभर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सभी को इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जगत जननी माता सीता ने अपने त्याग, तप, संकल्प और संयम से भारतीय संस्कृति में नारी शक्ति के वैभव और ओज का सर्वोच्च मानदंड स्थापित किया। मानव समाज को करुणा, संवेदना और मयार्दा का संदेश देने वालीं माता सीता से सभी के कल्याण की कामना करता हूं।

(गृह मंत्री अमित शाह का 'एक्स' पर पोस्ट)

पाकुड़ जिले के धनुषपुजा गांव निवासी बबलू बास्की की पुश्तैनी जमीन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबी समाद मियां द्वारा जबरन कब्जा करने का मामला संज्ञान में आया है। एसडीओ कोर्ट ने बबलू बास्की के पक्ष में फैसला सुनाया है। इसके बावजूद समाद मियां आदिवासी जमीन पर कब्जा करने की साजिश रच रहा है। हेमंत सोरेन जी, जमीन पर अवैध कब्जा करने का हश्र आप खुद भुगत चुके हैं। इसलिए अपने दलालों को काबू में रखिए और आदिवासी जमीन पर कब्जे का ख्वाब छोड़िए।

(बाबूलाल मरांडी का 'एक्स' पर पोस्ट)

अर्थव्यवस्था को मिलेगी गति

आज हमारी अर्थव्यवस्था भले विश्व की 10 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक हो व जीडीपी रैंकिंग में इस साल हम विश्व की तीसरी प्रमुख अर्थव्यवस्था बनने की तैयारी में हो, पर अर्थव्यवस्था के तेजी से विकास के लिए रेटपेयर्स की भागीदारी बढ़ाने की आज सबसे अधिक आवश्यकता है। फ्रीबीज के जमाने में केंद्रीय वित्त सचिव अजय सेठ द्वारा एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए देश की आर्थिक वृद्धि के लिए रेटपेयर्स को प्रोत्साहित करना जरूरी बताया गया है। दरअसल, एक ओर राजनीतिक दलों द्वारा लोक लुभावन फ्रीबीज सुविधाओं की घोषणाएं-दर-घोषणाएं की जा रही हैं तो दूसरी ओर देश को 2025 में जीडीपी रैंकिंग के अनुसार दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की चुनौती है। अर्थव्यवस्था का सीधा-सीधा गणित यह है कि एक तो करदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से कर के रुप में सीधे-सीधे आय सरकार को प्राप्त होती है तो दूसरी ओर सरकार अपनी विकास योजनाओं को अमलीजामा पहनाने के लिए उधारी से काम चलाने वाली स्थिति होती है,जिसे हम बजट प्रस्तावों में उधारी के रुप में देखते हैं। तीसरा प्रमुख स्रोत रेटपेयर्स होते हैं, देश का सेविंग पूल इन्हीं से बनता है। जहां तक आयकर का प्रश्न है तो आधार और पैनकार्ड के चलते अब आयकर के दायरे से कोई बच नहीं सकता। खासतौर से नौकरीपेशा या निश्चित पगार पाने वालों का तो आयकर सीधे-सीधे और बिना किसी छीजत के सरकार को प्राप्त हो जाता है। इसमें किसी तरह की चोरी की संभावना न के बराबर है। लगभग यही स्थिति जीएसटी के बाद देखने को मिल रही है और साल दर साल जीएसटी संग्रह में बढ़ोतरी भी हो रही है। दरअसल, जब स्थानीय स्वशासन की परिकल्पना की गई थी तो उसके साथ यह भी था एक समय आते-आते यह संस्थाएं अपनी गतिविधियों के संचालन के लिए सरकार पर निर्भर ना रहकर आत्मनिर्भर हो जाएंगी और इन संस्थाओं को सरकार के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, पर एक ओर यह सपना ही बनकर रह गया दूसरी ओर राजनीतिक दलों ने फ्रीबीज का ऐसा चलन चलाया कि रेटपेयर्स की भूमिका कम से कम होती जा रही है। रेटपेयर्स का प्रयोग सबसे पहले 1845 में माना जाता है। रेटपेयर्स की भूमिका को हम इससे अच्छी तरह समझ सकते हैं कि न्यूजीलैंड सहित अनेक देशों में तो रेटपेयर्स अपने हितों की रक्षा के लिए एसोसिएशन बनाकर आगे आ रहे हैं। हमारे देश में हालात इससे विपरीत है। हमारे यहां पिछले कुछ सालों में रेटपेयर्स की सहभागिता दिन-प्रतिदिन कम होती जा रही है। केंद्रीय वित सचिव अजय सेठ के अनुसार, संभवतः यही चिंता का कारण बन रहा है। रेटपेयर्स से सीधा-सीधा अर्थ सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र में जो बुनियादी सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है, ताकि उससे विकास या बेहतर सेवाओं के लिए राशि प्राप्त की जा सके। बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, सार्वजनिक परिवहन या इसी तरह की सेवाएं इसके दायरे में आती हैं। चुनावी वादों के चलते सरकार द्वारा बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि को कम-ज्यादा पर फ्रीबीज के दायरे में प्रमुखता से ला रही हैं। पेंशन योजनाएं और फ्री राशन, सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं, सीनियर सिटीजन व अन्य को राहत या अन्य दूसरी इसी तरह के निर्णय रेटपेयर्स की अर्थव्यवस्था में भागीदारी को सीमित करते हैं। लोकतंत्र में समान अवसर और आर्थिक रूप प से पिछड़े लोगों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए अनुदानित योजनाओं का संचालन संवेदनशील और लोकहितकारी सरकार के लिए आवश्यक है। इसका मतलब यह नहीं होना चाहिए कि सार्वजनिक सुविधाओं के लिए सरकार द्वारा जो राशि कर या अन्य रुप में प्राप्त की जाती है, वह नहीं मिले और उसका भार भी ईमानदार कर दाताओं पर पड़े तो यह किसी भी हालत में सही नहीं है। सरकार को सक्षम और कम सक्षम में अंतर करके चलना होगा। केंद्रीय वित सचिव की मंशा कहीं ना कहीं यही होगी कि फ्रीबीज के कारण जो रेटपेयर्स की अर्थव्यवस्था में भागीदारी दिन-प्रतिदिन कम हो रही है, उस पर ध्यान देना आवश्यक है।

अस्थायी राहत

भारत के वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह ने साल 2017 में इस अप्रत्यक्ष कराधान ढांचे के लागू होने के बाद से इस साल अप्रैल में लगातार रिकॉर्ड ऊंचाइयों को छुआ है। यह अप्रैल भी अलग नहीं था। आम तौर पर इसकी वजह यह है कि विभिन्न कारोबार अपने बही-खातों का मिलान करते हैं और वित्तीय वर्ष के आखिर में बनने वाली कर देनदारी पूरी करते हैं। इस बार कुल जीएसटी संग्रह लगभग 2.37 लाख करोड़ रुपये था, जो पिछले अप्रैल से एक साल में 12.6 फीसदी की बढ़ोतरी दिखाता है। रिफंड्स के बाद केंद्र सरकार की झोली में 2.09 लाख करोड़ रुपये आए, जो सालाना आधार पर 9.1 फीसद की बढ़त है। यह जीएसटी के अनुपालन में उल्लेखनीय बढ़ोतरी भी दिखाता है, जिसे तेज रिफंड और बड़े पैमाने पर फिनटेक अपनाये जाने से मदद मिली है। छोटे कारोबारों के लिए तेज रिफंड बेहद अहम हैं क्योंकि वे मामूली कार्यशील पूंजी के साथ काम करते हैं। भारत में फिनटेक अपनाए जाने की दर 87 फीसदी है, जो वैश्विक औसत से काफी ऊपर है और जिसे 2020-21 के कोविड-19 वाले अलगाव भरे वर्षों से मदद मिली। फिनटेक की वजह से एमएसएमई सेक्टर से लाखों लोग औपचारिक बैंकिंग प्रणाली के दायरे में आये, जिससे कर अनुपालन और नियामकीय निगरानी बेहतर हुई। साल 2018 से 2025 तक अप्रैल के जीएसटी संग्रहों से व्यापक अनुपालन साफ नजर आता है। इस दौरान जीएसटी संग्रह दोगुना होकर 1.03 लाख करोड़ रुपये से 2.37 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया। इस अप्रैल में महत्वपूर्ण चीज यह है कि निर्यातकों को जारी हुए रिफंड्स में 86 फीसद का उछाल है और आयातों से प्राप्त होने वाले जीएसटी राजस्व में 20.8 फीसद की बढ़ोतरी हुई है। यह एचएसबीसी इंडिया मैन्यूफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (पीएमआई) की अप्रैल रिपोर्ट में 10 महीने की उच्च वृद्धि से मेल खाती है। पीएमआई मार्च के 58.1 से बढ़कर अप्रैल में 58.2 हो गया।

Printed and Published by Fahim Akhtar on behalf of MAA MEDIA VENTURE and Printed at SHIVA SAI PUBLICATION PVT.LTD, Ratu, Kathitand, Near Tender Bagicha, H.P. Petrol Pump P.O.+P.S.- Ratu, Dist.-Ranchi, 835222, Jharkhand And Published at Roshpa Tower, 5th Floor, Main Road, Ranchi, Jharkhand-834001. R.N.I Number - JHABIL/2022/85899, Editor- Fahim Akhtar. Mob - 9431311669, E-mail : thephotonnewsjharkhand@gmail.com

How Nehru viewed role of governors

GOVERNORS continue to trigger controversies over their apparent attempts to disturb the federal balance of power. The latest example is a detailed report sent by West Bengal Governor CV Ananda Bose to the Ministry of Home Affairs regarding the law and order situation in Murshidabad, which witnessed violence recently after the enactment of the Waqf (Amendment) Act. Bose toured the state before submitting the report, in which he stated that the "twin spectres of radicalisation and militancy" posed a serious challenge to the state.

A flashback is instructive: In 1952, then Governor Sri Prakasa swore in a 152-member Congress government led by C Rajagopalachari in the 375-member Madras Legislative Assembly, ignoring United Democratic Front leader T Prakasam's claim of support of 166 legislators. Gian Singh Rarewala's coalition government in PEPSU (Patiala and East Punjab States Union) was dismissed in 1953 by invoking Article 356 (pertaining to President's rule) of the Constitution. In 1959, the Union Government dismissed the EMS Namboodiripad government in Kerala on the pretext of deteriorating public order.

Following the fourth General Election in 1967, the Governor's office was misused to dismiss coalition governments in seven states. Then Prime Minister Indira Gandhi had no qualms about removing a non-Congress government. Later, the brazenness of Governors Thakur Ram Lal (Andhra Pradesh, 1983-84) and Romesh Bhandari (Uttar Pradesh, 1996-98) led to their removal. The unabashed misuse of Article 356 prompted the Supreme Court to deliver a landmark judgment in the SR Bommai case (1994). In a recent significant judgment on withholding of Bills by the Tamil Nadu Governor, the apex court redefined gubernatorial powers.Since 2014, when Narendra Modi took charge as Prime Minister, several governors have tried to exceed their Raj Bhavan brief. As the Governor of West Bengal, Jagdeep Dhankhar (now Vice-President) — and now his successor Ananda Bose — made it a routine to tour the state without taking the state government into confidence. They have used their visits to comment against the government while addressing the media.Did the makers of the Constitution envision the Governor's role outside the Raj Bhavan, on the streets? If yes, how was his/her role defined vis-à-vis the elected state government?India's first Prime Minister Jawaharlal Nehru reflected on this question in his fortnightly letters to provincial/state premiers/chief ministers. He used to write long letters to provincial/state governments, dealing with a wide range of issues, including those being discussed in the Constituent Assembly, the policy measures being carried out by the Union Government regarding agriculture, food, refugee resettlement, foreign policy and industrial production, the way the UN Security Council dealt with the Kashmir issue in a partisan manner, and so on.Obviously, the Governor's office did not escape his attention. First and foremost, he looked at governors as non-partisan constitutional functionaries. He did not endorse politicking by them, particularly parallel politics in states, as political activities of governors that could make the Raj Bhavan a centre of partisanship would destroy the constitutionally designed power balance, equilibrium and ecosystem of governance.After attending a Conference of Governors, he wrote on May 14, 1949: "As was natural, the question of the relationship between the governors and ministers was considered. There was no question, of course, of the governors interfering with the work of the ministry. He had to function as a constitutional Governor. At the same time, it was pointed out that it would be undesirable and wasteful of talent if we did not utilise the governors' experience."He stressed that the premiers/chief ministers must keep the Governor of their state informed. Governors should also keep themselves informed.

NCERT and the politics of language in English textbooks

Measures taken by India, like halting water flow, blocking YouTube channels of famous Pakistani artistes and cricket stars, aim at crippling Pakistan

THE NCERT has ignited controversy by replacing the titles of English textbooks like 'Honeysuckle' with Hindi titles such as 'Poorvi', 'Mridang' and 'Santoor' for Classes VI, VII and VIII. Government officials defend these names, claiming they transcend language and draw from India's artistic traditions. 'Poorvi' (meaning eastern), they note, is not simply a Hindi word but a raga in Hindustani classical music, symbolising the harmony of an eastern dawn.

Defenders of the NCERT's move invoke the Shakespearean adage, "What's in a name?" It suggests that these titular changes are inconsequential. This argument, however, contains a glaring logical fallacy. If, indeed, there is "nothing in a name", why insist on replacing perfectly functional English titles with Hindi ones? The selective application of this principle betrays its disingenuousness. Would the same defender embrace naming Sanskrit textbooks 'Twinkle' or Hindi textbooks 'Harmony'? The ensuing discomfort and resistance would reveal the fallacy of their position. Names carry significant cultural weight and symbolic meaning — a fact the NCERT recognises when imposing Hindi nomenclature but conveniently overlooks when justifying it. The content of these textbooks has been revised to feature more Indian contexts. Moving away from western-centric materials —think 'Rain, Rain, Go Away' as a nursery rhyme far removed from India's monsoonal realities — the books now incorporate multiple genres intended to reflect students' lived experiences within the Indian social, cultural and geographical landscapes.The textbooks ostensibly aim to develop core language competencies through intelligently designed activities. Units are structured with sections like 'Let us listen', 'Let us speak', 'Let us read', 'Let us write' and 'Let us learn' while supposedly weaving in elements of cultural heritage alongside values of ecological sensitivity, disability awareness, gender equality and digital skills.The primary goal of textbooks is to develop core language competencies while integrating vocabulary and grammar within meaningful contexts relevant to Indian students. By merging Indian ethos with a global language, the NCERT envisions a system aligned with the 'Ek Bharat, Shreshtha Bharat' theme.

This rosy picture quickly deteriorates under scrutiny, particularly from non-Hindi-speaking states, where the renaming is perceived as a sinister move to impose Hindi and undermine linguistic diversity. Kerala's Education Minister V Sivankutt has labelled it a "violation of common logic", arguing that English textbooks deserve English titles, not Hindi ones transliterated into Roman script.In the broader context of states' resistance to the NEP 2020, these criticisms are not unfounded. Using 'Poorvi' — a Hindi word — for an English textbook represents symbolic overreach and a subtle assertion of Hindi supremacy, even in a subject taught in a global language. For students in regions where Hindi is neither spoken nor understood, these titles create an alienating psychological barrier to learning. Practical concerns also emerge: how will a child in rural Tamil Nadu pronounce 'Poorvi' or understand its meaning without Hindi familiarity? The Roman script doesn't resolve this disconnect; it merely highlights it, risking mispronunciation and confusion. Rather than fostering unity, this approach deepens regional divides by

portraying Hindi as the default lens through which India's diversity must be viewed.

The NEP-2020, as manifested in the NCFSE-2023 and these controversial textbooks, has reached its "crescendo". These materials purportedly aim to "instill" pride for the Indian ethos and values in students. This 'pride' must be 'ingrained' in the students even while teaching a non-Indian language. Yet, this approach overlooks that language and its teaching are key conduits for transmitting culture across generations.

Sapir-Whorf hypothesised that the structure of language determines one's perception and categorisation of experience. The Indian student does not grasp the 'structure' of the English language before schooling begins because English is largely the second language for her, and none of the Indian languages have a structure similar to that of English. It is through language that we socialise, we create or conflict with authority, we argue, imagine, fantasise and dream. The English language and its teaching cannot be 'separated' from the English culture, just as Hindi cannot be separated from the culture of 'Hindi patti' or Sanskrit cannot be disassociated with a particular religion, as it is the lingua franca of the gods only.Beneath this debate lies an uglier truth: the renaming of textbooks exemplifies a larger homogenising project, threatening India's pluralistic fabric. While 'Ek Bharat, Shreshtha Bharat' sounds noble, it often manifests as a push for uniformity, privileging Hindi and northern culture. Naming an English textbook 'Poorvi' is particularly ironic — a western language cloaked in a Hindi title, forcing an awkward marriage that reeks of cultural imperialism, shifting from colonial legacies to national majoritarianism. The near-total absence of non-Hindu characters — Muslims, Sikhs, Christians, Jains, Parsis, Buddhists — and the erasure of their cultures, values, festivals and craftsmanship in the textbook further underscores this steadily narrowing cultural imagination.Using English to "instill" Indian ethos and values is not merely inconsistent but also casts aspersions on Hindi, Sanskrit and other Indian languages' ability to do the same effectively. In the neoliberal context, English language teaching (ELT) is expected to enhance international communication with financial motivations. Viewing ELT solely in economic terms perpetuates the "indoctrination" explicit in Macaulay's infamous minutes. The NEP had an opportunity to alter this discourse, but it, instead, replaced colonial indoctrination with Indian majoritarian indoctrination.The tokenism in the textbooks' content deepens concerns. A southern folktale here, a reference to western kite-flying there and an eastern nod in the title 'Poorvi' feel like hollow gestures while the northern culture claims dominance.

This selective representation fails to address the systemic marginalisation of non-Hindi languages and cultures. In India, language is more than a medium — it's a vessel of identity, history and pride. By symbolically prioritising Hindi, the government sends a message that other languages are lesser, fuelling resentment among linguistic minorities.The NEP failed to recognise how critical pedagogy in ELT could have helped learners perceive social inequalities, injustice and imbalances. Instead of using indigenised language teaching for emancipation, it capitulated to a nationalist agenda that undermines India's true linguistic and cultural diversity, replacing colonial indoctrination with Indian majoritarian indoctrination. These nationalist ideals ring hollow, particularly when the National Flag in this textbook, despite the government's flag frenzy, is displayed with its colours upside down, a fitting metaphor for the fundamental inversion of the ideals being touted (see 'Poorvi', Class 7, page 200). The result is not educational liberation but merely a change in the source of ideological imposition.

Death before exam

Toppers' culture needs a hard reset

THE tragic deaths of three young students — two NEET aspirants in Kota, Rajasthan, and a forensic science student of a private university in Mohali, Punjab — within days of each other lay bare a systemic failure that India continues to ignore at its own peril. That one of the students died just before the NEET-UG exam underscores how relentless academic pressure, mental health neglect and unrealistic expectations have created a lethal mix for many. Kota, the coaching hub, has seen 14 student suicides this year alone. Despite repeated warnings, the structural stressors — high-stakes exams, toxic competition, unregulated coaching practices and the burden of 'guaranteed success' — remain unaddressed.Recently, the Central Consumer Protection Authority (CCPA) issued notices to several coaching institutes for misleading advertisements and unfair trade practices. Many ads promised top ranks and assured selections without

substantiating their claims. These promises, coupled with immense pressure, are often a trap for vulnerable students and anxious parents. The country's toppers' culture needs a hard reset. The Rajasthan government's proposal for the Coaching Institutes (Control and Regulation) Bill is a step forward. Mandatory counselling and aptitude tests before enrolment may help, but enforcement is the key. The 2018 guidelines that aimed to provide psychological support and regulate private institutes seem to have been ignored into irrelevance. Without strict oversight, the new law too risks becoming symbolic.

Parents must also introspect. Forcing children into ill-suited streams or tying self-worth to marks and rankings breeds despair. The country must stop treating its students as rank-seekers and start recognising them as individuals with unique strengths and limits. The government must cultivate an ecosystem that generates enough jobs for the youth with varied streams of interest. No exam is worth a life.

For now, continue with war by other means

To begin with, we must define what our aim is — do we want to deal a decisive, final blow to terrorism that comes from Pakistan or do we want to do the same to Pakistan?

Nearly two weeks after the horrific, targeted killing of defenceless tourists at Pahalgam, the dust has not yet settled to enable us to view the situation with clarity. The seething anger within our hearts is not abating. Though the single common emotion is revenge, its suggested method, modalities and manifestation vary. Public fora are full of views, opinions, recommendations, critiques, et al, depending upon the sources of their origin. But in the discussions, everyone seems to agree that the situation is more complex than what was perceived at first.When faced with complex problems, it is a good idea to revisit the first principles and lessons of history. While principles bring to fore axioms, history can be a good reminder of events and lessons that ought to have been learnt from them.

Some of our fellow citizens see war clouds gathering, but the more informed minds look at many other options short of, or more effective than, war. It is often said that if one wants peace, one must prepare for war. It would do no harm, therefore, to see how some of the time-tested and proven principles of war could help us to see through the haze.

To begin with, we must define what our aim is — do we want to deal a decisive, final blow to terrorism that comes from Pakistan or do we want to do the same to Pakistan? This is vital as the measures to be taken for both would be quite different.Offensive action could be physical or non-physical. Physical offensive must achieve surprise and it should be ensured that it is applied at the right time and at the right place. To that end, patience and level-headed planning and not knee-jerk reactions are the key. Non-physical actions, on the other hand, could be sustained over a long period and would generally be multi-pronged.There is a need to apply sufficient force to ensure success, yet there is the principle of economy of effort to be kept in mind. To achieve the two seemingly contradictory requirements,

concentrating the force at the point of decision is essential. That calls for mobility of assets and flexibility of plans. This is possible in both physical and non-physical offensive actions. The suspension of the Indus Waters Treaty (IWT) and the ban on mail and trade are two recent cases that exemplify the latter.Sustainability of an offensive depends on several factors; principle among them is robust economy. Our economy is on an upward curve; nothing we undertake should hurt that progress. Keeping our economy secure could, therefore, be a term of reference for our planners.

Cooperation between all organs of the government is essential to achieve optimum results. Fortunately, given the state of high morale not only within all ranks of the armed forces but also among all our citizens, necessary cooperation would be readily forthcoming.This is not the first time we are facing post-trauma complex challenges for decision-making at various levels and it most certainly would not be the last. In 1971, we faced not only an unbearable burden on our economy but also a grave national security concern arising from the influx of millions of refugees from the erstwhile east Pakistan. Acting on multiple fronts, like international diplomacy, political consensus and decisive military actions, we achieved a historic military victory over Pakistan. It was no hasty decision. The offensive was launched after waiting for many months of biding our time to select the right time and method and after full preparation.We learn from our mistakes, too. Who can forget the episode when lapses in security, lack of coordination between departments and some questionable decision-making resulted in the hijack of an Indian Airlines flight to Kandahar and the release of jailed terrorists? We are now far better prepared against such threats.Then, there have been the attacks on pilgrims of Amarnath Yatra, on Raghunath Temple, Akshardham and the Army camp at Kalu Chak and Pulwama. We have learnt and improved from each of them.During the Kargil war, our leadership showed considerable statesmanship in keeping the conflict confined to a specified geographical area. In fact, the need to remain within our means and in control of the situation at all times brought about the concept of 'limited war'.In an adverse situation such as the one we have experienced recently, it is common to hear of 'intelligence failure'. By holding someone or some agency accountable and placing the blame at its door, there is almost a sense of having nabbed the guilty. Before we indulge in any hasty blame game, we must remember two things. First, many such attacks are nipped in the bud by the security forces (SF) when 'actionable intelligence' is given to them by the intelligence apparatus. It is generally all in a day's work for the SF and rarely, if ever, publicised. Next, the SF work round the clock, ready and hoping for action against terrorists. The terrorists, on the other hand, can select a time and place to strike — so they have to be lucky just once.

The jury is still out on the whys and wherefores of the Pahalgam attack. We are also not certain what the Pakistan army's aim was in selecting an easy target in a cowardly, senseless attack. It could be to divert the attention of the Pakistan population from its recent failures in Balochistan and Khyber Pakhtunkhwa. Or, to hinder India's economic progress, or to provoke us and lure us to walk into a trap — a massive ambush waiting to be sprung.

Till the truth is revealed, as it was in the case of the intrusions in Kargil in 1999, we need to keep our powder dry for action, keep a cool head, continue to apply economic squeeze and continue our 'war by other means', as Clausewitz would say!

Evera Cabs to acquire 500 BluSmart Electric Cabs

New Delhi. Electric taxi service provider Evera Cabs (Prakriti Mobility) has initiated the repossession of 500 electric cabs earlier operated by troubled BluSmart. Evera said that 220 vehicles have been acquired and the remaining 280 are set to be reclaimed in the coming days.The company added that it is looking to enhance its position as a leading electric cab service provider, with a strong focus on airport mobility. Evera has plans to acquire 1,000 BluSmart cars.

"What we're executing is not just a scale-up, it is a realignment of the electric mobility narrative in India. As key players recalibrate, Evera is stepping forward with clear intent, absorbing proven EV assets and trusted drivers to ensure uninterrupted service across key routes," Evera Co-Founder and CEO Nimish Trivedi said.

Evera said its repossession of BluSmart's cabs through its lenders is part of a multi-stage strategic plan to reinforce its footprint in NCR's high-demand airport cab sector. In the next phase, Evera has plans to double down on its airport network expansion, extending services across all terminals of Delhi's airport. Last month electric cab-hailing platform BluSmart suspended operations across Delhi-NCR, Bengaluru, and Mumbai after capital market regulator Sebi banned Gensol Engineering and promoters - Anmol Singh Jaggi and Puneet Singh Jaggi, who are also co-founders of BluSmart - from the securities markets in a fund diversion and governance lapses case.

Game of skills involving money is gambling: Govt to SC

New Delhi. The government has informed the country's apex court that the moment a financial stake is introduced—even in games requiring skill—the activity becomes a form of betting and gambling. This submission was made as a crucial hearing on the applicability of GST to online gaming, fantasy sports, and casinos began on Monday in the Supreme Court. The government contended that such activities fall squarely within the purview of taxable actionable claims under the Central Goods and Services Tax (CGST) Act, 2017.

A bench comprising Justices J.B. Pardiwala and R. Mahadevan is examining whether the Goods and Services Tax (GST) is lawfully applicable to online games, fantasy sports platforms, and casinos, particularly when they involve monetary stakes.

The GST department's argument is based on the premise that once money is staked, the game—regardless of whether it involves skill or chance—enters the domain of gambling, a position previously upheld by Supreme Court judgments. Citing state laws, the revenue department has argued that state gambling statutes exempt games of skill from criminal prosecution only when played without stakes. "When stakes are involved, such games may be considered gambling," it stated in court.The revenue department has further submitted that the 101st Constitutional Amendment transferred taxing powers for betting and gambling to the Centre under Article 246A. It, therefore, argues that regulatory powers of the states cannot be construed as taxation powers.The government has also stated that the 2023 amendment was merely clarificatory in nature, asserting that the power to tax actionable claims existed even before the amendment.Abhishek A. Rastogi, founder of Rastogi Chambers and counsel for one of the petitioners before the Supreme Court, said: "If games of skill are treated as gambling solely because of monetary stakes, we risk blurring crucial legal boundaries. The decision will not just impact revenue collection, but the future of lawful, skill-based digital enterprises across India."The government contends that a 28% GST should apply to the total contest entry amount, effectively taxing the entire prize pool. However, gaming companies argue that GST should only be levied on their platform fees or commission, as many of these games involve skill rather than chance.

Global oil prices fall to multi-year lows; brent nears $58 amid global trade war

NEW DELHI. Global oil prices tumbled sharply on Monday after OPEC+ announced increased production for June. The alliance of oil-producing countries, led by Saudi Arabia, agreed to raise output by an additional 411,000 barrels per day (bpd) in June, following a similar increase in May.As a result, Brent crude dropped as much as 4.6% to near $58 per barrel, while West Texas Intermediate (WTI) hovered around $56 in early trading. Brent is now approaching

the four-year low it previously touched in April 2025. The aggressive ramp-up in production comes amid growing concerns that US President Donald Trump's tariffs could trigger a global recession, potentially weakening oil demand just as supply expands. Consequently, April recorded oil's largest monthly loss since 2021.The continued slide in oil prices spells potential economic relief for India, which relies heavily on imported crude. A lower oil import bill could ease inflationary pressures and help buffer the economy against external shocks. India's average crude basket price stood at $67.73 per barrel in April but fell to $61.89 on May 1, reflecting the global downtrend."While there are concerns about the first, second, and third round effects of US tariffs, especially on external demand and capital formation—one important factor is the ongoing, albeit unstated, pursuit of lower oil prices, possibly as low as $50 per barrel," said

Bhushan Power order puts Rs 34,000 cr bank fund at risk

New Delhi. The Supreme Court order rejecting JSW Steel's Rs 19,800 crore resolution plan and liquidating Bhushan Power & Steel Ltd (BPSL) has put at risk around Rs 34,000 crore of banks exposure to the latter.The banks will hae to pay back the entire Rs 19,350 crore they had received from the JSW group, and will have to fully provide for that in the June quarter. BPSL had owed Rs 48,523 crore to the lenders, most public sector banks led by the State Bank. The court order also puts a big question mark on the fate of the Rs 10,800 crore JSW had borrowed to fund the acquisition along with a Rs 4,000 crore term loan that JPSL had raised to run the company after the ownership changed hands.The development comes as banks are already facing squeezed margins —as lending rates are falling and will likely fall more in the coming months but deposit prices remain highly elevated and will remain so for some more quarters.Under the IBC scheme, lenders are legally bound to return the money received from the winning bidder if the resolution plan gets rejected later, a public sector banker told TNIE. Another banker said that banks will also have to set aside more funds if the liquidation value is lower than the now failed IBC resolution value. During the insolvency process, valuers had arrived at a liquidation value of Rs 9,700 crore.None of the nearly a dozen lenders, who are mostly public sector banks, have officially commented on the development except saying they are studying the detailed order.The bankers with exposure to the crippled company are mostly state-run lenders with State Bank of India having had an exposure of Rs 9,800 crore and had received Rs 3,930 crore in likely payback from JSW Steel under the resolution plan, followed by Punjab National Bank with Rs 6,100 crore of exposure and a likely recovery of Rs 2,440 croe, according to analysis by brokerages.Among leading

lenders, Axis Bank and Karur Vysya Bank are the only private sector lenders with exposures of Rs 900 crore and recovery of Rs 350 crore and Rs 400 crore and Rs 140 crore.The other major lenders include Canara Bank (Rs 3,700 crore & Rs 1,490 crore), Union Bank of India (Rs 3,200 crore & Rs 1,280 crore); Bank of Baroda (Rs 2,600 crore & Rs 1,050 crore); Indian Bank (Rs 2,600 crore & Rs 1,060 crore); Indian Overseas Bank (Rs 1,000 crore & Rs 420 crore); Jammu & Kashmir Bank (Rs 400 crore & Rs 170 crore), and IDBI Bank with Rs 600 crore and Rs 230 crore in payback.In a surprise order that has serious ramifications for the insolvency resolution process and questions the collective commercial wisdom of lenders, a Supreme Court bench of justices Bela Trivedi and Satish Chandra Sharma had last Friday set aside the IBC resolution of Bhushan Power & Steel and also ordered its liquidation saying JSW Steel, the lenders, the resolution professional Mahender Kumar Khandelwal as well the NCLT and NCLAT did not follow the IBC provisions and thus the entire deal was illegal.

Atheives up listing gains, slides 4% after wr Energy geak debut. Hold or sell

New Delhi. Electric two-wheeler maker Ather Energy ended nearly 4% lower on its market debut Tuesday, giving up early gains despite a modest listing premium. The stock opened at Rs 328 on the NSE, up 2.2% over its issue price of Rs 321, but slipped over 4% to an intraday low of Rs 308.95 amid weak market sentiment.

The Rs 2,981-crore IPO was subscribed 1.43 times and had seen subdued demand across categories. Analysts attributed the weak performance to aggressive pricing and sector headwinds.

"As expected, we see a flat listing, which was justified given the aggressive valuation—especially when benchmarked against peer OLA Electric," said Prashanth Tapse, Senior VP (Research), Mehta Equities Ltd.

"The electric two-wheeler segment remains highly competitive and capital-intensive, with most players, including market leaders, still struggling to turn profitable. We recommend a 'HOLD' only for risk-

taking investors comfortable with short- to medium-term volatility. Conservative investors should wait for the stock to settle at more reasonable valuations," he added.

Tapse added that the EV 2W space remains in a high-growth but high-burn phase, with potential for sharp swings in both business performance and stock price.Founded in 2013, Ather designs its scooters in-house and operates over 2,600 charging stations across 300 cities. Its product line includes the Ather 450 and the new family-focused Ather Rizta.The company plans to use IPO proceeds to fund a new factory in Maharashtra, repay debt, and invest in R&D. For FY24, Ather posted a net loss of Rs 1,059 crore on Rs 1,754 crore revenue, with EBITDA margins at -36%.While Ather enjoys strong brand equity and long-term growth potential, analysts caution that continued cash burn, pricing pressure, and market competition could keep the stock volatile in the near term.

Sensex down over 80 points, Nifty above 24,400; pharma stocks tumble

NEW DELHI. Benchmark stock market indices fell after opening flat on Tuesday as pharmaceutical stocks tumbled.The BSE Sensex was down 28.27 points to trade at 80,768.57 around 9:24 am, while the NSE Nifty50 was down 10.85 points to 24,450.30.Broader market indices also slipped into negative territory, with early trade marked by a slight uptick in volatility.

Among the Nifty50 pack, M&M, Hero MotoCorp, Bharti Airtel, ONGC, and Bajaj Auto emerged as the top gainers, while Cipla, Jio Financial Services, Dr Reddy's, Titan, and Eternal led the losses."Sustained FII buying for the 13th day in a row, supported by weak dollar, has imparted resilience and support to the market despite the India-Pak tensions," said Dr. VK Vijayakumar, Chief Investment Strategist at Geojit Financial Services.

"This resilience is further reinforced by tailwinds in the form of soft crude, declining inflation and the RBI's cheap money policy of rate cuts and abundant liquidity injection. These tailwinds have the potential to facilitate high GDP growth and improving corporate earnings in FY26, and the market is likely to discount this by moving to new highs," Vijayakumar added.

However, he pointed out that the "uncertainty regarding the India-Pakistan tensions will keep the market range bound" in the near-term. "Large cap IT has bottomed out. Large cap private sector banking stocks will remain resilient despite the recent run up," he added.From a technical perspective, the Nifty 50 continues to trade in a narrow consolidation range, forming a neutral candlestick pattern on the daily chart. A decisive move above 24,500 could pave the way for an up move towards 24,700 and 24,800. On the downside, support is seen at 24,200 and 24,000, where traders may find buying opportunities on dips, said Mandar Bhojane, Equity Research Analyst at Choice Broking.

On the institutional front, FIIs continued their buying streak on May 5 with net equity purchases of 497 crore, while DIIs remained strong buyers, investing 2,788 crore. This sustained inflow from both domestic and foreign investors reflects underlying market confidence, despite global uncertainties."Given the mixed cues and key resistance levels ahead, traders are advised to adopt a 'wait and watch' approach, especially in high-leverage positions. Booking partial profits on rallies and maintaining tight stop-losses is recommended. If Nifty sustains above 24,500, fresh long positions can be added gradually," Bhojane said.

UPI QR Codes Record 91.5 Per Cent Surge To 657.9 Million, Credit Card Growth Slows

Mumbai. UPI QR codes have recorded the fastest growth in digital payments infrastructure in the financial year 2024-25, with a 91.5 per cent jump over the previous financial year to 657.9 million, according to the latest RBI data.

The surge in UPI QR codes was accompanied by a slowdown in the growth rate of credit card transactions to 7.94 per cent year-on-year, while debit card additions registered a mere 2.7 per cent growth to 991 million.The growth in the number of UPI QR codes has been accelerating with the increasing deployment by platforms like Google Pay, Paytm, and PhonePe. The number of banks going live on UPI continues to increase, and the total touched 668 in April, which is expected to increase the value of such transactions, according to bank officials.March saw a record Rs 24.77 lakh crore in UPI transactions, marking a 25 per

cent increase in value and a 36 per cent increase in volume compared to the previous year. UPI has become the dominant method for digital transactions in India. Nearly four out of five digital payments in the country were conducted on the Unified Payments Interface (UPI) in the financial year 2024 (FY24), according to the Reserve Bank of India's annual report.

UPI's share, compared to the cumulative volume of digital payments in the country, has grown steadily from 73.4 per cent in FY23 to 79.7 per cent in FY24. In FY20, UPI's share as compared to the volume of total digital payments in India was pegged at 36.8 per cent.

The RBI is actively promoting digital payments through various initiatives, including the "Har Payment Digital" campaign, which aims to make every person in India aware of digital payments. RBI also allows flexibility in revising transaction limits for UPI in-person merchant payments, allowing NPCI to adjust limits based on user needs, with safeguards in place which has made the mode of payment more convenient.

Wall Street slips, snapping 9-day rally as oil prices hit 4-year low

Wall Street's nine-day winning streak ended Monday as oil prices fell to a four-year low following an OPEC+ output boost. Tech stocks and Buffett's exit also weighed on markets.

NEW DELHI. Stocks closed lower on Wall Street Monday, breaking a nine-day winning streak, as oil prices hit a four-year low after the OPEC+ group announced plans to increase output.The losses came amid a relatively calm day of mostly mixed trading. They follow several weeks of gains that helped the market wipe away its losses since the ongoing trade war began.The S&P 500 fell 36.29 points, or 0.6%, to 5,650.38. The decline broke the benchmark index's longest winning streak since 2004.

STORIES YOU MAY LIKE

Terrorists killed her husband, toxic trolls attempt character assassination

Third Indian student arrested in US in 2 weeks for trying to dupe elderly person

Pak national trying to enter India through Punjab border arrested

The Dow Jones Industrial Average fell 98.60 points, or 0.2%, to 41,218.83. The Nasdaq composite fell 133.49 points, or 0.7%, to 17,844.24.Technology companies and other big stocks were among the heaviest weights on the market. Apple slumped 3.1%, while Amazon fell 1.9% and Tesla slipped 2.4%.Berkshire Hathaway fell 5.1%. Legendary investor Warren Buffett announced over the weekend that he would step down as CEO by the end of the year after six decades at the helm. Buffett will still be chairman of the board of directors.The OPEC+ group of eight oil producing nations announced over the weekend that it will raise its output by 411,000 barrels per day as of June 1.

US crude oil prices fell 2% to $57.13 per barrel. Many producers can no longer turn a profit once oil falls below $60. Prices are down sharply for the year over worries about an economic slowdown. The energy sector led the losses within the S&P 500. Exxon Mobil shed 2.8%.Markets have been absorbing the shock of tariffs and the growing trade war. President Donald Trump has imposed import taxes on a wide range of

imports, prompting retaliation from global trading partners. Many of the more severe tariffs that were supposed to go into effect in April were delayed by three months, with the notable exception of tariffs against China.The delays have provided some relief to Wall Street, though uncertainty about the impact from current and future tariffs continues to hang over markets and the economy.

"Uncertainty remains elevated and economic data will likely weaken in the coming months, meaning further bouts of volatility are likely," said Ulrike Hoffmann-Burchardi, chief investment officer of global equities at UBS Global Wealth Management.

That uncertainty will overshadow the Federal Reserve's meeting this week.

The Fed is expected to hold its benchmark interest rate steady on Wednesday. It cut the rate three times in 2024 before taking a more cautious stance. The central bank was concerned that inflation, while easing, was still stubbornly hovering just above its target rate of 2%. Concerns about inflation reigniting have only grown amid the global trade war sparked by Trump's tariff policy.

The economy has shown some signs that it is feeling the impact from tariffs and the uncertainty over Trump's policy. The U.S. economy shrank 0.3% in the first quarter, marking the first drop in three years.The economy is still showing signs of resilience, however. Consumers have grown more cautious, but still continue to spend. Economic activity in the services sector continued expanding in April, according to a survey from the Institute for Supply Management.

Plot to revive sleeper cells foiled in Punjab, grenades, terror hardware seized

Punjab Police, acting on intelligence inputs and in coordination with central agencies, foiled a plot by Pakistan's ISI-backed terror networks to revive sleeper cells in the state by seizing a cache of arms and explosives in Shaheed Bhagat Singh Nagar.

NEW DELHI. In a major breakthrough in anti-terror operations, the Punjab Police's special cell has seized a cache of terrorist hardware and ammunition in Shaheed Bhagat Singh Nagar district, foiling an attempt by Pakistan's ISI-backed cross-border terror networks to revive sleeper cells in the region, officials said on Tuesday. Acting on intelligence inputs, the State Special Operation Cell (SSOC) of Punjab Police, in coordination with central agencies, seized two rocket-propelled grenades (RPGs), two improvised explosive devices (IEDs), five P-86 hand grenades, and a wireless communication set, the Punjab Police DGP tweeted. "Preliminary probe indicate a coordinated operation by Pakistan's ISI and allied terror outfits to revive sleeper cells in Punjab," he said.

The anti-terror operation comes just days after Pakistan-based terrorists opened fire on civilians in Jammu and Kashmir's Pahalgam, killing 26 people, most of them tourists. Security agencies, particularly in border regions, have been placed on high alert following the April 22 attack. Terrorist sleeper cells are covert groups of terrorists who remain inactive for long periods, blending into local communities until they receive orders to carry out attacks or provide support to active terrorist operations. Speaking exclusively to India Today, a former sleeper cell member said that the Pahalgam attack couldn't have been possible without the help of sleeper cells and around 5-6 of them were in touch with the Lashkar terrorists who carried out the attack.

In a similar anti-terror operation on Sunday, the Border Security Force (BSF) arrested a Pakistani national in Punjab's Gurdaspur district for allegedly attempting to infiltrate the India-Pakistan border. The individual, identified as Muhammad Hussain, has been handed over to the Punjab Police and remains in custody. Last week, a Pakistani Ranger, part of the country's paramilitary force, was also detained by Indian border forces. A preliminary investigation suggests the soldier may have been on an espionage or reconnaissance mission, amid heightened tensions between India and Pakistan following the Pahalgam attacks.

Blackouts, Evacuation, Hotlines: Details Of Today's Security Drill

New Delhi. Following directions from the Centre, states and Union Territories are preparing for a civil defence security drill tomorrow. While the Centre's instructions to the states' chief secretaries do not mention the tensions with Pakistan, the timing of the order, amid heightened tensions following the Pahalgam terror attack, leaves no room for interpretation. The last such drill was conducted in the run-up to the 1971 war between India and Pakistan, in which the latter was defeated and Bangladesh was created. Here is what you need to know about the security drill.

Who Will Be Part Of The Drill

According to the Ministry of Home Affairs notification to the states, this drill will be held across the country's 244 Civil Defence districts. "The conduct of the exercise is planned up to the village level. This exercise aims to assess and enhance the readiness of Civil Defence mechanisms across all States and Union Territories," it says.

According to the notification, the drill should see "active participation of the District Controller, various district authorities, civil defence wardens/volunteers, Home Guard (active /reservists volunteers), NCC, NSS, NYKS, college and school students".

The notification also mentions that civilians must be trained to respond to a "hostile attack".

What Are The Objectives

The Home Ministry notification lays down nine objectives of this security drill. The first is to assess the effectiveness of air raid warning systems and aims to prepare people for a response to an aerial attack. Hotline and radio communication lines with the Air Force will also be operational during this drill. It will also test the functionality of control rooms and shadow control rooms. The notification says civilians and students must be trained in civil defence to protect themselves "in the event of hostile attack".

The training also includes crash blackout measures, which refer to training on planned blackouts to guard against aerial attacks. As part of the drill, authorities may ask residents to switch off lights for a certain duration to mimic a blackout. The training will also include camouflaging of vital plants and installations. This means steps to cover or shield key premises -- such as airfields, refineries and rail yards -- from enemy fire. The drill will also check the preparedness of rescue teams and firefighters and evacuation measures. The evacuation drills will be rehearsals for moving civilians from vulnerable areas to safe zones. Civilians will also be trained in first-aid, firefighting and shelter techniques.

India Preps Pahalgam Response

The Pahalgam terror attack, in which 25 tourists and a Kashmiri pony ride operator were murdered in cold blood, has shocked and horrified the nation. The government has vowed a strong response, with Prime Minister Narendra Modi saying that the perpetrators and conspirators of the attack would get a punishment they cannot imagine. The investigation into the Pahalgam attack has pointed to a Pakistani hand, like several other terror attacks on Indian soil in the past.

Pakistan violates LoC ceasefire for 12th day, Army retaliates

New Delhi. The Indian Army responded to unprovoked small-arms firing by Pakistani troops across the Line of Control (LoC) during the night of May 5-6, Indian Army spokesperson said. This comes amid the rising tension between India and Pakistan after the Pahalgam terror attack. Pakistani troops continued ceasefire violations along the Line of Control for the 12th consecutive night with its unprovoked firing in Kupwara, Baramulla, Poonch, Rajauri, Mendhar, Naushera, Sunderbani, and Akhnoor in areas of Jammu and Kashmir, and the Indian Army responded in a calibrated and proportionate manner. Firing between the two sides comes amid heightened tensions following the April 22 terror attack in Pahalgam in which 26 people, mostly tourists, were killed.

Since the night of April 24, just hours after India suspended the Indus Waters Treaty following the killing of 26 people in the terror attack, Pakistani troops have been resorting to unprovoked firing at various places along the LoC in J&K, beginning from the Kashmir Valley. On April 24, Pakistan blocked its airspace for Indian airlines, closed the Wagah border crossing, suspended all trade with India, and stated that any attempt to divert water meant for Pakistan under the Indus Waters Treaty would be considered an "act of war."

India and Pakistan had agreed to a renewed ceasefire along the borders in Jammu and Kashmir in February 2021.

The situation has changed significantly since February 2021, when the DGMOs of India and Pakistan reiterated their commitment to the 2003 ceasefire agreement to ensure peace along the de facto border.

TCS Pays Full Quarterly Variable Allowance To Over 70% Of Employees

TCS (Tata Consultancy Services) reported a 1.7% decline in the March quarter net profit to Rs 12,224 crore, driven largely by a margin contraction.

New Delhi. Tata Consultancy Services has paid out 100 per cent of the Quarterly Variable Allowance (QVA) to more than 70 per cent of its workforce for the January - March quarter. The company clarified that for employees in other grades, the QVA payout is determined by the performance of their respective business units, which is consistent with TCS's established policy across quarters.

"We have paid out 100 per cent QVA to over 70 per cent of the company. For all other grades, the QVA depends on their unit's business performance. This is in line with our standard practice across quarters," TCS said in a statement. TCS (Tata Consultancy Services) reported a 1.7 per cent decline in the March quarter net profit to Rs 12,224 crore, driven largely by a margin contraction.

It logged a total revenue of Rs 64,479 crore in Q4 FY25, up 5.3 per cent over the year-ago period.

The company added 625 employees in the quarter, bringing its total workforce to over 6 lakh.

While announcing its Q4 and FY25 earnings last month, TCS had said that it would be deferring annual wage hikes to its 6.07 lakh employees due to the business uncertainties triggered by the tariff issues. The company's chief human resources officer Milind Lakkad cited business uncertainties for the delay in annual wage hikes, which generally set in from April. He, however, did not give a timeline for when the company will announce the hikes.

Supreme Court makes its judges' assets public: FDs, PPF, houses, stocks and more

The move comes in the wake of growing concerns over opacity in the judiciary, especially after a controversy surrounding the alleged discovery of burnt wads of cash at the residence of Delhi High Court judge Yashwant Varma following a fire incident.

New Delhi. In a significant move to boost transparency, the Supreme Court has begun uploading the asset declarations of its sitting judges on the court's official website. The asset details of 21 out of its 33 sitting judges are already on its official website, including information on real estate, movable property, gold, shares, and investments held by the judges, their spouses, and joint family members.

The disclosure also includes the assets of all five judges currently in the Collegium. In a press statement, the top court said that the remaining judges' asset details will be uploaded soon. This follows a full-court resolution passed on April 1 to place such information in the public domain. This will also apply to future judges.

The move comes in the wake of growing concerns over opacity in the judiciary, especially after a controversy surrounding the alleged discovery of burnt wads of cash at the residence of Delhi High Court judge Yashwant Varma following a fire incident. This marks a significant shift from previous practice, where asset declarations were mandatory only to the Chief Justice of India (CJI) but optional for public disclosure.

Additionally, the top court has also placed the complete process of appointments to the High Courts and the Supreme Court, including the role assigned to the High Court Collegium, the role of and inputs received from the state governments, central governments, consideration by the Supreme Court Collegium, and data on appointments made between November 2022 and May 2025 on its website for the knowledge and awareness of the public.

Keep cash, torch, medical kits handy: What today's security drill will focus on

New Delhi. Amid rising tensions with Pakistan following the Pahalgam terror attack, the Home Ministry has directed all states to conduct mock security drills on Wednesday focusing on preparedness for various emergency scenarios. A review meeting held in the Ministry of Home Affairs assessed the condition of civil defence installations across 244 districts—such as shelters, warning systems, and coordination facilities—are in working condition or require repairs. Training for civilians will be a key component of the drills.

According to a Home Ministry statement, the drills will focus on how to respond to air raid sirens and blackout situations. Sources said citizens will be instructed to keep medical kits with extra supplies, torches, and candles at home.

As per sources, people will be advised to keep cash handy to navigate situations where mobile devices and digital transactions may fail. The home ministry cited "new and complex threats" as the reason for these comprehensive exercises. Over 100 locations out of the 244 reviewed have been flagged as especially sensitive.

The mock drills will encompass several crucial measures, including the activating of air-raid warning sirens, training civilians on civil-defence strategies to ensure their safety during a "hostile attack," and the cleaning of existing bunkers and trenches. Other measures outlined in a letter to the chief secretaries of all states and administrators of Union territories include provisions for crash-blackout procedures, the early camouflaging of critical plants and installations, and the updating and rehearsal of evacuation plans. The drills will also involve testing the functionality of hotline and radio-communication links with the Indian Air Force (IAF) and assessing the readiness of control rooms and shadow control rooms.

Single complaint number for all waterlogging grievances, says Parvesh Verma

The initiative is aimed at resolving common issues such as waterlogging, broken roads, choked drains, and overflowing sewers more efficiently during the rainy season.

NEW DELHI. In an effort to improve citizen services ahead of the monsoon, the Delhi government will soon launch a unified helpline number '311' to register civic complaints related to departments such as the NDMC, MCD, DDA, PWD, Jal Board, and Flood Control.

Announcing the initiative during a visit to the NDMC Control and Command Centre, Public Works Department Minister Parvesh Singh Verma said the helpline will ensure citizens don't have to approach multiple departments for redressal. "Our vision is 'One Delhi, One Number'.

Citizens only have to call 311, and their complaints will be forwarded to the right department," he said.

The initiative is aimed at resolving common issues such as waterlogging, broken roads, choked drains, and overflowing sewers more efficiently during the rainy season. A joint meeting of all concerned departments will be held within the next few days to finalise the operational structure of the Command Centre, as well as the deployment of officials and technical coordination. The minister also announced that CCTV cameras would be installed in waterlogging-prone areas to enable real-time monitoring.

"With live monitoring and CCTV surveillance, our teams will be able to respond swiftly," Verma said, underlining the role of technology in managing monsoon challenges.

The NDMC Control and Command Centre will serve as the central hub for civic grievance management, operating 24x7 during the monsoon.

Monitoring officers from each department will be stationed at the facility to ensure coordinated and timely responses.

Additionally, all pumping stations across the city will be upgraded with automated systems to enhance drainage efficiency and assist field teams with real-time support.

"This entire arrangement is meant to reduce public inconvenience. The idea is not just to take complaints but to resolve them quickly and," Verma said.

Officials said every complaint received via 311 would be logged into a central system and linked to a responsible officer, promoting transparency and accountability.

NEWS BOX

Defiant Harvard slams 'illegal overreach' as Trump freezes research grants

world. As the Donald Trump administration froze billions of dollars in future federal grants to Harvard University, the Ivy League institution hunkered down, saying it would continue to oppose "illegal government overreach" aimed at stifling research.In a sharp clap back at Trump's latest action, Harvard blasted the administration for withholding funding for "life-saving research and innovation", adding that stopping federal grants would impose "unprecedented and improper control".Harvard, the wealthiest university in the US, said it would have "chilling implications" for higher education.Today's letter makes new threats to illegally withhold funding for lifesaving research and innovation in retaliation against Harvard for filing its lawsuit on April 21," the university said.e of the top-ranked universities in the world, filed a lawsuit after the Trump administration froze more than $2.2 billion in grants.The latest development intensifies the clash between Trump and Harvard over academic freedom, and combating campus antisemitism.

"Harvard will continue to comply with the law, promote and encourage respect for viewpoint diversity, and combat antisemitism in our community," it said."Harvard will also continue to defend against illegal government overreach aimed at stifling research and innovation that make Americans safer and more secure," the statement further said.On Monday, a letter sent to Harvard president Alan Garber by the Education Secretary accused the university of consistent "violations of its legal duties" and stated that it would no longer be eligible for future research grants.

Who Is Balvinder Singh Sahni, Indian-Origin Billionaire Jailed In Dubai For Money Laundering

Dubai. Dubai-based Indian businessman Balvinder Singh Sahni will be jailed and deported from the United Arab Emirates (UAE) for financial crimes, including money laundering. Also known as Abu Sabah, the billionaire received a five-year prison sentence and a Dh500,000 (Rs 1,14,89,750) fine. A Dubai court also ordered the confiscation of Dh150 million (Rs 3,446 million) from the businessman before he is deported from the country. A well-known name in Dubai's elite circles, Sahni has been convicted of laundering Dh150 million through a network of shell companies and forged invoices, according to a report by Gulf News. The businessman was convicted along with 33 others, including his son, reported Khaleej Times.

Who Is Balvinder Singh Sahni The 53-year-old businessman is the founder and chairman of the Raj Sahni Group (RSG) property development firm, which operates in the UAE, the US, India, and other countries. Per media reports, his company's Dubai property portfolio includes the Qasr Sabah's residential buildings in Dubai Sports City, a 24-storey Burj Sabah apartment complex in Jumeirah Village Circle, commercial property in Bay Square, Business Bay and a five-star hotel called Sabah Dubai, among others. A well-connected name in Dubai's elite circle. Sahni is known to be a luxury car collector and often posts his expensive vehicles on social media. He made headlines in 2016 after he purchased car number plate D5 for Dh33 million (about $9 million at the time) for one of his Rolls-Royce cars.

US Offers $1,000 And Pay For Travel To Migrants Who Self-Deport

Washington. The Trump administration said Monday it will pay for the travel and give $1,000 to undocumented migrants who "self-deport" back to their home country."If you are here illegally, self-deportation is the best, safest and most cost-effective way to leave the United States to avoid arrest," Homeland Security Secretary Kristi Noem said.The Department of Homeland Security (DHS) "is now offering illegal aliens financial travel assistance and a stipend to return to their home country through the CBP Home App," Noem said in a statement.

DHS said the stipend of $1,000 will be paid after a person's return to their home country has been confirmed through the app.

"Self-deportation is a dignified way to leave the US and will allow illegal aliens to avoid being encountered by

US Immigration and Customs Enforcement (ICE)," the department said in the statement.

DHS said that even with the payment of travel assistance and the stipend "it is projected that the use of CBP Home will decrease the costs of a deportation by around 70 percent."t said that the average cost currently to arrest, detain, and remove an undocumented migrant is $17,121.

DHS said an undocumented migrant from Honduras had already taken advantage of the program to return home.US President Donald Trump pledged during his White House campaign to deport millions of undocumented migrants.

Filipino 'Asian Francis' emerges as top contender for next Pope

Vatican City Filipino Cardinal Luis Antonio Tagle is sometimes called the "Asian Francis" because of his infectious smile, easy laugh, and spontaneity with words.Like the late Argentine pope, he hails from a country far from the Catholic Church's traditional power base of Europe and came to Rome with an outsider's view.Some who have put Tagle on unofficial short lists for the next pope say he would be a shoo-in to succeed Francis if cardinal electors who enter the secret conclave on Wednesday are looking for as close a similarity as possible in order to assertively continue Francis' progressive streak.If Tagle were elected, it would also likely signal to the world's 1.4 billion Catholics that the cardinals want to go forward with Francis' vision of generally opening up the Church to the modern world by not choosing a man who might roll back some of the late pope's reforms.It would also mean his fellow cardinals had shrugged off question marks over his management abilities."He would represent a continuity of what Pope Francis has been doing," said Rev. Emmanuel Alfonso, a former student of Tagle's who has known him for decades. "He's really like Pope Francis in terms of his love for the poor, his approachability and so on."Tagle, the former archbishop of Manila, would be the first pope from what is now considered Asia, although in the early Church some popes hailed from what is now called the Middle East, technically part of Asia.Tagle, who looks younger than his 67 years and likes to be called by his diminutive nickname "Chito", has headed the Vatican's Dicastery for Evangelization, effectively the Church's missionary arm, for the past five years. That position gave him enormous influence over national churches in developing countries.As archbishop of Manila, and before as bishop of the Philippine city of Imus, Tagle gained pastoral experience in running dioceses in Asia's largest Catholic country. By bringing him to the Vatican in 2020, Francis gave him one more notch in experiences seen as helpful to papal candidates.Tagle's move to Rome brought criticism from then-Philippine President Rodrigo Duterte, who oversaw a bloody "war on drugs" that killed thousands of Filipinos during his 2016-2022 administration.Duterte said Tagle had been removed from Manila for meddling in national politics.

The Philippine Catholic bishops' conference denied those accusations forcefully. Bishop Pablo Virgilio David of Kalookan, a conference official made a cardinal in 2024,

called Duterte's claim "unbelievably ludicrous".Many cardinals already know Tagle personally, and many may see an attraction in having a pope from Asia, viewed by Church leaders as an important region of growth for the faith. Young people feel comfortable with him.When Tagle hosted Francis for a visit to the Philippines in 2014, the visit drew the largest crowds in the history of papal travel, including a Mass that attracted up to 7 million people.

DOCTRINAL BACKGROUND

Tagle, who speaks Italian, English, and Spanish as well as his native Tagalog, now has five years of experience with the Vatican's arcane bureaucracy, although some cardinals may think even that is not enough to run the global Church.One possible weakness in Tagle's candidacy is that he was involved in a management scandal three years ago.In 2022, Francis removed him from a second job as titular head of a Vatican-based confederation of 162 Catholic relief, development and social services organisations working in more than 200 countries.Francis fired the entire leadership of the group, called Caritas Internationalis, following allegations of bullying by top management.Tagle's role, akin to a chancellor of the organisation, was mostly symbolic and ceremonial. He was not directly involved in day-to-day running and was generally admired by staffers.

Unlike Francis, Tagle enjoys a global reputation as a theologian, which could help him gain votes from moderate cardinals concerned by some of Francis' off the cuff utterances, which led to what some called confusion about Church teachings.

Crocodile attacks zoo visitor who entered enclosure for selfie in the Philippines

world. A 29-year-old male was severely injured after being attacked by a crocodile at a zoo in the Philippines. The attack happened on April 28 at the Kabug Island Mangrove and Wetlands Park in Zamboanga Sibugay province when the man entered the reptile's enclosure to take pictures, allegedly believing that the animal was a prop.According to police, the visitor climbed over a chain-link fence carrying his phone and walked toward the crocodile, unaware of danger. "He thought the crocodile was merely a plastic replica," said Police Staff Sergeant Joel Sajolga. Moments later, the crocodile attacked and bit his arm.

Video of the attack taken by bystanders showed the female crocodile, named Lalay, grabbing the man's arm and dragging him into shallow water. Screams can be heard as the crocodile

started performing a "death roll", a deadly spinning action employed by crocodiles to tear apart prey.Despite the chaos, the man remained conscious and sat in the water until help arrived. The zookeeper, who had earlier warned him not to enter the enclosure, rushed in and used a concrete object to strike the animal, forcing it to release the victim.As reported by People, emergency responders arrived quickly following the rescue. The man was bitten deeply by the arm and leg and was rushed to Dr. George T. Hofer Memorial Hospital, where he received more than 50 stitches, according to reports. He is said to be mentally challenged, according to reports.Public Asked to Avoid Animal Enclosures

"This kind of behavior is extremely dangerous," Sgt. Sajolga told local media. "He risked not only his own life but potentially others as well. He's very fortunate to be alive."Police confirmed an investigation is underway. Zoo officials are also reassessing safety protocols to prevent similar incidents.

Debt-ridden Pak tests missile, ignoring Moody's warning: Can its economy withstand

world. On April 22, 26 tourists were killed in one of the worst attacks on civilians in India in nearly 20 years. India blamed Pakistan for the violence, but Pakistan denied involvement. However, Islamabad claimed it had intelligence suggesting that India was planning a military strike.In response to the growing tensions, Pakistan launched a surface-to-surface missile named "Fatah" with a range of 120 kilometres. On Saturday, Pakistan tested Abdali missile, which has a longer range of 450 kilometres. The Pakistani army said the missile test was successful.Prime Minister Shehbaz Sharif praised the launch and said, "This successful test makes it clear that Pakistan's defence is in strong hands."Diplomatic relations between the nuclear-armed neighbours are at a boil following an attack targeting Hindu tourists in Kashmir, killing 26 on April 22.

MOODY WARNS OF ECONOMIC SETBACK

The military level strain is increasing between the two neighbouring countries. Concerns regarding Pakistan's economy are also on the rise. The international credit rating agency Moody cautioned that ongoing conflict would damage the country's economic recovery.

Pakistan only recently began to stabilise its economy after the International Monetary Fund (IMF) provided it with a $7 billion loan package last year.

In its report, Moody's said, "Sustained escalation in tensions with India would likely weigh on Pakistan's growth and hamper the government's ongoing fiscal consolidation, setting back Pakistan's progress in achieving macroeconomic stability."The agency further stated that if the standoff persists, it would harm Pakistan's access to foreign funds and strain its foreign currency reserves. This would potentially make it more difficult for Pakistan to meet its international debt obligations.Meanwhile, India's economy is expected to remain unaffected since it has limited financial ties with Pakistan. However, Moody's added that a rise in defence expenditure could slow down India's efforts to manage its own budget.Iran's foreign minister, who offered to help both countries ease tensions, arrived in Pakistan for meetings with top leaders. He is expected to visit India later this week.India has accused its neighbour of supporting Islamist separatists battling security forces in its part of the region.

Why Hamas Is Executing Palestinians Amid Food Crisis Under Israeli Blockade

Cairo. At least six Palestinians were executed by Hamas in Gaza, and 13 others were shot in the legs for allegedly looting food stores and community kitchens, the Palestinian group said in a statement, as desperation grows in the enclave under a complete Israeli blockade that has now entered its third month."A warning has been issued - those who ignore it bear full responsibility," Hamas said in the statement.Over the last week, there have been reports of armed gangs looting some of the remaining food supplies in Gaza City, challenging Hamas' control of the territory. The Palestinian group has accused some of these "criminal gangs" of working in collaboration with Israel.

"A warning has been issued - those who ignore it bear full responsibility," Hamas said in the statement.Ismail Al-Thawabta, director of Gaza's Hamas-run government media office, said some of the looters acted under a clan umbrella and others acted as organised groups, some of which he said received direct support from Israel.He said a number of "revolutionary execution rulings" had been carried out against "several top criminals" proven to have been involved in looting.In one incident, the Hamas-run interior ministry said a police officer was killed and others were wounded when an Israeli drone fired a missile at a police unit chasing criminals in Gaza City.

"We will strike with an iron fist all these renegades, and we will take the

necessary measures to deter them, no matter the cost, and we will not allow them to continue terrorizing citizens, threatening their lives, and stealing their property," the ministry said in a statement on Saturday, referring to the alleged looters.Israel has, meanwhile, not commented on the allegation.

Hamas Imposes Curfew In Gaza

According to a Reuters report, Hamas' armed wing has started imposing curfews starting at 9 pm (local time) to restrict the movement of civilians and to chase criminals.ome of the Gazans supported Hamas' actions, saying the looting gangs have terrorised locals and are aiding the Israeli government in "starving" them. "Those gangs, some of them armed, have terrorised people, not only stealing food, but stopping some people on the roads and taking away their money and phones," Ahmed, a resident of Gaza City, told Reuters."They aid the occupation in starving us; they must be dealt with as collaborators," he added.SAFA news agency, close to Hamas, said the interior ministry has formed a new 5,000-member force tasked with confronting looters and armed gangs. However, local police forces have been hampered by attacks from Israeli drones against any armed Palestinians they identify.Hamas deployed thousands of police and security forces across Gaza after a ceasefire took effect in January, but its armed presence shrank sharply since Israel resumed large-scale attacks in March.

Humanitarian Crisis In Gaza

United Nations officials have warned of the increasingly dire humanitarian situation facing Gaza, which has been devastated by the Israeli campaign launched following the Hamas-led attack on Israel on October 7, 2023.

Dear Harvard...': Linda McMahon bars university research grants in scathing letter

- The Trump administration barred Harvard from new federal research grants. In a scathing letter, Education Secretary Linda McMahon cited "disastrous mismanagement" and accused the university of betraying academic ideals and legal obligations.

world. The Trump administration on Monday barred Harvard University from receiving any new federal research grants. Education Secretary Linda McMahon conveyed in a sharply worded letter to the president of Harvard, Alan M. Garber. This is the Trump administration's most pointed action against one of the nation's most prestigious academic institutions."This letter is to inform you that Harvard should no longer seek grants from the federal government, since none will be provided," McMahon wrote to Harvard President Alan M. Garber. She accused the university of "disastrous mismanagement" and stated the institution had abandoned core academic values.This move comes as Harvard challenges the federal government in court over the suspension of billions in funding, after refusing to comply with demands McMahon called essential for accountability."Harvard University has made a mockery of this country's higher education system. It has invited foreign students, who engage in violent behaviour and slur contempt for the United States of America, to its campus. In every way, Harvard has failed to abide by its legal obligations, its ethical and fiduciary duties, its transparency responsibilities, and any semblance of academic rigour. It had scrapped standardised testing requirements and a normalised grading system," she wrote.She alleged Harvard of embroiling in humiliating plagiarism scandals. "Harvard has even been embroiled in humiliating plagiarism scandals, exposed clearly and plainly in the media, with respect to your then University President, who was an embarrassment to our Nation. Much of Harvard's hateful discrimination was revealed, last year, by the great work of

Congresswoman Elise Stefanik, and her Committee. As if it were trying to embarrass itself even further. Harvard hired failed Mayors Bell De Blasio and Lori Lightfoot, perhaps the worst mayors ever to preside over major cities in our country's history, to supposedly teach "leadership" at their School of Public Health. This is like hiring the captain of the Titanic te teach navigation to future captains of the sea," she added.The move by the administration seems to mark a change in its tack in regulating elite institutions. Previous attempts at recalling research grants had been met with legal challenges, including Harvard, which relied on both the First Amendment and the Administrative Procedure Act in filing its lawsuit. Now, by aiming at upcoming grants, the administration might be trying a different strategy—one that could prove harder to challenge in court.In her three-page letter, McMahon wrote, "At its best, a university should fulfill the highest ideals of our nation, and enlighten the thousands of hopeful students who walk through its magnificent gates, but Harvard has betrayed its ideal."

HARVARD RESPONDS: UNPRECEDENTED AND IMPROPER CONTROL

Harvard was quick to respond. In a statement released Monday night, the university accused the Trump administration of doubling down on political interference.

NEWS BOX

Shubman Gill not affected by weight of captaincy: Gujarat Titans director Solanki

New Delhi. Shubman Gill has been one of those cricketers who have thrived under the burden of responsibility that comes with leading a side," Gujarat Titans' Director of Cricket, Vikram Solanki, said. In his second year as captain of the 2022 champions, Gill has appeared comfortable in IPL 2025, both with the bat and in his tactical decisions on the field.The Gujarat Titans currently occupy fourth spot with 14 points from just 10 games and are well-placed to reach the playoffs for the first time since 2023. Gill appeared somewhat flustered during his maiden stint as captain of the Titans, but with a more well-rounded attack this season, the young star has looked at ease, navigating the pressures of a high-profile tournament such as the IPL."As far as leadership is concerned, he has really grown into the role of captaincy," Solanki said while addressing a press conference on the eve of their IPL 2025 match against the Mumbai Indians in Mumbai."When you have somebody as gifted, as talented, as exceptional as Shubman is as a batsman, sometimes you might have concerns about whether the weight of leadership would bear heavily. I don't think that's been the case. You sometimes see that people thrive in such responsibility roles, and Shubman has

certainly been that," he added.

Gill, who clinched the Orange Cap in 2023 with 890 runs, managed just 426 runs in 12 matches last season. However, in IPL 2025, Gill has already amassed 465 runs in 10 matches at a strike rate of 162 - his best in the IPL so far.

WHAT MAKES GILL-SAI JODI A HIT

Gill and Sai Sudharsan have forged a sensational opening combination, setting the stage alight at the top of the order. The pair has added 628 runs - the most for any partnership this season, a remarkable 173 runs more than their nearest rivals, Virat Kohli and Devdutt Padikkal.When asked about the secret behind Gill and Sudharsan's success at the top, Solanki said: "You can only credit them and their success, credit their partnership, to their hard work."There is the nuance that they are similar in terms of how they approach the game. They are fairly traditional in how they set themselves up. At their core, they have a solid technique and an understanding and appreciation for facing the new ball, where there can be some movement.

MI vs GT, IPL 2025 Preview: Predicted XI, team news and Mumbai pitch conditions

New Delhi. Mumbai Indians (MI) will aim to continue their winning juggernaut as they take on Gujarat Titans (GT) in Match 56 of the Indian Premier League 2025 (IPL 2025) on Tuesday, May 6 at Wankhede Stadium, Mumbai. The Hardik Pandya-led side is coming into the fixture on the back of a dominant 100-run victory over the Rajasthan Royals (RR).MI have made a remarkable turnaround after winning just one out of their first five fixtures and are on a six-match winning streak. The five-time champions have only achieved the feat twice in their golden history and are once again looking like the team to beat in the ongoing season after having got most of their things together.The top order is finally firing for MI

with Rohit Sharma and Ryan Rickelton getting the team off to fiery starts while the bowling attack led by the formidable new-ball pair of Jasprit Bumrah and Trent Boult. Hence, MI have found their groove and are going to be hard to stop going ahead in the season.On the other hand, Gujarat are coming into the fixture after beating Sunrisers Hyderabad (SRH) by 38 runs. The Shubman Gill-led side has been at the top of their game as they currently sit on the fourth spot on the points table with seven victories from ten matches.

Gujarat's top order, consisting of Shubman Gill, Sai Sudhsarsan and Jos Buttler, has been firing all cylinders and has proved to be a major headache for the opposition. Apart from that, the bowling attack led by Prasidh Krishna and Mohammed Siraj has been the reason behind the downfalls of several batting lineups. R Sai Kishore has also done a fabulous job of stemming the run flow in the middle overs.Hence, the upcoming fixture is expected to be a mouth-watering clash with both teams at the top of their game. The winner of the match will climb to the top of the points table, and both teams will look to bring their A game to the fore to further strengthen their playoffs chances.

IPL 2025: Coach Vettori blames lack of consistency for SRH's early elimination

- Sunrisers Hyderabad were eliminated from the play-offs race
- Daniel Vettori blamed lack of consistency from his side in IPL 2025
- SRH will now look to salvage pride and test their bench strength

New Delhi. Sunrisers Hyderabad head coach Daniel Vettori lamented his team's lack of consistency, which he believes was the key factor behind their disappointing campaign in IPL 2025. After finishing as runners-up last season, SRH failed to replicate their form and cohesion, ultimately crashing out of playoff contention on Monday following a rain-abandoned match against Delhi Capitals.SRH had a must-win game on their hands and appeared to be in control after a strong bowling performance restricted DC to 133/7. Led by Pat Cummins, the Sunrisers' pace attack dismantled the Delhi top order and looked poised to chase down the target. However, relentless rain after the first innings meant the match could not resume, and both teams were forced to share a point.

"Obviously, it's disappointing," Vettori said at the post-match press conference. "We came in with high hopes, but we haven't been consistent enough with our performances. We've spoken about not being able to put together a complete game, and today was shaping up to be one. It's frustrating we couldn't finish it, but that's the nature of cricket."With the abandonment, SRH remained on just seven points from eleven matches, effectively ending their playoff hopes. In contrast, Delhi Capitals moved to 13 points and stayed in the race for a top-four finish.It has been a season to forget for SRH, who were expected to be strong contenders following their explosive batting displays in 2024. But this year, the team struggled to replicate that form, suffering from frequent batting collapses and inconsistent execution with both bat and ball.Vettori acknowledged that the team must learn from the experience. "We've got to accept where we are. We've had moments where we've shown our potential, but we haven't backed it up game after game," he said.

With three matches still to play, SRH will now look to salvage pride and test their bench strength. The focus will likely shift to preparing for next season, with an eye on building a more balanced and dependable squad.

Liverpool fans burn Alexander-Arnold's jersey after defender announces departure

- Harry Kane finally breaks his title drought as Bayern Munich secure the Bundesliga championship. Freiburg's draw with Leverkusen ensured Bayern's triumph, highlighting the competitive nature of the league.

Liverpool Liverpool fans expressed anger after right-back Trent Alexander-Arnold officially announced his decision to leave the club at the end of the 2024–25 season. The England international, who joined the Reds at the age of six, revealed his departure via a heartfelt message on social media, calling it the "hardest decision" of his life.The 26-year-old England defender has opted not to renew his contract and is expected to join Spanish giants Real Madrid on a free transfer, with reports suggesting a six-year deal is already in place. Alexander-Arnold, who has made 352 appearances and won eight major trophies with Liverpool, including two Premier League titles and a Champions League crown, cited the desire for a new challenge and personal growth as his reasons for leaving."This club has been my whole life – my whole world - for 20 years," Alexander-Arnold said in his statement. "From the Academy right through until now, the support and love I have felt from everyone inside and outside of the club will stay with me forever. I will forever be in debt to you all."But, I have never known anything else and this decision is about experiencing a new challenge, taking myself out of my comfort zone and pushing myself both professionally and personally."However, the announcement has sparked mixed reactions among the Anfield faithful. While many have expressed gratitude and well-wishes, a section of the fan base responded with anger. In a video shared by betting platform Midnite on social media platform X, one supporter was seen burning an Alexander-Arnold jersey in protest. The number 66 shirt, emblazoned with the defender's name, was engulfed in flames, reflecting the emotional weight of the news.Liverpool responded with an official statement, acknowledging his contribution and wishing him the best: "Alexander-Arnold will depart with our gratitude and appreciation for his contribution during a sustained period of success," the club said in a statement.

The news comes with Liverpool still having three matches left in their campaign, and Alexander-Arnold hopes his decision won't overshadow the team's achievements. "I just hope the noise doesn't take away from what we've achieved this season," he said.

As he prepares to don the white of Real Madrid, Alexander-Arnold leaves behind a legacy at Anfield that few can match—both as a generational talent and a local lad who lived the Liverpool dream.

Virat Kohli always said I will be next Sachin Tendulkar, reveals school teacher

New Delhi. Star India batter Virat Kohli's school teacher, Vibha Sachdev, has revealed that he had aspirations to be India's next Sachin Tendulkar since his childhood. Virat Kohli is today touted as the best batter across formats and the true successor to Tendulkar. The 36-year-old is currently in the middle of another prolific IPL season, being the highest run scorer of the tournament so far with 505 runs from 11 matches.Recently, Kohli's school teacher opened up about his early days and revealed that he loved participating in all school activities. She also stated that Kohli had made up his mind to be India's next Sachin Tendulkar right from a young age as people took notice of his sheer grit and confidence."His eyes were very expressive. Virat was an active participant in all the school activities, he was an enthusiastic and eager participant of all the interhouse activities. 'Ma'am, I will be the next Sachin Tendulkar of Indian Team' was the oft repeated

quote, yes at that time sometimes it made us smile at the sheer grit and confidence of the wide eyed boy," Vibha Sachdev told Cricadium.Furthermore, Vibha Sachdev also revealed that Kohli worked really hard to excel in both sports and academics. However, his studies took a backseat while he had to practice.

"Virat always scored well in his exams. He was an above-average performer, and the only time he would lose a few marks was when his practices took his time away. 'I prepared for my exam late after I came back from my practices', Was something that we used to hear very frequently from him. He worked very hard to excel in both sports and academics, and the teachers at Vishal Bharti Public School, Paschim Vihar fully understood his struggle and cooperated with him by giving him added guidance," he added.Meanwhile, Kohli is playing for Royal Challengers Bengaluru (RCB) in the ongoing IPL, and the Rajat Patidar-led side is having a golden run, being at the top of the points table so far. RCB are comfortably sitting at the top with eight wins from 11 matches, having 16 points to their name. They will be eager to continue their winning run against Lucknow Super Giants (LSG) on Friday, May 9 in Lucknow.

Shai Hope to lead West Indies squad for ODI series against Ireland and England

New Delhi. West Indies have named a strong 15-member squad for their upcoming six-match ODI tour of Europe, with seasoned wicketkeeper-batter Shai Hope continuing as captain. The Caribbean side will take on Ireland and England in three ODIs each later this month, with the series forming a crucial step in their preparations for the ICC Men's Cricket World Cup 2027.

The squad includes a solid core of experienced batters in Brandon King, Evin Lewis, and Keacy Carty, while 19-year-old Jewel Andrew-a standout performer at the 2024 ICC U-19 Men's Cricket World Cup-has earned a call-up. However, Shimron Hetmyer misses out as he remains engaged in the IPL with Rajasthan Royals.The squad largely resembles the group that registered a 3-0 series sweep over Bangladesh late last year, followed by an impressive home series win against England. Head coach Daren Sammy is optimistic about maintaining momentum as the team works toward building consistency ahead of the next World Cup, which will be hosted jointly by South Africa, Zimbabwe, and Namibia."These matches form a critical component towards the 2027 World Cup and there are signs of the team building consistency following the series sweep against Bangladesh and the win over England late last year," Sammy said.

"We expect the conditions to be challenging but we are creating a culture and mindset which emphasize playing the brand of cricket that is taking us closer to some of our overall objectives."In addition to the squad announcement, Cricket West Indies confirmed changes in the coaching setup. Former fast bowler and 2012 T20 World Cup winner Ravi Rampaul replaces James Franklin as bowling coach.

Put Jasprit Bumrah off his mark: Shane Watson's ultimate challenge for GT

- Shane Watson revealed that the ultimate challenge for the GT batters will be to put Jasprit Bumrah off his mark during their match at the Wankhede stadium on May 6. Bumrah has been in top form with the ball after his return from injury.

New Delhi. Shane Watson feels that putting Jasprit Bumrah off his mark will be the ultimate challenge for the GT batters during their clash against MI. Bumrah, who missed the first few games for Mumbai this season, made a slow start to life in IPL 2025 but has found his groove in the past few games. The India pacer has been more aggressive in his approach this season and has 11 wickets from 7 matches.

GT batters, especially the top three of Shubman Gill, Sai Sudharsan and Jos Buttler, have been the main reason behind their side's success in IPL 2025 and will have the task of going up against Bumrah. Speaking to Star Sports, Watson said that GT's first major challenge will be to score runs off Bumrah as it will be tough to put off the star pacer."It's tough facing Jasprit Bumrah in any format anywhere. He's just that good. And the thing about Jasprit Bumrah, even if he has a bad day, he might not get a wicket, and he goes for around 7 runs an over. That's his really bad day."It is just mind-blowing how incredibly good Jasper Bumrah is. So, look, the Gujarat Titans batters, they're gonna have their work cut out because as a starting point, been able to handle Jasprit Bumrah, find a way to be able to score some runs off him, try to put him off. How you put him off, I've got no idea, to be honest," said Watson.

'Bumrah won't give too many loose balls'

Watson feels that the likes of Gill and Sudharsan will trust their batting and shot-making ability and wait for a loose delivery. However, with Bumrah, the former Aussie all-rounder feels that not a loose balls will be available for the GT batters."But the one thing that you kow with Shubman Gill and also with Sai Sudharsan is they just trust their batting, but they trust their shot-making ability where they know that there's gonna be a loose ball available to them in some way, shape, or form. But when you're up against Bumrah, very rarely does he actually bowl a loose ball, so that's where the challenge is going to be for those two guys in particular. How we're going to find a way to be able to put Jasprit Bumrah off knowing that I have to stand still and react, I'm not really going to get too many loose balls coming my way, so that's going to be the ultimate battle it is for any batter, but especially those world-class batters of GT," he added.

Sidharth Malhotra Joins Pregnant

Kiara Advani

In NYC Ahead Of Her Met Gala Debut

Kiara Advani is all set to make her debut at Met Gala 2025, and fans can't keep calm! The actress, who is expecting her first child, was recently joined by her hubby Sidharth Malhotra in New York City, ahead of her Met Gala debut. Looks like Sidharth has arrived to support his wife during this major moment, and he shared a few glimpses to give his fans a sneak-peek into his day in NYC.Sidharth Malhotra showcased his dedication to fitness by heading to the gym shortly after arriving in NYC. He took to his Instagram stories to share a glimpse through the window, capturing the stunning skyline of New York City. He was seen with a bottle of water in one hand, and he captioned the picture as, "Gym time #hydrate." He also added, "Hello NYC!" Meanwhile, in another picture, he showcased what his 'leg day' looks like.

Met Gala 2025 is scheduled to take place at May 5 at New York City's renowned Metropolitan Museum of Art. Kiara Advani landed in NYC a few days ahead of the fashion event. On May 3, she shared the first picture from New York, giving fans a behind-the-scenes glimpse. The picture showed a table adorned with several colourful items- including a vase of pink roses, as well as a cake in the form of a tiny mannequin wearing a gorgeous black gown and a pearl set. The picture also featured a booklet with the Met steps on the cover, and the label reads, "The MET Gala." The actress will opt for a custom couture by ace fashion designer Gaurav Gupta for Met Gala 2025.

Meanwhile, before heading to NYC, looks like Kiara Advani enjoyed a fun-filled vacation with Sidharth Malhotra in Europe. She shared some lovely pictures from their European vacation. Radiating warmth and a healthy pregnancy glow, the actress gave fans a peek into her peaceful moments – from food to florals and quiet street strolls.In March, Kiara Advani and Sidharth Malhotra announced that they are expecting their first child. They shared a joint post on Instagram that read, "The greatest gift of our lives Coming soon."

Nushrratt Bharuccha

Says Being Replaced In Dream Girl 2 Was 'Unfair': 'Even Male Actors...'

Nushrratt Bharuccha, who starred opposite Ayushmann Khurrana in the 2019 film 'Dream Girl', was not cast in the second instalment. She was replaced by Ananya Panday in the 2023 film Dream Girl 2. Last month, after Nushrratt shared that the decision to not cast her in the sequel was 'not cool', director Raaj Shaandilyaa responded by clarifying that the film was a franchise installment, not a direct sequel. Now, the actress has reacted to the director's remark, saying that she didn't think it was fair to be left out of Dream Girl 2, regardless of whether it was labelled a sequel or a franchise. She explained that similarly, if Luv Ranjan wouldn't have cast her in Pyaar Ka Punchnama 2, she would have felt equally hurt and questioned the decision.

While speaking with Siddharth Kannan, Nushrratt Bharuccha said that while it felt unfair at the time, she has moved on. She talked about her friendship with Raaj Shaandilyaa, and said that they are still very close friends. She admitted that she was hurt back when Dream Girl 2 had released, however, that chapter is over for her now. "I did another film with him. He has come to me with three more offers. We will still work together on something or the other. For me that chapter is over. But if you ask me now, did it or did it not hurt? Yes, it did. Did I feel like it was fair? I don't think it was fair. I don't think anybody can think it is fair. Sequel tha, franchise tha, jo bhi tha. Jis bhi context mein aap film ko daal do."

Nushrratt also addressed the gender bias, calling it 'unfair' that the female actors are often replaced in sequels while male actors are typically retained. She added that even her male co-stars think it is unfair. "I would at least like to say this about the actors I have worked with, even the male actors will think it's unfair. It's not like the heroes are the ones thinking 'Sahi ho raha hai'. They are all actors. We are from the same industry. But for whatever reason, the need of that film is different," she said. She then added that it finally boils down to the decision and choice of the 'makers', and there's no point challenging it.

What Did Raaj Shaandilyaa Say About Replacing Nushrratt Bharuccha In Dream Girl 2?

Last month, director Raaj Shaandilyaa responded to Nushrratt being replaced by Ananya in Dream Girl 2. In an interview with Times of India, he explained that Dream Girl 2 was never designed as a direct sequel but as part of a growing franchise. "If it were a proper sequel, I would've cast Nushrratt," he said. "But since this was more of a franchise film, we decided to bring in a new female lead." Raaj added that the original story arc between Ayushmann and Nushrratt's characters had already reached a natural conclusion.

Sarabhai Vs Sarabhai Film On The Cards? JD Majethia Says 'Could've Been Made Earlier...'

Producer JD Majethia is known for his successful comedy shows such as Khichdi, Sarabhai Vs Sarabhai, among others. He recently made a surprising announcement of the movie Khichdi 3, leaving fans excited. In a recent interview, he was asked whether he also plans to turn Sarabhai Vs Sarabhai into a film series, similar to what he did with Khichdi. JD Majethia replied that there might have been a chance to make a film on Sarabhai Vs Sarabhai earlier, but the opportunity seems to have passed. He said that while there 'should be more' to the series, it's too late to make a film on it now.

While speaking with Hindustan Times, JD Majethia shut down hopes for a Sarabhai Vs Sarabhai film. "Sarabhai Vs Sarabhai ki film nahi banni chahiye. (A film on Sarabhai Vs Sarabhai should not be made). It could have been made earlier but not now. There should be more to that series too, but it's too late to make a film on that. I am not too sure, but we will wait and see," he said.

Meanwhile, in the same interview, he also talked about the level of comedy going downhill. "The overall level of comedy has gone down in our industry. You will find small gags and videos on social media, but the hunger to spend money to go watch something has reduced. You won't find any comedy that can become legendary today, as you used to until a few years earlier, and the reason is we don't have such talented crop of writers and actors for that," he said.Sarabhai Vs Sarabhai, starring an ensemble cast of Satish Shah, Ratna Pathak Shah, Sumeet Raghavan, Rupali Ganguly, and Rajesh Kumar, remains one of the most beloved sitcoms in Indian television history. The first season aired from 2004 to 2006 on television, and has attained cult status thanks to its sharp wit, timeless humour and unforgettable characters. The show returned with a new season, 'Sarabhai Vs Sarabhai: Take 2' in 2017, and it was streamed on Hotstar. The story of the second season was set 11 years after the first season's conclusion.

Babil Khan Returns To Instagram, Ananya Panday Says 'Always In Your Corner'

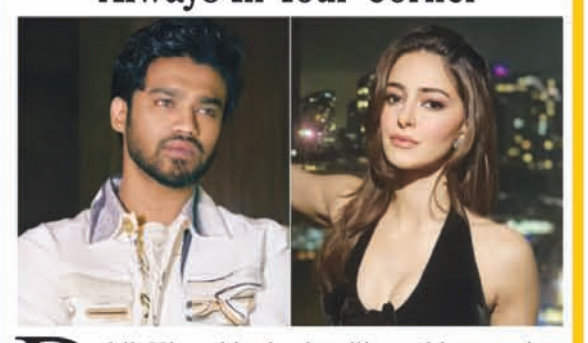

Babil Khan hit the headlines this morning after a video of his emotional breakdown went viral on Reddit. He was seen criticizing Bollywood, and also named Ananya Panday, Siddhant Chaturvedi, Raghav Juyal, Adarsh Gourav, Arjun Kapoor among others. After the video went viral, Babil deactivated his Instagram account. Now, hours later, Babil has made a comeback on Instagram. He clarified that the video was extremely misinterpreted, and that he was only trying to show his support to the actors he named in the video. Ananya Panday reacted to Babil's Instagram story, and expressed her support. Showing solidarity, she mentioned that she is always in his corner.

Ananya Panday Expresses Her Support To Babil

A few hours ago, Kubbra Sait shared Babil's team's official statement on her Instagram, and penned a note urging people to 'be kind'. Upon returning to Instagram, Babil first shared Kubbra's post on his Instagram story, and wrote, "Thank you so much (red heart emoji) The video was extremely misinterpreted. I was trying to show support to Ananya Panday, Shanaya Kapoor, Gourav Adarsh, Arjun Kapoor, Raghav Juyal, Arijit Singh." He further added, "I genuinely don't have the energy to indulge more but I do this as responsibility for my peers that I truly admire." Ananya Panday re-shared Babil's story, and expressed her solidarity by writing, "Only love and good energy for you Babil, always in ur corner."

Babil Showers Love On Siddhant Chaturvedi And Raghav Juyal

Meanwhile, Babil shared another story, in which he shared Raghav Juyal's post and wrote, "Raghav Juyal, bhai you are my icon, my idol, and my elder brother that I never had." In the next story, he showered love on Siddhant Chaturvedi, and wrote, "I love you brother."

Babil's Team's Official Statement

Earlier, Babil's team issued a statement that read, "Over the past few years, Babil Khan has earned immense love and appreciation for his work, as well as for his openness about his mental health journey.

Like anyone else, Babil is allowed to have difficult days — and this was one of them. We want to reassure all his well-wishers that he is safe and will be feeling better soon. That said, a video of Babil has been widely misinterpreted and taken out of context."